राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 36

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, मंगलवार, 16 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

तस्मै श्री गुरुवे नमः

सरोकार

राजस्थान में जल संरक्षण से विकास का 'चौका'

जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर से 90 किलोमीटर दूर स्थित लापोड़या गांव जल

संरक्षण की चौका विधि के लिए दुनियाभर में विख्यात है। जब पूरा राजस्थान सूखे की मार झेल रहा होता है, इस गांव में हरियाली होती है। जल संरक्षण के जरिये गांव समृद्धि की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। (पेज-13)

जागरण विशेष

रुपहले पर्दे पर दिखेगा शूटर दादियों का संघर्ष

बागपत : जीवन के सात दशक पार करने के बाद पिस्तौल उठाकर पदकों की झड़ी

लगाने वाली शूटर दादियों की बायोपिक बनकर तैयार है। फिल्म 'सांड़ की आंख' के जरिए दुनिया चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर के संघर्ष को जानेगी। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

एनआइए कानून का दुरुपयोग नहीं होने देगी सरकार : शाह

नई दिल्ली : आतंकी हमलों की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को और अधिकार देने वाले बिल पर लोकसभा ने मुहर लगा दी है। एनआइए को साइबर क्राइम, मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच का भी हक मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एनआइए के दुरुपयोग की विपक्ष की आशंकाओं को बेबुनियाद बताया है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

हिमाचल में 24 घंटे में पूरा हुआ बचाव अभियान, 14 की मौत

सोलन : हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित कुमारहट्टी के पास चार मंजिला इमारत गिरने से दबे लोगों को बचाने का अभियान 24 घंटे बाद पूरा हो गया है। हादसे में मलबे में दबे 42 लोगों में से 14 की मौत हो गई, जबकि 28 को सकुशल निकाल लिया गया। मृतकों में में असम राइफल्स के 13 जवान शामिल है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

बीमा लेने का फैसला किसानों पर छोड़ने की तैयारी

नई दिल्ली : केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सदस्यता लेने का फैसला पूरी तरह से किसानों पर ही छोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए योजना में बदलाव पर विचार हो रहा है। इनमें सभी किसानों के लिए फसल बीमा को वैकल्पिक बनाना शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

हाफिज सईद को पाकिस्तानी अदालत ने दी अग्रिम जमानत

लाहौर: मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन साथियों को पाकिस्तान की एक आतंक रोधी अदालत से सोमवार को अग्रिम जमानत मिल गई। अदालत ने मदरसे के लिए जमीन के अवैध उपयोग के मामले में चारों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर 31 अगस्त तक अंतरिम जमानत प्रदान की है।

कोलेजियम प्रणाली पर संसद में उठे सवाल

वेंकैया बोले ▶ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के अधिकारों पर चर्चा की जरूरत

सभी दलों के सांसदों ने एक सुर में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर दिया जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली में सोमवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत करते सदन के सभापति एम. वेंकैया नायडू (टीवी ग्रैब)। एएनआइ

शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता पर सोमवार को संसद में सवाल उठे और इसमें बदलाव की मांग उठाई गई। लगभग सभी दलों के सांसदों ने एक सुर से सिविल सेवा की तर्ज पर निचली अदालतों में केंद्रीय न्यायिक सेवा के जरिये जजों की नियुक्ति की मांग का समर्थन किया। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने इस मांग के प्रति सांसदों की गंभीरता को देखते हुए सदन में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों और उनकी सीमाओं पर चर्चा की जरूरत बताई।

राज्यसभा में शून्यकाल में भाजपा सदस्य अशोक वाजपेयी ने कोलेजियम व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, इसमें जातिवाद, परिवारवाद से लेकर पेशेवर निकटता जैसे पहलुओं का बोलबाला रहता है। इसकी वजह से सामान्य परिवार से कानून के क्षेत्र में आए लोगों के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जज बनना बेहद मुश्किल है। वक्त की जरूरत है कि शीर्ष न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। संविधान में कोलेजियम प्रणाली का कोई प्रावधान नहीं है इसीलिए इस व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा,हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं की जा रही हैं। वाजपेयी ने सुझाव दिया कि सिविल सेवा की तरह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय न्यायिक सेवा के जरिये नियुक्तियां की जाएं ताकि सामान्य परिवारों के लोग भी शीर्ष न्यायपालिका में जा सकें। उनकी मांग से राजद के मनोज कुमार झा, सपा के राम गोपाल यादव समेत पक्ष-विपक्ष के अधिकांश सांसदों ने सहमति जताते हुए खुद को संबद्ध किया। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा,यह बेहद अहम मसला है। जिस तरह सदन में सदस्यों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर सहमति दिखाई है, उसे देखते हुए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र और सीमाओं पर सदन में चर्चा की जरूरत है। ज्ञात हो, जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान हो चुकी है। शीर्ष कोर्ट ने संसद में पेश न्यायिक जवाबदेही कानून को निरस्त भी कर किया था।

कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को होगा शक्ति परीक्षण

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में पिछले दिनों से चल रहे सियासी घमासान का पटाक्षेप इस हफ्ते होने की उम्मीद है। कांग्रेस-जदएस गठबंधन सरकार की अगुआई कर रहे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी गुरुवार को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। कांग्रेस और जदएस के 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद उनकी सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। इस बीच, भाजपा ने दावा किया है कि वह अगले चार-पांच दिन में सरकार बना लेगी।

विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार ने सोमवार को कहा, मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवार सुबह ग्यारह बजे सदन में विश्वास मत प्रस्ताव रखेंगे। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्तापक्ष व विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत में विश्वास मत के लिए गुरुवार का दिन तय हुआ। साथ ही उन्होंने भाजपा की मांग पर विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के बाद भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येद्दयुरप्पा ने कहा, उनकी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की बात कही थी। जिसके बाद सरकार द्वारा विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने की तिथि तय हुई। वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्दरमैया ने कहा, सरकार विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने को तैयार है।

16 विधायकों ने सौंपा है इस्तीफा : दरअसल, कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस के तेरह और जदएस के तीन विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, स्पीकर ने अभी उनके इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं किया है। दो निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन वापसी का एलान करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मुंबई में होटल में ठहरे इन विधायकों के विश्वासमत के दौरान मौजूद रहने की संभावना कम ही है।

बागियों को मनाने के तमाम प्रयास विफल : कांग्रेस-जदएस की तरफ से बागी विधायकों को मनाने के प्रयास विफल रहे हैं। कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद और अन्य नेता बागियों को मनाने के लिए उनसे होटल में मिल सकते हैं। लेकिन बागी विधायकों ने मुंबई पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर कांग्रेस के नेताओं से खतरा बता दिया। उन्होंने कहा है कि वो खड़गे, आजाद या कांग्रेस के अन्य किसी भी नेता से मिलना नहीं चाहते।

मतदान से दूर रह सकते हैं मुंबई के होटल में ठहरे बागी विधायक

बागी विधायकों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से बताया खतरा

बेंगलुरु में सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अपने सहयोगियों से कुछ महत्वपूर्ण बात करते कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी। प्रेट्र

येद्दयुरप्पा बोले, पांच दिन में बना लेंगे सरकार : भाजपा नेता येद्दयुरप्पा ने कहा कि उन्हें अगले चार से पांच दिन में राज्य में सरकार बना लेने का भरोसा है। उन्होंने कहा, 'कुमारस्वामी बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। यह बात कुमारस्वामी भी जानते हैं। वह सदन में बढ़िया भाषण देने के बाद पद से इस्तीफा दे देंगे।' बता दें कि पिछले साल चुनाव के बाद येद्दयुरप्पा मुख्यमंत्री बने थे। 224 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 105 सीटें मिली थी। लेकिन वह विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर सके थे और विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। (पेज-3 देखें)

चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण टला

श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश), आइएएनएस : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण आखिरी क्षण में टाल दिया। प्रक्षेपण यान 'बाहुबली' रॉकेट में आई तकनीकी खामी के चलते प्रक्षेपण से मात्र एक घंटे पहले उल्टी गिनती रोक दी गई।

मिशन कंट्रोल सेंटर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा लांच विंडो के तहत अब चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण संभव नहीं है। प्रक्षेपण की अगली तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। लांच विंडो वह समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और उस दौरान दूसरे उपग्रहों से टकराने का खतरा भी कम होता है। इसरो के अधिकारी ने बताया कि तड़के2.51 बजे जीएसएलवी-एमके 3 रॉकेट से चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण की पूरी तैयार कर ली गई थी, लेकिन रॉकेट में तकनीकी खामी का पता चलते ही मिशन कंट्रोल सेंटर ने ब्लास्ट से 56 मिनट 24 सेकेंड पहले तड़के 1.55 मिनट पर प्रक्षेपण टालने की घोषणा की। अधिकारी ने कहा, खामी का पता लगाकर उसे दूर करने में कम से कम 10 दिन का समय लग सकता है, उसके बाद प्रक्षेपण के नए कार्यक्रम के बारे में फैसला किया जा सकेगा। इसरो के दो पूर्व अधिकारियों ने बताया कि रॉकेट के दबाव बनाने वाली प्रणाली में खामी आई होगी। उन्होंने बताया कि ग्रहों के गतिमान रहने के चलते अंतर-ग्रहीय मिशन जटिल होता है।

भारत के लिए अहम मून मिशन : भारत के लिए यह मिशन बहुत अहम है। इस मिशन के सफल होते ही चंद्रमा पर अपना यान उतारने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही चंद्रमा पर अपने यान उतारने में सफल रहे हैं। 4 मीटर लंबे और 640 टन के जीएसएलवी-एमके 3 रॉकेट से 3.8 टन के अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 को छोड़ा जाना था। इस मिशन पर 978 करोड़ रुपये की लागत आई है।

तीन खंडों वाला है चंद्रयान-2 : चंद्रयान-2 के तीन भाग हैं। पहला खंड ऑर्बिटर है जिसका वजन 2,379 किलोग्राम और उस पर आठ पेलोड हैं। दूसरा भाग लैंडर विक्रम है, जिसका वजह 1,471 किलोग्राम और चार पेलोड हैं। तीसरा भाग रोवर प्रज्ञान है, जिसका वजन 27 किलो है और इस पर दो पेलोड हैं। प्रज्ञान को विभिन्न वैज्ञानिक खोज करना है।

तीन स्टेज रॉकेट है 'बाहुबली': चार टन तक के उपग्रह को ले जाने की क्षमता वाला प्रक्षेपण यान 'बाहुबली' ठोस ईंधन द्वारा संचालित होता है। दो स्ट्रैप-ऑन मोटर्स के साथ यह तीन चरण/ इंजन रॉकेट है। इसका दूसरे चरण का इंजन तरल ईंधन बूस्टर है और तीसरा क्रायोजेनिक इंजन है।

कहां उतरता चंद्रयान-2 : चंद्रयान-2 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजा जाना था, जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। यह भाग अत्यधिक ठंडा रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां सीधी नहीं पड़ती।

प्रक्षेपण टालने की सराहना : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व वैज्ञानिक रवि गुप्ता ने कहा कि इस तरह के मिशन में ऐसी तकनीकी खामी आती रहती है। सबसे सराहनीय बात यह है कि वैज्ञानिकों ने बड़ा हादसा होने से पहले इसका पता लगा लिया।

खामियों का पता लगाने के लिए कमेटी का गठन : रॉकेट में आई खामी का पता लगाकर उसे दूर करने के उपाय सुझाने के लिए इसरो ने कमेटी का गठन किया है।

आखिरी वक्त में रॉकेट 'बाहुबली' में तकनीकी खामी का पता चला

मौजूदा लांच विंडो में प्रक्षेपण संभव नहीं, नई तारीख का एलान बाद में

इसरो के रॉकेट जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हीकल-मार्क 3 में आई तकनीकी खामी के चलते चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण टालना पड़ा। प्रेट्र

कोख के कारोबार पर 10 साल तक की कैद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

किराए पर कोख यानी कमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए सरकार ने 'द सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल, 2019' सोमवार को लोक सभा में पेश किया गया। इस विधेयक में कमर्शियल सरोगेसी को गैर-कानूनी ठहराया गया है और इसका उल्लंघन करने पर 10 साल के कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

हाल के वर्षों में भारत सरोगेसी हब केतौर पर उभरा है जिसके चलते सरोगेट माताओं के शोषण की खबरें आ रही हैं। कानून के अभाव के चलते सरोगेसी का अंधाधुंध व्यवसायीकरण हुआ है। डॉक्टर और सरोगेसी क्लीनिक इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। विधि आयोग ने भी अपनी 228वीं रिपोर्ट में कानून बनाकर कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाने की सिफारिश की है।

लोकसभा में पेश सरोगेसी विधेयक में 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान

सिर्फ भारतीय दंपती को ही सरोगेसी से संतान प्राप्त करने की अनुमति

डॉ हर्षवर्धन फाइल फोटो

स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने 'द सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल, 2019' लोक सभा में पेश किया। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

सरोगेसी के व्यवसायिक इस्तेमाल के पहले अपराध पर पांच साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। अगर यह अपराध दोबारा किया जाता है तो कारावास की अवधि बढ़कर 10 साल और जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये हो सकती है। सिर्फ उन भारतीय दंपतियों को ही सरोगेसी से संतान प्राप्त करने की अनुमति होगी जो संतान उत्पन्न करने में अक्षम हैं। ऐसे दंपती के लिए उनकी निकटवर्ती रिश्तेदार ही सरोगेट मां बन सकेगी। सरोगेट मां की उम्र 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए और उसका पहले से अपना एक बच्चा होना चाहिए। सरोगेट मां को सिर्फ एक बार ही सरोगेसी की अनुमति होगी। प्रस्तावित कानून के तहत सरोगेसी क्लीनिक का पंजीकरण अनिवार्य होगा और कोई भी व्यक्ति या क्लीनिक सरोगेसी का व्यवसायिक इस्तेमाल या प्रचार नहीं कर पाएगा।

'द सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल 2019' की मुख्य बातें

- राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव
- सरोगेट मां संतान चाहने वाले दंपती की नजदीकी रिश्तेदार होनी चाहिए
- सरोगेट मां की उम्र 25 से 35 वर्ष और उसका अपना एक बच्चा होना चाहिए
- सिर्फ एक बार ही सरोगेट मां बन सकेगी कोई महिला
- सरोगेसी कारोबार करने पर 10 साल कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना

बीएड कालेजों में अब पढ़ने और पढ़ाने वालों पर रहेगी नजर

नई दिल्ली : शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सभी संस्थानों को छात्रों व शिक्षकों की रोजाना की उपस्थिति का ब्योरा आनलाइन देना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस बाबत निर्देश दिए हैं। सभी बीएड कालेजों और अन्य संस्थानों को माह भीतर बायोमीट्रिक मशीनें लगानी होंगी (पेज-4)

छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों ने आठ नक्सलियों का समर्पण कराया

सुकमा : छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा का दंश झेल रहे सुकमा में पहली बार ऐसा हुआ, जब ग्रामीणों ने समझाकर आठ नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया। इनमें एक नक्सली पर एक लाख रुपये का इनामी घोषित है। रविवार को आठों नक्सलियों को लेकर ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे और आत्मसमर्पण कराया। (पेज-6)

तरसे लोगों पर जमकर बरसे बदरा

देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुई झमाझम बारिश ने गर्मी से बेहाल लोगों को राहत प्रदान की। इंडिया गेट पर स्कूटर सवारों का अंदाज उनकी खुशी को बयां कर रहा है। एएनआइ

नई दिल्ली : बारिश के लिए तरस रहे दिल्लीवासियों पर बदरा जमकर बरसे। सोमवार सुबह से ही मौसम करवट ले रहा था। हवा भी चल रही थी और बादलों एवं सूरज के बीच आंखमिचौली भी। दोपहर बाद तीन बजे के एकाएक काली घटा छा गई। इतना अंधेरा छा गया कि वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलानी पड़ गई। इसके बाद जो झमाझम बारिश शुरू हुई, वह घंटे भर तक चली। झमाझम बारिश से तापमान में भी चार डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से एक डिग्री कम) दर्ज किया गया। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान भी हल्की मानसूनी बौछारें दिल्ली को भिगोती रहेंगी। हिमालय के तराई क्षेत्रों पर टिकी मॉनसून ट्रफ के दिल्ली के करीब आने के चलते बुधवार से बारिश तेज होगी।

उठा सवाल

चौके-छक्कों के आधार पर इंग्लैंड को विश्व चैंपियन बनाने वाले नियम की हो रही आलोचना, फाइनल में 'गेंद को अवरोध' पहुंचाने के नियम में भी हुई गलती

न्यूजीलैंड के साथ हुए 'छल' से निशाने पर आइसीसी

अभिषेक त्रिपाठी ● लंदन

क्रिकेट के जनक इंग्लैंड का पहली बार विश्व कप जीतने का जश्न विवादों में घिर गया और दुनिया भर के प्रशंसक और मीडिया उपविजेता न्यूजीलैंड को छला हुआ बता रहे हैं। रविवार को लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में सुपर ओवर टाई होने के बाद चौके-छक्कों के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। यही नहीं साइमन टॉफेल सहित कई अंपायरों ने बेन स्टोक्स के बल्ले में लगकर बाउंड्री के लिए गई गेंद पर छह रन देने के फैसले को भी गलत बताया। इससे दुनियाभर में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की आलोचना हो रही है।

न्यूजीलैंड की मीडिया ने इसे अपनी टीम के साथ छल बताया है। कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी आइसीसी के नियम को हास्यास्पद करार दिया है। रविवार को लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। पहले 50-50 ओवर का मैच टाई रहा। बाद में सुपर ओवर भी टाई हो गया। आइसीसी के बनाए गए नियमों के आधार पर इंग्लैंड को इसलिए विजेता घोषित किया गया क्योंकि उसने न्यूजीलैंड के 17 चौकों-छक्कों (पारी और सुपर ओवर को मिलाकर) से ज्यादा 26 बाउंड्री लगाई थीं। युवराज सिंह, गौतम गंभीर, स्कॉट स्टायरिस, मुहम्मद कैफ, चेतेश्वर पुजारा और ब्रेट ली सहित दुनिया भर के क्रिकेटरों ने इसे आइसीसी का बेतुका नियम बताया है।

इसको लेकर न्यूजीलैंड की मीडिया में भारी गुस्सा है। न्यूजीलैंड हेराल्ड ने लिखा, 'क्रिकेट विश्व कप फाइनल : 22 नायक और कोई विजेता नहीं।' वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन ने कहा कि विश्व कप फाइनल का फैसला सुपर ओवर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए था। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और इंग्लिश कप्तान इयोन मॉर्गन दोनों को संयुक्त रूप से विश्व कप ट्रॉफी दी जानी चाहिए थी। इस तरह का फाइनल कोई भी टीम नहीं हारना चाहेगी।

छह रन देने पर भी सवाल : पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर व मेरिलबोर्न क्रिकेट कमेटी की उपसमिति के सदस्य साइमन टॉफेल ने इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स के बल्ले से लगकर चौके के लिए गई गेंद पर मैदानी अंपायरों के छह रन देने के फैसले को गलत बताकर विवाद को और गहरा दिया। 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड को जीत के लिए उस समय तीन गेंदों पर नौ रन की जरूरत थी। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने थ्रो फेंका और गेंद रन पूरा करने के लिए डाइव लगाने वाले बल्लेबाज स्टोक्स के बल्ले से लगकर चौके के लिए चली गई। अंपायरों ने दो रन दौड़ने और एक चौके को मिलाकर कुल छह रन इंग्लैंड के खाते में जोड़ दिए लेकिन टॉफेल का कहना है कि यहां पर एमसीसी के 'गेंद को अवरोध' पहुंचाने के नियम का गलत इस्तेमाल हुआ। इसमें सिर्फ पांच रन ही मिलने चाहिए थे क्योंकि थ्रो फेंके जाने के समय स्टोक्स और आदिल राशिद ने दूसरे रन के लिए एक-दूसरे को क्रॉस नहीं किया था। अगर ऐसा होता तो सुपर ओवर की जरूरत ही नहीं पड़ती और न्यूजीलैंड विश्व विजेता हो जाता।

दिल तोड़ने वाली हार के बाद नीशाम बोले, बच्चों मत बनना खिलाड़ी

लंदन : आइसीसी विश्व कप 2019 के फाइनल मैच में जेम्स नीशाम ने कीवी टीम को लगभग विश्व

चैंपियन बना ही दिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मार्टिन गुप्टिल के आउट होने से टीम खिताब अपने नाम करते-करते रह गई। नीशाम ने इस मैच के बाद एक ऐसा ट्वीट किया है, जिसे पढ़कर आपकी आंखें भर जाएंगी। नीशाम ने बच्चों को सलाह दी है कि वो खेल ना चुनें और खिलाड़ी ना बनें। उन्होंने ट्वीट में लिखा, बच्चों! खिलाड़ी मत बनना, बेकर बन जाओ या कुछ और बन जाओ। मोटे होकर 60 साल की उम्र में खुशी से मर जाना, लेकिन क्रिकेटर मत बनना।

(संबंधित सामग्री पेज-12 पर)

एनपीसीसी रिश्वत मामले में सीबीआइ ने दो अफसरों समेत सात को पकड़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनपीसीसी) लिमिटेड के दो वरिष्ठ अधिकारियों समेत सात लोगों को कथित रूप से 40 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के लिए गिरफ्तार किया है। बीएसएफ की सीमा चौकी निर्माण से संबंधित बिल पास करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। यह जानकारी सोमवार को अधिकारियों ने दी।

जांच एजेंसी ने एनपीसीसी के जोनल मैनेजर राकेश मोहन कोटवाल, मैनेजर लतिफुल पाशा और पांच अन्य (श्री गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अनीश बैद, कंपनी के निदेशक बिनोद सिंघी, कंपनी में कर्मचारी रमेश कुमार, कोटवाल के रिश्तेदार सुनील कुमार और धर्मेंद्र कुमार नामक व्यक्ति) को गिरफ्तार किया है। सुनील ने कोटवाल की ओर सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में एक होटल में रमेश कुमार से 25 लाख की रिश्वत ली। शनिवार को सीबीआइ की टीम ने छापेमारी कर रंगे हाथों उसे गिरफ्तार कर लिया। अन्य को बाद में आरोपितों से पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि सीबीआइ को लेनदेन के बारे में गुप्त सूचना मिली थी और उसके बाद छापेमारी की गई। बाद में दिल्ली, सिलचर, जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी और ग्वालियर में 18 स्थानों पर तलाशी ली गई। आरोप है कि कोटवाल और पाशा ने बैद से 33 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

बैद ने कोटवाल को बिल क्लीयर होने के बाद भुगतान का भरोसा दिया था। कोटवाल ने उसे बिल तैयार करने और पिछली तिथि से प्रोसेस करने का सुझाव दिया था। साथ ही उसने बैद को कथित रूप से तीन लाख रुपये असम के सिलचर में एनपीसीसी जोनल कार्यालय में कार्यरत कार्यालय सहायक को प्रारंभिक भुगतान करने को कहा। सीबीआइ ने कहा, तीन दिनों बाद बैद ने असम के व्यापारी विनीत अग्रवाल के माध्यम से 25 लाख रुपये देने की व्यवस्था की। यह भुगतान हवाला चैनल से किया गया।

बीएसएफ की सीमा चौकी निर्माण से संबंधित बिल पास करने के नाम पर मांगी गई थी 40 लाख की रिश्वत

34.7 डिग्री सेल्सियस रहा सोमवार को राजधानी में अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम साढ़े पांच बजे तक बारिश 28.8 मिलीमीटर हुई। मंगलवार को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 16 जुलाई 2019

हाईप्रोफाइल जालसाज दबोचे

ठगी ▸ एक खुद को पीएमओ में आयुक्त बताता था तो दूसरा आइएएस

दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारियों समेत बड़ी हस्तियों से है नजदीकी

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

कनॉट प्लेस थाना पुलिस ने दो बड़े जालसाज गिरफ्तार किए हैं। आरोपितों में एक खुद को पर्यटन मंत्रालय में आइएएस अधिकारी और दूसरा प्रधानमंत्री कार्यालय में आयुक्त आदि का प्रोफाइल बताकर ठगी करते थे। दोनों दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में लोगों को सरकारी विभागों से काम दिलवाकर अथवा उनके रुके काम करवा कर लाखों रुपये ऐंठते थे।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपितों में कृष्णा कुमार गौड़ मूल रूप से मथुरा (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है, लेकिन गुरुग्राम के बी ब्लॉक, सुशांत लोक, फेज एक में रहकर गोरखधंधे को अंजाम दे रहा था। पत्नी से विवाद के कारण वह अकेला रहता है। उसने आइआइआइटी ग्वालियर से पढ़ाई की है। वह पर्यटन मंत्रालय के अधीन आने वाले एपिरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर में आइएएस होने का दावा करता था। वह भारत सरकार लिखी कार से चलता था। साथ ही, एक प्राइवेट पीएसओ कम ड्राइवर भी रखा था।

पीएसओ महिपाल को भी उसकी असलियत पता नहीं थी। महिपाल ने पुलिस को बताया कि गौड़ अक्सर गुरुग्राम के बड़े होटलों में खुद को आइएएस बताकर मुफ्त में खाना खाता था। फेसबुक प्रोफाइल में उसने खुद को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कोआर्डिनेटर बताया है। प्रोफाइल में राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों के साथ कई फोटो हैं। गौड़ के दिल्ली पुलिस के कई विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज समेत कई बड़ी हस्तियों से नजदीकी होने का पता चला है। वह अक्सर आला अधिकारियों से मिलने दिल्ली पुलिस मुख्यालय जाता था।

दूसरा आरोपित शिवम चौहान मूल रूप से शामली (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है, लेकिन सुशांत लोक, फेज वन गुरुग्राम में वह कृष्णा कुमार गौड़ के साथ ही रहता था। इसके पास से प्रधानमंत्री कार्यालय में आयुक्त होने का फर्जी परिचय पत्र बरामद हुआ है। यह गौड़ ने ही उसे दिया था।

पुलिस के मुताबिक 11 जुलाई को कनॉट प्लेस स्थित खादी ग्रामोद्योग के कर्मचारी ने एडिशनल डीसीपी नई दिल्ली जिला को शिकायत कर बताया कि शिवम चौहान नाम का शख्स खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में आयुक्त होने का परिचय देकर चेयरमैन से मीटिंग कराने का दबाव डाल रहा है। पुलिस के कहने पर शिकायतकर्ता ने मीटिंग की तिथि तय कर दी। 12 जुलाई को शिवम देहरादून के रहने वाले राबी रावत व एक अन्य को लेकर खादी ग्रामोद्योग पहुंच गया। चेयरमैन से मीटिंग में शिवम ने पहले उन्हें अपना आइकार्ड थमाया, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय में आयुक्त होने का जिक्र था, फिर उसने चेयरमैन से कहा कि वह राबी व उसके साथ आए शख्स को कोई काम दे दें। प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें काफी फायदा दिलाया जाएगा। इस पर पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। थाने लाकर पूछताछ में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो गया। शिवम के जरिये कृष्णा को थाने बुलाकर दबोच लिया गया। भारत सरकार लिखी कार भी जब्त कर ली गई। जांच से पता चला है कि दिल्ली पुलिस युवा स्कीम के तहत जो कार्यक्रम करती है, कृष्णा ही उसका आयोजन करता था।

वीरेंद्र देव दीक्षित को भगोड़ा घोषित करने को कदम उठाएगी सीबीआइ

जासं, नई दिल्ली : रोहिणी स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संस्थापक वीरेंद्र देव दीक्षित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह दीक्षित को भगोड़ा घोषित करने के लिए कदम उठाएगी। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह प्रक्रिया जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि सत्र न्यायालय में इस पर जल्द कार्रवाई शुरू हो सके। हालांकि, डेढ़ साल बाद भी वीरेंद्र देव दीक्षित का पता नहीं लगा पाने पर मुख्य पीठ ने सीबीआइ को फटकार भी लगाई।

मुख्य पीठ ने इस दौरान आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के फैसले के खिलाफ एमसीडी ट्रिब्यूनल में की गई अपील का आठ सप्ताह के अंदर निपटारा करने के भी प्राधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि ध्वस्तीकरण पर लगी रोक को हटाने के संबंध में अब तक क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया। पीठ ने इस दौरान रिकॉर्ड पर लिया कि विश्वविद्यालय अवैध निर्माण करके बनाया गया था और वहां पर युवती व महिलाएं बुरी स्थिति में रह रही थीं। पीठ के सवाल पर नगर निगम ने कहा कि उन्होंने कई बार ट्रिब्यूनल में कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट निगरानी कर रहा है, लेकिन इस बाद भी उन्होंने रोक लगाई और इसकी समयसीमा बढ़ाई जा रही है।

सिसोदिया बोले, दिल्ली के स्कूलों में वैकल्पिक विषय होगी मैथिली

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली के स्कूलों में अब मैथिली को 8वीं से 12वीं तक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल विद्यार्थी पंजाबी और उर्दू को ही वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ते हैं। यही नहीं, सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथिली को वैकल्पिक विषय के रूप में लेने वालों के लिए दिल्ली सरकार मुफ्त कोचिंग भी कराएगी। यह जानकारी सोमवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी।

मैथिली-भोजपुरी अकादमी की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी मैथिली का कोई कंप्यूटर फोंट मौजूद नहीं है। लिहाजा मैथिली का फोंट उपलब्ध कराने के लिए सरकार सी-डैक से संपर्क कर रही है। फोंट बनने के बाद जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। सिसोदिया ने बताया कि नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में कनॉट प्लेस में पांच दिन का मैथिली-भोजपुरी उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैथिली को तो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन भोजपुरी को नहीं। आज अगर हम स्कूलों में भोजपुरी को पढ़ाना भी चाहें तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वह संविधान की अनुसूची में नहीं है। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में भी शामिल नहीं कर सकते। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कोई विद्यार्थी भोजपुरी को वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं ले सकता। यहां तक कि अगर कोई संसद में भोजपुरी में शपथ लेना चाहे तो वह भी नहीं कर सकता। इसके लिए मैथिली-भोजपुरी अकादमी के चेयरमैन के तौर पर वह केंद्र सरकार को लिख रहे हैं कि भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। जागरण

▸ **कहा, मैथिली-भोजपुरी में उल्लेखनीय काम करने वालों को करेंगे सम्मानित**

मिलेगा सम्मान

उप-मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि मैथिली-भोजपुरी भाषा में कला, साहित्य, रंगमंच, शोध, पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली शख्सियतों को सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान इस प्रकार से हैं

1. शिखर सम्मान (मैथिली) लाइफटाइम अचीवमेंट (2.5 लाख)
2. शिखर सम्मान (भोजपुरी) लाइफटाइम अचीवमेंट (2.5 लाख)
3. साहित्यकार सम्मान (मैथिली) (1 लाख)
4. साहित्यकार सम्मान (भोजपुरी) (1 लाख)
5. कला एवं संस्कृति सम्मान (मैथिली) (1 लाख)
6. कला एवं संस्कृति सम्मान (भोजपुरी) (1 लाख)
7. पत्रकारिता (मैथिली) (1 लाख)
8. पत्रकारिता (भोजपुरी) (1 लाख)
9. समालोचना (मैथिली) (1 लाख)
10. समालोचना (भोजपुरी) (1 लाख)
11. अनुवाद (मैथिली) (1 लाख)
12. अनुवाद (भोजपुरी) (1 लाख)

न्यूज गैलरी

कपिल ने की केजरीवाल की सदस्यता रद करने की मांग

नई दिल्ली : विधायक कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सदस्यता रद करने की मांग वाली याचिका दायर की है। मिश्रा ने केजरीवाल पर पार्टी विरोधी गतिविधियों, देश विरोधी कार्यों और विरोधी राजनीतिक दलों का प्रचार करने संबंधी आरोप लगाकर याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, मयंक गांधी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के बयानों का हवाला देते हुए केजरीवाल की पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोपित बताया। मिश्रा ने याचिका में केजरीवाल को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने केजरीवाल के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयानों, सेना पर दिए बयानों का उल्लेख करते हुए उन्हें पार्टी संविधान के खिलाफ कार्य करने वाला बताया। (जासं)

कैलाश गहलोत के विभाग बढ़े इमरान हुसैन के घटे

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कद बढ़ाते हुए उनके विभागों में वृद्धि की है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन से पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव जंतु विभाग लेकर गहलोत को दे दिए गए हैं। अब गहलोत के पास छह विभाग हो गए हैं, जबकि इमरान के पास महज दो विभाग बचे हैं। गहलोत के पास पहले विधि, न्याय एवं विधायी कार्य, परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और राजस्व विभाग थे। इनमें पर्यावरण, वन तथा वन्य जन्तु विभाग भी जुड़ गए हैं। वहीं हुसैन के पास अब केवल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और चुनाव रह गए हैं। (जासं)

एयरपोर्ट पर लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी में दो धरे

नई दिल्ली : इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी में दो लोगों को धरा है। दोनों तस्कर भारतीय हैं और बैंकाक जाने की जुगत में लगे थे। उनके पास से 130 किलो लाल चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। इसकी कीमत 19 लाख रुपये आंकी गई है। सीआइएसएफ के प्रवक्ता हेमेंद्र सिंह ने बताया कि 14 जुलाई की आधी रात उनकी सर्विलांस टीम को टर्मिनल-3 के चेकइन एरिया में संदिग्ध अवस्था में दो शख्स भारी बैग लेकर घूमते हुए मिले थे। उनके सामान की जांच हुई तो 130 किलो लाल चंदन की लकड़ी बरामद हुई। इस बारे में पूछताछ पर वे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। इसके बाद जवानों ने चंदन की लकड़ी जब्त कर दोनों तस्करों राहुल कुमार और मिराजुद्दीन को कस्टम अधिकारियों के हवाले कर दिया। (जासं)

दिल्ली सरकार प्रत्येक सफाईकर्मी को देगी सुरक्षा किट : केजरीवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सरकारी या निजी कंपनी के सफाईकर्मी अब सीवर में बिना सुरक्षा किट के नहीं उतरेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार प्रत्येक सफाईकर्मी को सुरक्षा किट प्रदान करेगी। यह बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित सीवर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला के दौरान कही। साथ ही सफाईकर्मियों ने किट का प्रयोग करने के लिए शपथ पत्र भी लिया। इस मौके पर मुख्य सचिव विजय देव, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल कुमार और उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस समय उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली थी, उस समय यहां 58 फीसद कालोनियों में ही पीने के पानी की सप्लाई होती थी। अब 93 फीसद कालोनियों में पीने के पानी की आपूर्ति हो रही है। कानूनी दावपेंच वाली कालोनियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर कालोनी में पानी पहुंचा दिया गया है। सरकार की पहली प्राथमिकता हर घर में पानी पहुंचाने की है। इसके बाद दिल्ली में 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की सप्लाई का प्रयास किया जाएगा, ताकि लोगों को आरओ की जरूरत न पड़े।

केजरीवाल ने कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आई थी उस समय सिर्फ 50 फीसद कालोनियों में सीवरलाइन थी, लेकिन आज करीब 80 फीसद में सीवर की पाइपलाइन बिछ चुकी है। इसे 100 फीसद पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। दिल्ली सरकार दलगत राजनीति के ऊपर उठकर हर क्षेत्र में समान विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में न्यूनतम मजदूरी लागू करने वाली पहली सरकार दिल्ली की है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब किसी की भी जान सीवर की सफाई में न जाए, इसके लिए ही सरकारी व निजी प्रत्येक सफाईकर्मी को सुरक्षा किट देने का निर्णय लिया गया है। निजी ठेकेदार कच्ची कालोनियों में सफाईकर्मियों से काम कराते हैं, जिनकी जान को खतरा रहता है। ऐसे कर्मचारी अब सुरक्षाकिट के साथ ही सीवर में उतरें।

सफाईकर्मी खुद भी रहें जागरूक : दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने कहा कि सफाईकर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन सफाईकर्मी खुद भी जागरूक रहेंगे, तभी सरकार का यह प्रयास सफल हो सकेगा। कार्यशाला में सफाई कर्मचारियों को सीवर में सुरक्षा किट के साथ उतरने का प्रशिक्षण देने के साथ ही अन्य जरूरी जानकारी दी गई।

तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से आयोजित सीवर सुरक्षा कार्यशाला के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य। जागरण

एयरपोर्ट पर पायलट को बंधक बनाकर लूटा

जासं, नई दिल्ली : इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट पर कैब चालक और उसके साथियों ने इंडिगो एयरलाइंस के पायलट को बंधक बनाकर करीब एक लाख 32 हजार की लूटपाट की है। कैब चालक ने उन्हें इंडिगो की पार्किंग छोड़ने का झांसा देकर अपनी कैब में बैठाया था। इसके बाद साथियों की मदद से चाकू के बल पर पायलट से एटीएम, डॉलर व नकदी छीन ली। आइजीआइ एयरपोर्ट के पुलिस उपायुक्त संजय भटिया ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान कर ली है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

मूलरूप से कनाडा निवासी मुहम्मद मेहंदी घाजनफानी निजी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो में पायलट (कैप्टन) के पद पर कार्यरत हैं। वह 12 जुलाई की आधी रात विमान लेकर आइजीआइ के डोमेस्टिक टर्मिनल-1 पर आए थे। नई दिल्ली के होटल ली मेरिडियन में उन्हें ठहरना था। टर्मिनल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कैब के लिए अपनी कंपनी के एजेंट को फोन किया। उसने बताया कि कैब चालक इंडिगो पार्किंग में मौजूद है। उन्हें पार्किंग की जानकारी नहीं थी। लिहाजा पार्किंग जाने के लिए जैसे ही वह टर्मिनल-1 मेट्रो स्टेशन के गेट संख्या दो के समीप पहुंचे। वहां मौजूद एक युवक ने कहा कि 100 रुपये में वह उन्हें कैब से पार्किंग स्थल तक छोड़ देगा। वह जब कैब में बैठे तो उसमें पहले से ही चालक के अलावा तीन अन्य लोग मौजूद थे। इन लोगों ने पायलट को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। इसके बाद एटीएम कार्ड लेकर दस बार में एक लाख रुपये निकाल लिए।

एनडीएमसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान तथ्यों को छिपाकर अवकाशकालीन पीठ से अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने के लिए सोमवार को एनडीएमसी को जमकर आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने कहा, 'क्या आप इस तरह से इस संस्था को बदनाम करना चाहते हैं।' डीजल वाहनों के पंजीकरण के बारे में प्राप्त किया गया 16 मई का आदेश वापस लेते हुए कोर्ट ने एनडीएमसी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ इस बात से बेहद नाराज थी कि नियमित पीठ ने सात मई को आदेश पारित करते हुए इस मामले में जुलाई में सुनवाई का आदेश दिया था। जब एनडीएमसी की तरफ से पेश वकील ने यह कहा कि मानसून को ध्यान में रखते हुए ही अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले को लाया गया था तो पीठ ने कहा, 'हम पर हावी होने की कोशिश नहीं करिए, इस मामले में तो अनैतिकता की हद हो गई।' यह मामला नालों से गंदगी और गाद निकालने के लिए विशेष उपकरणों से सुसज्जित छह डीजल वाहनों के पंजीकरण और नगर निगम के ठोस अपशिष्ट नियम 2016 पर अमल से संबंधित था।

दरअसल, जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सात मई को कहा था कि प्रदूषण के मामले के साथ ही इस पर जुलाई में विचार किया जाएगा, लेकिन एनडीएमसी की ओर से अवकाशकालीन पीठ के समक्ष 16 मई को इस मामले को लाया गया। इस दौरान पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को इन डीजल वाहनों का पंजीकरण करने का निर्देश दिया था। इस मामले की सोमवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सात मई को उसने अंतरिम राहत से स्पष्ट रूप से इन्कार किया था, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि क्या ये वाहन पेट्रोल या सीएनजी में भी उपलब्ध हैं। यही वजह थी कि इसे जुलाई में सुनने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, 'इस न्यायालय में यह क्या हो रहा है? यह (अवकाशकालीन पीठ का 16 मई का आदेश) एक तरह से अंतिम है। इसमें अब करने के लिए क्या बचा है?

पीठ ने इस तथ्य पर भी नाखुशी जाहिर की कि अवकाशकालीन पीठ को एनडीएमसी के वकील ने यह जानकारी नहीं दी कि नियमित पीठ पहले ही अंतरिम राहत से इन्कार कर चुकी है। पीठ ने कहा कि जब इस मामले में कोई नई अर्जी दाखिल नहीं हुई तो फिर अवकाशकालीन पीठ के समक्ष इस मामले को क्यों लाया गया। अवकाशकालीन पीठ का 16 मई का आदेश वापस लेने के बाद अब एक उचित पीठ इस पर विचार करेगी।

▸ **तथ्यों को छिपा अवकाशकालीन पीठ से अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने का मामला**

क्या आप इस तरह से इस संस्था को बदनाम करना चाहते हैं। हम पर हावी होने की कोशिश मत कीजिए। इस मामले में तो अनैतिकता की हद हो गई।'
–कोर्ट की टिप्पणी

जेवर एयरपोर्ट के लिए क्वेरी देने की समय सीमा बढ़ी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (नियाल) ने जेवर एयरपोर्ट के लिए क्वेरी देने की समय सीमा को 22 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इंडिया एक्सपो मार्ट में सोमवार को हुई प्री बिड कांफ्रेंस में कंपनियों के आग्रह पर नियाल ने यह फैसला किया है। 31 अगस्त को नियाल क्वेरी का जवाब कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करेगी।

प्री बिड कांफ्रेंस में उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीधे अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसका सीधा लाभ उद्योगपतियों और कारोबारियों को मिलेगा। क्षेत्र में कारोबार को नई ऊंचाई मिलेगी। विकास की दृष्टि से क्षेत्र आगे होगा। एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण छह गांवों की 3300 एकड़ जमीन पर होगा।

प्री बिड कांफ्रेंस में शामिल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि क्वेरी देने के लिए उन्हें कुछ और समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कांफ्रेंस में अपनी क्वेरी भी रखी। कंपनियों ने बिड के लिए सौ करोड़ रुपये की धरोहर राशि को कम करने का आग्रह किया। इसके अलावा तकनीकी पैरामीटर को भी लचीला करने का अनुरोध किया। नियाल ने स्पष्ट किया कि बिड व कंसेशन एग्रीमेंट के पैरामीटर पीएमआइसी, प्रदेश कैबिनेट, केंद्र सरकार के विभाग व नीति आयोग की सलाह पर तय किए गए हैं। इसमें बदलाव संभव नहीं है। पैरामीटर में बदलाव होने पर पीएमआइसी व प्रदेश कैबिनेट से अनुमोदन लिया जाएगा।

कंपनियों की मांग पर नियाल ने 22 जुलाई तक क्वेरी देने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया। बिड में हिस्सा लेने की इच्छुक कंपनी प्रतिनिधियों से कहा कि वह 22 जुलाई तक ईमेल या कंपनी की वेबसाइट पर अपनी क्वेरी उपलब्ध करा दें। इसका जवाब 31 अगस्त को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कांफ्रेंस में नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया व पीडब्ल्यूसी ने जेवर एयरपोर्ट का प्रस्तुतीकरण दिया।

पेशाब करने से रोका, नहीं माना तो की हत्या

जासं, नई दिल्ली : तिलक नगर थानाक्षेत्र में पेशाब करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की भीड़ के सामने सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अंकित (19) के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, एक आरोपित रवि को गिरफ्तार किया गया है।

अंकित के बड़े भाई रोहित फोटोग्राफ की दुकान में काम करते हैं। एक दुकान में अंकित ने मोबाइल ठीक होने के लिए दिया था। शनिवार रात जब वह नहीं लौटे तो रोहित इनकी तलाश में निकले। जब वह न्यू महावीर नगर स्थित गली नंबर एक शिव शक्ति मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि वहां भीड़ लगी है। इन्होंने देखा कि पिज्जा बेचने वाला एक लड़का रवि, अंकित पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। वारदात के बाद रवि फरार हो गया। रोहित अपने भाई को डीडीयू अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, हत्या का कारण पेशाब करने को लेकर हुआ विवाद था। अंकित पिज्जा की दुकान के सामने खड़े थे। वह पास ही एक जगह पर पेशाब करने जाने लगे। इसका दुकानदार ने विरोध किया। इस पर दोनों में विवाद होने लगा। विवाद इस कदर बढ़ा कि दुकानदार ने स्टॉल पर रखा चाकू उठाया और अंकित पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

कारगिल विजय की गाथा बताने को रवाना हुई ट्रेन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के शौर्य को दर्शाने वाली तस्वीरों से सजी हुई काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के सोमवार को नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने पर भारत माता की जय के उद्घोष के साथ स्वागत हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी और नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया।

अंगड़ी ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा दिखाए गए पराक्रम और बलिदान के संदेश को ले जाने वाली यह ट्रेन दूरदराज के गांवों, कस्बों और शहरों तक जाएगी। यह शहीदों के प्रति सम्मान और आभार प्रदर्शित करने और देशवासियों को कारगिल युद्ध में सैनिकों की वीरता की जानकारी देने के लिए भारतीय रेल की पहल है।

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि कारगिल विजय के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1999 में इस युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को अलग अंदाज में श्रद्धांजलि और सम्मान देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 20वें कारगिल विजय दिवस की स्मृति में 218 रेल कोच को सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की कहानी कहने वाले वीरता के रंग में रंगा गया है। इन्हें दस ट्रेनों में लगाया जाएगा। इस तरह के विशेष कोच से सजी हुई ट्रेनें लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करेंगी और सौहार्द व अखंडता का संदेश देंगी।

यात्रियों ने भी रेलवे के इस पहल की सराहना की है। वाराणसी जा रहे शंभु राय ने कहा कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने और जवानों की वीरता को याद कराने की यह पहल सराहनीय है। राखी सिंह ने कहा कि अन्य ट्रेनों में भी ऐसे कोच लगाए जाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सैनिकों की वीरता की जानकारी मिल सके। कार्यक्रम में भारतीय सेना के जीओसी (दिल्ली क्षेत्र) लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री, लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के भाई विशाल बत्रा, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक टीपी सिंह सहित कई रेलवे अधिकारी मौजूद थे।

कारगिल युद्ध की विजय गाथा की जानकारी देने के लिए विशेष तस्वीरों से सजाई गई काशी विश्वनाथ ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। ध्रुव कुमार

मिशन एडमिशन

नॉर्थ कैंपस के कॉलेजों में छात्रों को मिला दाखिले का अवसर

दिल्ली विवि के चौथे कटऑफ के पहले दिन 4,412 छात्रों के दाखिले हुए, इस साल अब तक 58,558 छात्र स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके हैं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के चौथे कटऑफ के तहत सोमवार को छात्र कॉलेजों में दाखिला लेने पहुंचे। छात्रों के लिए चौथा कटऑफ बेहद खास रहा, क्योंकि कई छात्रों को नॉर्थ कैंपस के प्रमुख कॉलेजों में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दाखिला मिला।

चौथे कटऑफ के तहत हिंदू कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में सामान्य श्रेणी में 97.75 फीसद और सोशलॉफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स में चौथा कटऑफ 97.25 फीसद, जियोलॉजी ऑनर्स में 95.33 फीसद और लाइफ साइंस कोर्स में 94.66 फीसद तक जारी हुआ। इसमें भी छात्रों को दाखिले का अवसर मिला। वहीं, किरोड़ीमल कॉलेज में अन्य प्रमुख कोर्स में दाखिले बंद हो चुके हैं, लेकिन इस कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम कोर्स में छात्र दाखिला लेने के लिए पहुंचे। कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 97.25 फीसद और बीकॉम में 96.75 फीसद तक कटऑफ गया। वहीं मिरांडा हाउस कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 97.52 कटऑफ होने के बाद भी कई छात्राएं दाखिला लेने के लिए पहुंचीं।

श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) में भी छात्रों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दाखिले का अवसर मिला। इस कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में चौथा कटऑफ 98.62 फीसद तक जारी हुआ। इसमें कई छात्र दाखिला लेने पहुंचे।

दौलत राम कॉलेज में दाखिला लेने पश्चिम विहार से पहुंची सुमेधा सिंह ने कहा कि मुझे खुशी है कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में मेरा चौथे कटऑफ में दाखिला हो गया है। मैं बहुत पहले से उम्मीद लगाए हुए थी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इस कॉलेज में 95.75 फीसद तक कटऑफ जारी हुआ है। इस कालेज में काफी छात्राएं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में भी दाखिला लेने के लिए पहुंचीं। इस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में 95 फीसद तक कटऑफ जारी हुआ था। छात्र-छात्राएं सुबह के कॉलेजों में सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक अपना दाखिला लेने के लिए पहुंचे थे। दाखिले के लिए दोपहर एक बजे तक का ही समय था। लेकिन दाखिले से दस्तावेजों की कॉपी को जांचने के लिए एक से दो घंटे लगे। इससे छात्रों को इंतजार भी करना पड़ा।

डीयू प्रशासन के अनुसार सोमवार को चौथे कटऑफ के पहले दिन तीन हजार छात्रों के दाखिले हुए। अब तक डीयू में 57 हजार तक दाखिले हो चुके हैं।

छात्र रद भी करा रहे हैं दाखिले : डीयू के कॉलेजों के अधिकारियों ने कहा कि कैंपस और कैंपस के बाहर के कॉलेजों में कई छात्र चौथे कटऑफ के पहले दिन अपने दाखिले रद भी कराने पहुंचे। इन छात्रों के तीसरे कटऑफ में दाखिले हो चुके थे। लेकिन चौथे कटऑफ में इन छात्रों को अपने मनपसंद कोर्स और कॉलेज में दाखिले का मौका मिला। इसके कारण इन्हें अपने दाखिले रद कराए। अब अगले दो दिन भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कुछ छात्र अपने दाखिले रद कराने आ सकते हैं। चौथे कटऑफ के तहत बुधवार तक छात्रों के पास दाखिले का अवसर है।

अब तक कुल 58,558 ने लिया प्रवेश : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्टूडेंट वेलफेयर डीन एवं दाखिला समिति के अध्यक्ष प्रो. राजीव गुप्ता ने सोमवार रात नौ बजे चौथे कटऑफ के पहले दिन तक हुए दाखिले के आंकड़े जारी किए। उन्होंने बताया कि सोमवार को कुल 4,412 छात्रों के दाखिले हुए। अब तक डीयू में कुल 58,558 छात्रों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले हो चुके हैं। डीयू में कुल 62 हजार स्नातक कोर्स की सीटें हैं।

डीयू के चौथे कटऑफ के बाद रामजस कालेज में दाखिला फार्म भरती छात्रा। जागरण

डूसू का आरोप, डीयू में वामपंथी एजेंडा थोपने की हो रही कोशिश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रो. योगेश त्यागी के खिलाफ उनके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एबीवीपी का आरोप है कि डीयू के कुछ विभागों के नए पाठ्यक्रमों में आपत्तिजनक और एकपक्षीय सामग्री को शामिल किया जा रहा है। अंग्रेजी और इतिहास विभाग के ऐसा हो रहा है। इसके विरोध में कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। छात्र संगठन का आरोप है कि डीयू के इन विभागों में वामपंथी विचारधारा के एजेंडे को छात्रों पर थोपने का प्रयास हो रहा है। एबीवीपी का दावा है कि डीयू के कुछ विभागों के पाठ्यक्रमों में हिंदू धर्म संबंधी आपत्तिजनक पाठ्यक्रम सामग्री को शामिल किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष (डूसू) अध्यक्ष शक्ति सिंह ने कहा कि डीयू में वामपंथियों के एजेंडा को थोपने की कोशिश हो रही है। डीयू के अकादमिक मामलों की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार को हुई थी। इसमें अंग्रेजी विभाग के पाठ्यक्रम के सिलेबस में कुछ बदलाव करने के प्रस्ताव लाए गए थे। समिति के कुछ सदस्यों ने इस पर विरोध जताया और आरोप लगाया कि इसमें गलत तथ्यों को पाठ्यक्रमों में डाला गया है। इसे तुरंत हटाया जाए। एबीवीपी ने डीयू से मांग की है कि विभागों के कुछ पाठ्यक्रमों में राष्ट्रवादी संगठनों पर पक्षपातपूर्ण लेखों और हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक पाठ्य सामग्री को शामिल किया गया है, इसे तुरंत हटाया जाए। एसी के सदस्य ने यह भी आरोप लगाया है कि शुक्रवार को अकादमिक मामलों की स्थायी समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के कोर्स के पाठ्यक्रमों के सिलबेस में बदलाव करने के मामलों पर चर्चा हुई थी। इसमें 2013 में मुज्जफरनगर दंगों और भीड़ की तरफ से हत्या करने की घटनाओं को अंग्रेजी पत्रकारिता में शामिल किया गया है।

235 आतंकवादी मारे गए 2017 में विभिन्न आतंकवाद निरोधी अभियानों में। 2018 में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 265 थी। इन दो वर्षों में सेना के 85 सैनिक शहीद हुए हैं। 2017 में इनकी संख्या जहां 42 थी, वहीं 2018 में 43 थी।

मिलेगी मजबूती ▶ राष्ट्रीय जांच एजेंसी को और अधिकार देने वाला संशोधन विधेयक लोकसभा से पास

एनआइए कानून का नहीं होंने देंगे दुरुपयोग : शाह

चर्चा के दौरान ओवैसी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच हुई तीखी नोकझोंक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- शाह बोले- हम आतंकवाद को 'लेफ्ट' और 'राइट' के नजरिये से नहीं देखते
- अब साइबर क्राइम और मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच करेगी एजेंसी

आतंकी हमलों की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को और अधिक अधिकार देने से संबंधित विधेयक पर लोकसभा ने मुहर लगा दी है। इसके तहत एनआइए को अब साइबर क्राइम और मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच का अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ ही एनआइए विदेशी धरती पर भारतीय या भारतीय हितों पर हमलों की भी जांच कर सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एनआइए के दुरुपयोग की विपक्षी सांसदों की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि सरकार आंतकवाद में किसी तरह का अंतर नहीं करती है।

सरकार के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देते हुए अमित शाह ने उम्मीद जताई कि एक मजबूत एनआइए के सहारे भारत आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने में सफल होगा। उन्होंने कहा कि एनआइए 90 फीसद मामलों में दोषियों को सजा दिलाने में सफल रही है, जिससे साबित होता है कि यह दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसियों में से है। एनआइए के एक खास समुदाय के खिलाफ दुरुपयोग की आशंकाओं को खारिज करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार कानून के हिसाब से काम करती है और सभी एजेंसियां कानून सम्मत मापदंड का पालन करती हैं। उन्होंने सदन को भरोसा दिया कि सरकार किसी भी तरीके से इस एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करेगी। गृह मंत्री ने साफ किया कि 'आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है, यह न तो 'लेफ्ट' है और न ही 'राइट' है। आतंकी हमले की साजिश करने वाले को सजा दिलाना जरूरी है और यह जरूर मिलेगी।'

नई दिल्ली में सोमवार को संसद के निम्न सदन लोकसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को और अधिक अधिकार देने से संबंधित विधेयक पर चर्चा के दौरान एआइएमआइएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की टोका-टाकी से गृह मंत्री अमित शाह नाराज हो गए (टीवी ग्रैब)। प्रेट्र

शाह ने कहा, मन में डर बैठा हो तो वह क्या कर सकते हैं : विधयेक पर चर्चा के दौरान एआइएमआइएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की टोका-टाकी से अमित शाह नाराज हो गए। शाह ने ओवैसी को कहा कि विपक्षी सांसदों के बोलने के दौरान सत्तापक्ष के किसी सांसद ने टोका-टाकी नहीं की थी, इसीलिए उन्हें भी शांत होकर सत्तापक्ष के सांसद की बात सुननी चाहिए। इस पर ओवैसी ने शाह से कह दिया कि उंगली मत दिखाइये, हम डरने वाले नहीं है। इसके जवाब में शाह ने कहा कि वे किसी को डरा नहीं रहे हैं, लेकिन यदि किसी के मन में डर बैठा हो, तो वे क्या कर सकते हैं।

एक दिन पाकिस्तान करेगा सार्क समझौते पर हस्ताक्षर : विपक्ष ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के खिलाफ सार्क समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने का मुद्दा उठाया। विपक्ष का कहना था कि इससे पाक के भीतर से आतंकवाद खतरे से निपटने में एनआइए पूरी तरह सक्षम नहीं हो सकेगा। भले ही उसे विदेशी धरती पर भारतीय या भारतीय हितों के खिलाफ हमले की जांच का अधिकार दे दिया जाए। जवाब में शाह ने कहा कि पाकिस्तान के सार्क समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने की वजह से हम एनआइए में संशोधन को रोक नहीं सकते हैं। किसी न किसी दिन पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय दबाव में हस्ताक्षर करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वैसे इसके बिना भी पाकिस्तान की धरती पर पनप रहे आतंकवाद से निपटने के लिए कई दूसरे रास्ते भी हैं।

एनआइए कानून को मिलेगी मजबूती

आतंकवाद के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से लोकसभा में एनआइए संशोधित विधेयक 2019 पारित हो गया है। अब इस विधेयक के राज्यसभा से पारित होने का इंतजार है, जिसके बाद एनआइए पहले से और अधिक मजबूत हो जाएगी। आइये जानते हैं कि एनआइए (संशोधन) विधेयक में क्या बदलाव किए गए हैं? पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, एनआइए अधिनियम 2008 में तीन प्रमुख संशोधन किए गए हैं।

- **पहला बदलाव अपराधों का प्रकार है, जिसकी जांच एनआइए कर सकती है और मुकदमा चला सकती है। मौजूदा अधिनियम के तहत, एनआइए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 जैसे अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच कर सकती है।**
- **संशोधित विधेयक एनआइए को मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री, साइबर आतंकवाद, और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 जैसे अपराधों की जांच करने में सक्षम बनाएगा।**
- **दूसरा परिवर्तन एनआइए के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। मौजूदा अधिनियम के तहत, इसके दायरे में आने वाले अपराधों के लिए, एनआइए अधिकारियों के पास अन्य पुलिस अफसरों के समान शक्ति होती है। देश के किसी भी राज्य में जांच करने के लिए यह स्वतंत्र है। संशोधित विधेयक एनआइए अफसरों को भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि एनआइए का क्षेत्राधिकार अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन होगा।**
- **तीसरा परिवर्तन एनआइए के दायरे में आने वाले अपराधों या तथाकथित सूचीबद्ध अपराधों के लिए विशेष परीक्षण अदालतों से संबंधित है। मौजूदा अधिनियम केंद्र को एनआइए की जांच के लिए विशेष अदालतों के गठन की अनुमति देता है। संशोधित विधेयक केंद्र सरकार को इस तरह की जांच के लिए सत्र अदालतों को विशेष अदालत के रूप में गठित करने शक्ति प्रदान करता है।**

कब हुआ गठन

- **भारत में आंतकवाद से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2008 को संसद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक्ट 2008 पारित कर एनआइए का गठन किया था। यह एजेंसी देश में आंतकवाद से जुड़ी किसी भी जांच के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए इसे राज्यों से किसी भी तरह की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।**

संसद प्रश्नोत्तर

उज्ज्वला से घटे दमा-खांसी के 20 प्रतिशत मामले

- गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुई उज्ज्वला योजना

नई दिल्ली, प्रेट्र / एएनआइ : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना गांव-गरीब के परिवारों को धुएं से निजात दिलाने के साथ ही दमा-खांसी के मामलों में 20 फीसद तक कमी लाने में भी सफल रही है। गरीब महिलाएं चूल्हे के धुएं से सबसे ज्यादा दमा-खांसी से पीड़ित हैं।

लोकसभा में एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए उज्ज्वला योजना वरदान साबित हो रही है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। यह 27 फीसद गरीबों को बीपीएल श्रेणी से ऊपर लाने में भी मददगार साबित हुई है।

उन्होंने कहा कि इंडियन चेस्ट सोसायटी तथा इंडियन चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उज्ज्वला की वजह से महिलाओं की खांसी-दमा के मामलों में 20 फीसद की कमी आई है। उन्होंने कहा कि यह योजना का सबसे संतोषजनक पहलू है।

बता दें कि उज्ज्वला को सरकार ने मई 2016 में लांच किया था। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। तीन साल में सरकार का लक्ष्य लगभग 5 करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। प्रधान ने कहा कि इस योजना के तहत देशभर में सरकार ने अब तक 7.34 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 1.34 करोड एलपीजी कनेक्शन बांटे गए हैं। उन्होंने बताया कि 86 फीसद उज्ज्वला के लाभार्थियों ने अपना पहला सिलेंडर उपयोग करने के बाद वापस कर दूसरा भरा सिलेंडर खरीदा। दूसरा सिलेंडर लेने पर सब्सिडी लाभार्थियों के खाते में डाल दी गई। प्रधान ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए पांच वर्ष में देशभर में 9000 से ज्यादा एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं।

अब नए परंपरागत पाठ्यक्रमों को मंजूरी नहीं देगा एआइसीटीई

नई दिल्ली, प्रेट्र : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से कम रोजगार की संभावना वाले नए परांपरागत पाठ्यक्रमों को शुरू करने की अनुमति नहीं देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉक चेन, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डाटा साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी और 3 डी प्रिंटिंग एंड डिजाइन जैसे उभरते हुए पाठ्यक्रमों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। यह जानकारी सोमवार को सरकार ने लोकसभा में दी।

प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह भी कहा कि इंजीनियरिंग छात्र मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा बन सकें, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, उद्योगों की जरूरतों और इंजीनियरिंग संस्थानों में चल रहे कोर्सों के बीच की खाई को पाटने के लिए एआइसीटीई ने कई कदम उठाए हैं। इसमें छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप भी शामिल है। इंजीनियरिंग छात्रों को मिलने वाले रोजगार पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आइआइटी के छात्र दुनिया की 500 शीर्ष कंपनियों में से 200 में कार्यरत हैं।

रमेश पोखरियाल निशंक फाइल फोटो

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दावा किया कि उद्योगों की आवश्यकताओं के मुकाबले इंजीनियरिंग संस्थानों में जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनके बीच कोई मेल नहीं है। इसे खत्म किया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अगर इस बेमेल संबंध को खत्म कर दिया जाए तो कोई भी रोजगार के लिए छात्रों को पकौड़े तलने की सलाह नहीं देगा।

दो सालों में हुए 470 आतंकी हमले

नई दिल्ली, एएनआइ : सरकार ने राज्यसभा को बताया कि 2017 और 2018 में देश में 470 आतंकी हमले हुए। भाजपा सांसद विजय गोयल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि 2017 में 131 हमले केवल जम्मू-कश्मीर में हुए। मणिपुर में आठ जबकि अरुणाचल व असम में इस दौरान एक-एक हमला हुआ। 2018 में जम्मू-कश्मीर में 318 हमले हुए जबकि मणिपुर में आठ और नगालैंड में तीन आतंकी हमले हुए।

ढांचा विध्वंस मामले में जज ने और छह माह का समय मांगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने के मामले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट से और छह माह का समय मांगा है। इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती एवं अन्य शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश ने 25 मई को लिखे गए पत्र में शीर्ष कोर्ट को सूचित किया है कि उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2019 तक निर्धारित है। सोमवार को जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामला पेश किया गया। पीठ ने उप्र सरकार को 19 जुलाई तक उस प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए कहा है जिसके तहत विशेष न्यायाधीश के कार्यकाल को इस चर्चित मामले में फैसला सुनाने तक का विस्तार दिया जा सकता है। 19 अप्रैल 2017 को शीर्ष कोर्ट ने 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई रोजाना आधार पर दो वर्षों में पूरी करने का आदेश दिया था। मध्य युग के ढांचे को ढहाए जाने को अपराध करार देते हुए कोर्ट ने सीबीआइ को वीवीआइपी आरोपितों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप की दलील को अनुमति दी थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कल्याण सिंह जबतक इस पद पर बने हैं तबतक वह संविधान के तहत प्रतिरक्षा के हकदार हैं। जिस समय विवादित ढांचा ढहाया गया था उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

मामले की सुनवाई में 25 साल की देरी के लिए कोर्ट ने सीबीआइ को फटकार लगाई थी। कहा था, 'आरोपितों को कठघरे में नहीं लाया गया क्योंकि सीबीआइ ने संयुक्त सुनवाई में अभियोजन नहीं चलाया। यह जिन तकनीकी कारणों से हुआ उसे दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया।'कई निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि रायबरेली के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट से आडवाणी एवं अन्य पांच के खिलाफ कार्यवाही लखनऊ के विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (अयोध्या मामले) की अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा।

नीरज शेखर ने राज्यसभा और सपा से दिया इस्तीफा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र के भाजपा में शामिल होने की अटकलें
- राज्यसभा से इस्तीफा मंजूर, समाजवादी पार्टी ने साधा मौन

लोकसभा चुनाव में मिली करारी मात से समाजवादी पार्टी (सपा) अभी उबर भी नहीं पाई थी कि सांसद नीरज शेखर ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा देकर उसे बड़ा झटका दे दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक खटास पैदा हो गई थी। नीरज के इस्तीफे पर सपा नेता चुप हैं। उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को नीरज शेखर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। सदन में उनका कार्यकाल नवंबर 2020 तक था। दरअसल, लोकसभा चुनाव के दौरान नीरज शेखर बलिया संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने टिकट की मांग की थी। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें आश्वस्त भी किया था, लेकिन आखिरी वक्त तक भरोसा देकर अचानक उनकी जगह सदानंद पांडेय को बलिया से उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया गया। इसके बाद से उनकी नाराजगी बढ़ती ही गई।

राज्यसभा के सभापति एम. वैंकैया नायडू को इस्तीफा सौंपते नीरज शेखर। ट्विटर

आजमगढ़ से जीतकर आए पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से उनकी एक भी मुलाकात नहीं हुई। संसद परिसर में दोनों के बीच दुआ सलाम भी बंद हो गई थी। दोनों नेताओं के बीच नाराजगी पार्टी के अन्य नेताओं में चर्चा का विषय तो थी, लेकिन उनके पार्टी छोड़ देने पर सभी अचंभित हैं। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चंद्रशेखर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिबंश की पुस्तक 'चंद्रशेखर : द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स' का विमोचन करेंगे। उससे पहले ही नीरज शेखर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। मालूम हो कि चंद्रशेखर के निधन के बाद नीरज शेखर ने पहली बार बलिया से ही चुनाव लड़ा था। 2007 में बलिया संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में भारी मतों के अंतर से जीतकर नीरज शेखर संसद पहुंचे थे। चंद्रशेखर की विरासत संभाल रहे नीरज ने अपने राजनीतिक तेवरों के चलते ही 2009 के आम चुनाव में भी बाजी मारी और 2014 तक संसद में रहे। 2014 की मोदी लहर में वह भाजपा के भरत सिंह से चुनाव हार गए थे।

इसके बाद समाजवादी पार्टी (सपा) ने उन्हें 2014 में राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचा दिया था। तथ्य यह है कि बलिया संसदीय सीट से लगातार चंद्रशेखर चुनाव जीतते रहे। वह कभी सपा के सदस्य नहीं थे, लेकिन तत्कालीन सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव उनके खिलाफ कभी अपना प्रत्याशी नहीं उतारते थे। पिछले दिनों राज्यसभा में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी नीरज शेखर के किसी व्यवहार पर बिना शर्त यह कहकर माफी मांगी थी कि घटना के दिन वह (रामगोपाल) सदन में उपस्थित नहीं थे।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में अफसरों के प्रोफाइल की हो रही जांच : गोयल

- लंदन में भारतीय समुदाय से बातचीत में बोले रेल मंत्री

लंदन, प्रेट्र : रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक अभियान के तहत रेल मंत्रालय के अधिकारियों के प्रोफाइल की छानबीन की जा रही है ताकि पारदर्शिता का उदाहरण पेश किया जा सके।

तीन दिवसीय ब्रिटेन यात्रा के दौरान पीयूष गोयल ने भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और सभी राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय उच्चायोग और इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में गोयल ने कहा, 'विभिन्न विभागों में कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।' भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने से संबंधित एक सवाल के जवाब में गोयल ने कहा, 'जिन राज्यों में हम सरकार में हैं, वहां हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाई जा रही है ताकि लोगों को यह अहसास हो कि अब जानकारियां सार्वजनिक हैं और अगर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे।'

पीयूष गोयल फाइल फोटो

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का भी कामकाज संभाल रहे गोयल ने कहा, 'बीते वर्षों में हम हमेशा अच्छे समझौते नहीं कर पाए, लिहाजा उनमें से कुछ अब हमें परेशान कर रहे हैं। अब ऐसा कोई व्यापार समझौता नहीं किया जाएगा जो भारतीय हितों की कीमत पर हो।' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल में पेश आम बजट को उन्होंने सही मायनों में भारत को 2024-25 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप करार दिया।

कर्नाटक के अन्य पांच विद्रोही विधायकों की याचिका पर भी सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्नाटक के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। सत्ताधारी कांग्रेस-जदएस गठबंधन के 15 विद्रोही विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के संवैधानिक मुद्दे पर शीर्ष कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। 10 बागी विधायकों की याचिका स्वीकार की गई थी। शीर्ष कोर्ट अब और पांच बागियों की याचिका पर भी सुनवाई करेगा।

पांच विद्रोही विधायकों आनंद सिंह, के. सुधाकर, एन. नागराज, मुनिरत्न और रोशन बेग ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ के सामने सोमवार को अपनी याचिका पेश की। इन विधायकों ने लंबित याचिका में पक्ष मानने की मांग की। पहले 10 विधायकों की याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से मंगलवार तक कोई फैसला नहीं लेने के लिए कहा है। पीठ ने वकील मुकुल रोहतगी को अनुमति दे दी। 12 जुलाई को शीर्ष कोर्ट ने विधानसभा को यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। कर्नाटक में राजनीतिक गतिरोध जारी है। प्रदेश में गुरुवार को शक्ति परीक्षण होगा।

30 हजार युवाओं को ट्रेनिंग देगी दासौ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राहुल गांधी पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कसा तंज, कहा- किसी 'भाई' की जेब में नहीं गया पैसा
- राफेल बनाने वाली कंपनी दासौ और आइटीआइ नागपुर के बीच हुआ समझौता

राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी दासौ भारत में 30 हजार युवाओं को ट्रेनिंग देगी। विश्व कौशल विकास दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में दासौ के प्रतिनिधि ने इस संबंध में हुए समझौते का आदान-प्रदान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समझौते का हवाला देते हुए राफेल सौदे में दलाली के आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर तीखा तंज किया। उन्होंने कहा कि राफेल सौदे में आफसेट कांट्रैक्ट का पैसा किसी 'भाई' की जेब में नहीं गया है बल्कि युवाओं को ट्रेनिंग देने के काम आ रहा है।

सीतारमण ने कहा कि आम चुनाव के दौरान बार-बार यह आरोप लगाया जा रहा था कि राफेल सौदे में आफसेट कांट्रैक्ट का पैसा मोदी ने किसी को दे दिया है। लेकिन सच्चाई आपके सामने है। दासौ आफसेट कांट्रैक्ट का पैसा युवाओं को ट्रेनिंग देने पर खर्च कर रहा है। नागपुर स्थित आइटीआइ में दासौ युवाओं को एविएशन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग की सुविधा विकसित करने जा रहा है।

इस अवसर पर कानून और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजीटल इंडिया, मेक इंडिया, स्टार्ट अप और स्टैंड अप जैसी देश की तस्वीर बदलने वाली योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इन सभी की सफलता युवाओं के कौशल विकास पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि 2014 के पहले भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली केवल दो फैक्ट्रियां थी, जो अब बढ़कर 268 हो गई हैं। यही नहीं, भारत मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर का देश बन गया है। उन्होंने गांव-गांव में मोबाइल के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में मोबाइल रिपेयरिंग के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देने का सुझाव दिया।

सीतारमण फाइल फोटो

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि यूजीसी कुछ ऐसे पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है, जिसमें 50 फीसद पढ़ाई के साथ-साथ 50 फीसद ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही उद्योग जगत की जरूरत को ध्यान में रखकर 150 नए पाठ्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जावान युवाओं का है और सही दिशा में उपयोग के लिए उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग की जरूरी है। कौशल विकास मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने कहा कि अभी तक तीन करोड़ युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार सालाना एक करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी में है। सरकार का युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर है।

सतर्कता

रक्षा मंत्री ने दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम करने वाली प्रणाली विकसित करने के दिए निर्देश, विशेषज्ञों की सिफारिशों की समीक्षा भी की

सैन्य प्रतिष्ठानों में दुर्घटनाएं रोकने के लिए विशेष समिति गठित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सैन्य प्रतिष्ठानों में आए दिन गोला बारूद से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और इनसे होने वाली जान-माल की हानि को कम करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसी पद्धति विकसित करने की बात कही है, जिससे इस तरह के खतरों को टाला जा सके। राजनाथ सिंह ने दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम करने वाली प्रणाली विकसित करने के निर्देश देते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के चैयरमैन डॉ जी सतीश रेड्डी और सेना के पूर्व उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कम्पोज के नेतृत्व में सेवाओं, ओएफबी, डीजीक्यूए, डीआरडीओ के सदस्यों को शामिल करके एक कार्य बल का गठन किया है। साथ ही इन विशेषज्ञों की सिफारिशों की समीक्षा भी की है।

रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सैनिकों और आम लोगों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले एक दशक में सेना के कई हथियार डिपो हादसों के शिकार हो चुके हैं। आंकड़े बताते है कि साल 2000 में भरतपुर के आयुध डिपो में भयंकर आग लगी थी और 2001 में पठानकोट और गंगानगर के आयुध डिपो में करोड़ों का गोला बारूद जलकर खाक हो गया था। इसी तरह साल 2002 में जोधपुर के आयुध डिपो में आग लगी। 2005 में सीएडी पुलगांव का आयुध डिपो तबाह हुआ। 2007 में कुंदरु के आयुध डिपो और 2010 में पानागढ़ के आयुध डिपो में आग लगी थी। यह सिलसिला आज भी जारी है, जिसके चलते कई हजार करोड़ रुपये बरबाद हुए हैं और बड़ी संख्या में सैनिकों और आम लोगों की जान भी गई है। खुद कैग भी अपनी रिपोर्ट में कुछ वक्त पहले भारतीय सेना के पास गोला-बारूद की कमी के लिए आयुध कारखाना बोर्ड को जिम्मेदार ठहरा चुका है और गोला बारुद के रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर चुका है। इसीलिए सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और कार्य बल की सिफारिशों को तेजी से लागू करने के निर्देश दे चुकी है।

राजनाथ सिंह फाइल फोटो

एएन-32 विमान अब भी उड़ने लायक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में एएन-32 विमान की दुर्घटना बेशक दुखद है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि सारे एएन-32 विमान उड़ान के लायक नहीं। उन्होंने कहा अभी 118 एएन-32 विमान पूरी तरह उड़ान भरने के लायक हैं और जरूरत के हिसाब से पहाड़ी दुर्गम इलाकों में इस विमान की जरूरत है।

रक्षामंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हाल में हुई एएन-32 विमान दुर्घटना की कोर्ट आफ इन्क्वायरी जांच चल रही है और रिपोर्ट आने पर जरूरी सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों पायलट और क्रू समेत 13 लोगों को लेकर उड़ान भरने के बाद यह विमान लापता हो गया। कई सप्ताह की व्यापक खोज के बाद भी अभी तक इसके मलबे का कुछ भी अता-पता नहीं चला है। राजनाथ सिंह ने इस विमान की उड़ान क्षमता को लेकर राज्यसभा में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 118 एएन-32 विमानों में से 55 विमानों का अपग्रेडेशन भी किया गया है। इन विमानों को पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही उड़ान की इजाजत दी जाती है। उन्होंने कहा कि जो विमान हाल में अरुणाचल में लापता होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ वह भी उड़ान भरने में पूरी तरह सक्षम था।

इन विमानों की उपयोगिता को लेकर उठाए सवालों पर रक्षामंत्री ने कहा कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों में इनकी जरूरत है, क्योंकि ये कम उंचाई पर उड़ सकते हैं। साथ ही दुर्गम पहाड़ियों में बड़े विमानों की उड़ान मुश्किल है और इसमें एएन-32 बिल्कुल मुफीद हैं। हालांकि राजनाथ ने यह बात भी स्वीकार किया कि अरुणाचल सरीखे पहाड़ी इलाकों में बीते कुछ सालों में विमान दुर्घटना के ऐसे 34 मामलों की कोर्ट आफ इन्क्वायरी जांच हुई है, जिसमें 27 की रिपोर्ट भी आ गई है और इनके आधार पर जरूरी सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी

6.3 लाख करोड़ रुपये निवेश हो सकता है अगले पांच साल में जल और साफ-सफाई के क्षेत्र में। बजट में नल से जल योजना की घोषणा के बाद इस निवेश का अनुमान जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल की एक रिपोर्ट में लगाया गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 16 जुलाई 2019

बीएड कॉलेजों में पढ़ने और पढ़ाने वालों पर रहेगी नजर

- एनसीटीई रखेगा निगाह, आदेश का पालन न करने पर रद होगी मान्यता
- हर दिन की उपस्थिति का देना होगा ब्योरा, बायोमीट्रिक मशीनें लगाने के निर्देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में जुटी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सभी संस्थानों को अब छात्रों और शिक्षकों की हर दिन की उपस्थिति का ब्योरा आनलाइन देना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने इसे लेकर सभी संस्थानों को निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी बीएड कॉलेजों और दूसरे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को एक महीने के भीतर बायोमीट्रिक मशीनें लगाने के लिए कहा है। एनसीटीई ने यह निर्देश शिक्षकों और छात्रों के नियमित संस्थान न आने की शिकायतों के बाद दिया है।

एनसीटीई ने निर्देश का पालन न करने वाले संस्थानों की मान्यता रद करने की भी हिदायत दी है। ऐसे सभी संस्थानों को एनसीटीई ही मान्यता देती है। हालांकि, इनके कामकाज को जांचने का जिम्मा उन विश्वविद्यालयों का है, जिनसे ये संबद्ध हैं। एनसीटीई सहित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं। हालांकि छात्रों को 70 फीसद से अधिक की उपस्थिति के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका भी ठीक तरीके से अनुपालन नहीं कराया जा रहा। इसमें भी संस्थानों की मिलीभगत सामने आने लगी थी।

एनसीटीई के मुताबिक, नई व्यवस्था से अब कोई भी संस्थान छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति में कोई बदलाव नहीं कर सकेगा। साथ ही किस संस्थान में कितने छात्र नियमित रूप से पढ़ने आ रहे हैं, इसका भी पता चल सकेगा। सरकार ने पहले देश भर के सभी बीएड और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का औचक सर्वे भी कराया था, जिसमें बड़ी संख्या में संस्थान एक कमरे में ही चलते मिले थे। इसके बाद ऐसे करीब 400 कॉलेजों की मान्यता रद करते हुए इन्हें बंद कराया गया था।

शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रतीकात्मक

योगी सरकार ने घर में छोटी दुकान चलाने वालों को गृहकर में दी बड़ी राहत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

योगी सरकार ने घरों में छोटी दुकान चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पांच गुना गृहकर घटाकर अब डेढ़ गुना कर दिया है। इससे बेरोजगारी की समस्या पर भी अंकुश लगाने में सरकार को सहायता मिलेगी। सोमवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में कुल 12 फैसले किए गए। राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने नगर निगम (संपत्ति कर) नियमावली, 2000 में संशोधन कर उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से संपत्ति वर्गीकरण की असमानता को दूर किया गया है। बदले नियम के तहत अधिकतम 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल की दुकानों मसलन चाय, अंडा, पान, सब्जी, ब्रेड, दूध, दर्जी, धोबी-लॉन्ड्री, फल, फोटो स्टेट, हेयर ड्रेसर आदि की दुकानों के लिए आवासीय दर से

योगी आदित्यनाथ फाइल फोटो

अब डेढ़ गुना ही कर लिया जाएगा। अभी तक यह दर पांच गुना थी। इस फैसले से प्रदेश में लाखों की संख्या में छोटे दुकानदारों को फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि नगर निगम सीमा में स्थित भवन और भूमि पर संपत्ति कर लगाए जाने का प्राविधान है। संपत्ति कर के तहत सामान्य कर (भवन कर), जल कर और जल निस्तारण कर (सीवर कर) आते हैं। यह कर भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य के आधार पर लगाए जाते हैं। कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने के लिए नगर निगमों में आवासीय भवनों के संपत्ति कर के लिए स्वनिर्धारण का विकल्प लागू किया गया।

उप्र के विकास में याद की जाएगी योगी की भूमिका : राजेश अग्रवाल

जागरण संवाददाता, हावड़ा : 'उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास के लिए गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। राज्य के विकास में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। हमने दो साल के अपने कार्यकाल में प्रदेश को आर्थिक स्तर पर सशक्त बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। वर्तमान में प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर अपेक्षाकृत मजबूत हुआ है।' यह कहना है उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल का। वह सोमवार को पश्चिम बंगाल में उत्तर हावड़ा के सलकिया स्कूल रोड स्थित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं उद्योगपति अनिल गोयल के निवास पर आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री अग्रवाल का नागरिक अभिनंदन किया गया।

दो माह बाद ही 250 करोड़ कर्ज लेने को मजबूर उत्तराखंड सरकार

- वित्तीय वर्ष के पहले महीने ही बाजार से उठाने पड़े थे 500 करोड़
- चालू वर्ष में अब तक 750 करोड़ पहुंच रहा है कर्ज का आंकड़ा

राज्य ब्यूरो, देहरादून

दो महीने ठीकठाक गुजारने के बाद उत्तराखंड सरकार फिर कर्ज के लिए बाजार में दस्तक देने को मजबूर है। वेतन-भत्ते, पेंशन, मानदेय और एरियर के बढ़ते बोझ से तात्कालिक तौर पर निजात पाने को 250 करोड़ कर्ज मंगलवार को सरकार के खाते में पहुंच जाएगा। इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 750 करोड़ रुपये हो जाएगा।

यूं तो चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के पहले महीने यानी बीते अप्रैल माह में ही सरकार को 500 करोड़ लेना पड़ा था। आमदनी कम और खर्च ज्यादा के संकट से जूझ रही राज्य सरकार के सामने हर महीने सबसे बड़ी वित्तीय समस्या कार्मिकों के वेतन-भत्ते, मानदेय भुगतान की होती है। अपने संसाधनों के बूते इस समस्या का समाधान संभव नहीं हो पा रहा है। नतीजतन छोटा राज्य हर वित्तीय वर्ष में भारी-भरकम कर्ज लेकर अपने कार्मिकों को घी पिलाने को बाध्य है। कर्ज के लिहाज से इस साल का पहला महीना भले ही झटका देने वाला रहा हो, लेकिन इसके बाद अगले दो महीने यानी मई और जून में सरकार को कर्ज लेने की नौबत नहीं आई थी। अब दूसरी तिमाही के पहले महीने जुलाई में खर्च के पहाड़ ने राज्य सरकार के आर्थिक संतुलन को डिगा दिया है।

राज्य कर्मियों की पेंशन योजना में बढ़ाई हिस्सेदारी

सरकार ने बीते माह वर्ष 2005 के बाद नियुक्त राज्य कर्मियों की अंशदायी पेंशन योजना में बतौर नियोक्ता अपनी हिस्सेदारी 10 फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद करने और राज्य कर्मचारियों राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी और सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक एरियर की केंद्र सरकार के हिस्सेदार वाली 50 फीसद राशि 67.52 करोड़ का भुगतान करने का निर्णय लिया। वहीं इसी माह की 28 तारीख को मसूरी में 11 हिमालयी राज्यों का कॉन्क्लेव भी होना है। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री व आला नौकरशाह शिरकत करेंगे। इस खर्च को भी राज्य सरकार को वहन करना है। वित्त सचिव अमित नेगी ने 250 करोड़ कर्ज लेने की पुष्टि की।

सिद्धू काम नहीं करना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं : कैप्टन

रखी बात ▶ सिद्धू ने इस्तीफा सीएम की कोठी पर भेजने की दी जानकारी

सीएम बोले-जरनैल के सौंपे काम से एक सिपाही कैसे इन्कार कर सकता है

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

पंजाब में कैबिनेट मंत्री के पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर नाटकीय घटनाक्रम सोमवार को भी जारी रहा। सिद्धू ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकारी कोठी पर भिजवा दिया, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे थे। कैप्टन ने 39 दिनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, 'सिद्धू काम नहीं करना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं।' पहले माना जा रहा था कि कैप्टन सिद्धू को एक और मौका दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तेवर ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह सिद्धू को लेकर कोई नरमी के मूड में नहीं हैं।

सिद्धू ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के सरकारी कोठी पर भेजने की जानकारी भी ट्विटर पर दी। इस्तीफा देने के बावजूद सिद्धू न तो मीडिया के सामने आए हैं और न ही उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद ही अब सिद्धू के इस्तीफे पर फैसला किया जाएगा। कैप्टन ने कहा कि जो विभाग सिद्धू को दिया गया था उन्हें उसमें काम करना चाहिए था। कैप्टन ने सवाल किया- 'जरनैल द्वारा सौंपा गया काम करने से एक सिपाही कैसे इंकार कर सकता है?' उन्होंने कहा कि यदि सरकार की कार्यवाही कारगर ढंग से चलानी है तो इसमें कुछ अनुशासन भी होना चाहिए।

नवजोत सिंह सिद्धू

कैप्टन अमरिंदर सिंह

सिद्धू के साथ मेरा कोई मतभेद नहीं : कैप्टन ने यह भी कहा, 'मेरा उसके साथ कोई मतभेद नहीं है। यदि सिद्धू को मुझसे किसी तरह की कोई समस्या है तो वही बता सकता है।' राहुल गांधी को इस्तीफा भेजने पर कैप्टन ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मंत्रिमंडल का फैसला कांग्रेस हाईकमान की सलाह से किया जाता है जिस कारण सिद्धू का पार्टी प्रधान को इस्तीफा भेजना ठीक है।

दूसरे दिन भी कोठी पर सन्नाटा, सिद्धू ने स्टाफ को भेजा छुट्टी पर

विपिन कुमार राणा, अमृतसर : नवजोत सिंह सिद्धू की कोठी पर सोमवार को भी सन्नाटा पसरा रहा। उनके दफ्तर के स्टाफ को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को देर रात सिद्धू अमृतसर से दिल्ली या फिर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनकी पत्नी डॉ. सिद्धू कोठी में ही थीं। कई बार मीडिया ने उन्हें संदेश भेजा और प्रतिक्रिया लेनी चाही, पर उन्होंने मिलने से इन्कार कर दिया। इक्का-दुक्का समर्थक ही कोठी पर पहुंचे, पर उनसे भी परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला।

हमेशा की दबाव की राजनीति : सिद्धू ने हमेशा ही दबाव की राजनीति की है। चाहे भाजपा में रहते हुए 2016 में राज्यसभा से इस्तीफा देने का मामला हो या फिर 2014 में लोकसभा टिकट न मिलने की वजह से 'कोपभवन' में जाने का। 17 जुलाई 2009 में राजिंदर मोहन सिंह छीना को अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बनाने के बाद भी वह अज्ञातवास पर चले गए थे।

कलराज हिमाचल और देवव्रत गुजरात के राज्यपाल बने

जेएनएन, नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वहां के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को गुजरात भेजा गया है।

नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कलराज मंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता कलराज को राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा लंबे समय चल रही थी। हिमाचल प्रदेश में कलराज को आचार्य देवव्रत की जगह नियुक्त किया गया है और देवव्रत को गुजरात का राज्यपाल बनाया गया है। गुजरात में वह ओपी कोहली की जगह लेंगे। कोहली सोमवार को इस पद से मुक्त हो रहे हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार में कलराज को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया था। हालांकि, उन्होंने 75 वर्ष की उम्र पार करने पर 2017 में ही मंत्री पद छोड़ने का फैसला ले लिया था। उस समय संसद में वह उत्तर प्रदेश के देवरिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रत्याशी नहीं बनने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि वह पार्टी की जवाबदेही संभालना चाहेंगे।

छग में सदन से सड़क तक अंडे पर उबाल

- बढ़ा विवाद-सदन में विपक्ष ने किया हंगामा, सड़कों पर उतरे समाजिक संगठन
- स्कूलों में मिड डे मील में अंडा देने की योजना बनी सरकार के गले की फांस

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में मिड डे मील में अंडा परोसने की योजना पर शुरू हुई सियासत और तेज हो गई है। सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा व जकांछ के विधायकों ने अंडे पर शोरशराबा किया। इधर समाजिक संगठनों के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन कर विरोध जताया।

तीन दर्जन से अधिक संगठनों और कांग्रेस विधायकों की मांग पर सरकार ने सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में अंडे को शामिल किया गया, ताकि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई तेज हो सके। जिला खनिज न्यास की राशि से अंडे की खरीद की योजना बनी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ ऐसे सामाजिक संगठन सड़क पर उतर गए, जिनमें मांसाहार प्रतिबंधित है। सरकार की तरफ से ऐसे संगठनों के मान-मनौव्वल की कोशिश भी हुई, लेकिन वे अंडे की जगह कुपोषण खत्म करने के लिए कोई शाकाहारी चीज देने की मांग कर रहे हैं।

जैसे ही कुछ संगठनों का विरोध शुरू हुआ, तो विपक्षी दल भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी सरकार के फैसले की खिलाफत में उतर आए हैं। सोमवार को विधानसभा सदन में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। कांग्रेस सरकार का कहना है, न केवल कुपोषण को कम करने, बल्कि मुर्गीपालन में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी मिड डे मील में अंडे को शामिल किया जा रहा है।

सरकार का तर्क-अंडा खाना अनिवार्य नहीं किया : सरकार का कहना है कि आदेश में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा खाना अनिवार्य है। आदेश में यह है कि जो बच्चे अंडा नहीं खाना चाहते हैं, उनके लिए दूध या सोया से बनी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी।

विरोधियों का तर्क-साथ बैठकर भी नहीं खा सकते : कबीरपंथी, जैन, सनातन धर्म और गायत्री परिवार के लोगों का कहना है कि उनके समाज के बच्चे मांसाहार खाने वालों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। इन समाजों का आरोप है कि राज्य सरकार का फैसला उनके समाज के बच्चों को मांसाहारी बनाने वाला है।

क्या कर सकती है सरकार? : आदिवासी बहुल इलाकों में बच्चों को अंडा दिए जाने की मांग है, ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के फैसले को वापस नहीं लेना चाहते हैं। कुछ समाजों के विरोध को देखते हुए सरकार यह विचार कर रही है कि स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा खाने वाले बच्चों को उन बच्चों से अलग बैठाकर खाना खिलाया जाए, जो मांसाहारी नहीं हैं।

38 फीसद बच्चे कुपोषित : सरकार का कहना है कि अधिकारिक सर्वेक्षणों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 38 फीसद बच्चे कुपोषित हैं। अनुसूचित जनजाति के बच्चों में कुपोषण की दर 44 फीसद है। ग्रामीण व शहरी गरीब बच्चों में से लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है।

छग में मिड डे मील में अंडा परोसे जाने को लेकर विवाद बढ़ा। प्रतीकात्मक

मध्यप्रदेश में नहीं, लेकिन चार पड़ोसी राज्यों में दिया जा रहा

मध्यप्रदेश में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने मिड डे मिल से अंडे को हटाया था। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो उसने भी अंडा को मिड डे मिल में शामिल नहीं किया है। जिन संगठनों को अंडा देने की मांग की है, उनके मुताबिक मध्यप्रदेश को छोड़ छत्तीसगढ़ के दूसरे पड़ोसी राज्य ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत देश के 15 राज्यों के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा परोसा जा रहा है।

रजिस्ट्री अधिकारियों और बेलगाम वकीलों से सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुछ वकीलों के अनियंत्रित व्यवहार और तत्काल सुनवाई वाले मामलों की लिस्टिंग में रजिस्ट्री अधिकारियों के कथित 'घटिया काम' पर नाराजगी जताई। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने एक केस को तत्काल सुनवाई की सूची से हटाने को लेकर रजिस्ट्री के अधिकारी की खिंचाई की। जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही इस मामले को तत्काल सुनवाई की सूची में रखने का आदेश दिया था। जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'क्या चल रहा है? उसने (वकील) ने पिछले हफ्ते इस मामले का मेंशन किया था और हमने इसे नहीं हटाने का आदेश दिया था। जब आदेश पारित किया जाता है तब आपको समझ नहीं आता? किस तरह का स्टाफ है?' पीठ में जस्टिस दीपक गुप्ता भी शामिल थे। प्रधान न्यायाधीश कोर्ट के उठने से पहले वकीलों के व्यवहार पर खफा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में चैंबर आवंटन करने की मांग कर रहे वकील प्रधान न्यायाधीश के सामने एक साथ बोलने लगे थे।

असम एनआरसी पर केंद्र के 2019 के आदेश का परीक्षण करेगा कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विदेशी न्यायाधिकरण संशोधन आदेश 2019 की प्रक्रियाएं लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। बता दें कि न्यायाधिकरण पर असम एनआरसी से बाहर रह गए लोगों की अपील सुनने का जिम्मा है। शीर्ष अदालत एनआरसी को अंतिम रूप देने की कवायद की निगरानी कर रही है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा दायर याचिका का संज्ञान लिया। इसमें कहा गया है कि 2019 का आदेश उन लोगों के लिए अनुचित है, जो एनआरसी में शामिल नहीं किए जाने को चुनौती दे रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि इस आदेश से एनआरसी में शामिल होने से छूट गए लोगों की अपील का अधिकार प्रभावित होगा, क्योंकि न्यायाधिकरण ऐसे लोगों की अनुपस्थिति में भी उनकी अपील सुन सकेगा।

एसडीएम से बोले भाजपा विधायक- एमएलए से बात करने का तरीका नहीं आता है आपको

नईदुनिया, बीना (सागर)

मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना में बिजली बिल अधिक राशि के आने की शिकायत करने सोमवार को समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे भाजपा विधायक महेश राय एसडीएम पर भड़क गए। दरअसल, एसडीएम करोड़ीलाल मीना ने ज्ञापन लेने तहसीलदार प्रशांत अग्रवाल को भेजा तो विधायक समर्थक एसडीएम के चैंबर में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। विधायक ने एसडीएम से कहा कि आपकी नौकरी नई-नई है। एक एमएलए (विधायक) से बात करने का तरीका नहीं आता है आपको। इधर, एसडीएम ने ऐसी कोई बहस होने से इन्कार किया है।

विधायक राय एसडीएम को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन तहसीलदार के आने के बाद बात बिगड़ी। विधायक ने ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम को बुलाया, लेकिन वह अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले। बाद में एसडीएम ने विधायक को अपने दफ्तर में ही बुलाया। विधायक समर्थकों के साथ एसडीएम से बात करने पहुंचे। विधायक ने एसडीएम से बाहर आकर लोगों की शिकायत सुनने व ज्ञापन लेने के लिए कहा। इस पर एसडीएम ने इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञापन लेने के लिए तहसीलदार को भेजा था, आपने उन्हें ज्ञापन क्यों नहीं दिया। एसडीएम ने विधायक से कहा कि आप यहीं ज्ञापन दे जाओ। उन्होंने दफ्तर के बाहर जाने से इन्कार कर दिया। विधायक ने कहा कि एसडीएम के रवैये की शिकायत कलेक्टर से कर दी है और विधानसभा में भी विशेषाधिकार हनन का मामला रखा जाएगा।

'ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो भाजपा के तीन टुकड़े कर देंगे'

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने गोवा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के साथ ही कमलनाथ सरकार के गिरने के खतरे के सवाल पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार को हटाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो भाजपा के तीन टुकड़े कर देंगे। मंत्री आरिफ अकील ने सीहोर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उक्त टिप्पणी की। मप्र के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि डॉग स्क्वॉड के तबादले पर सवाल खड़े करने वाले नेताओं की सोच कुत्ते जैसी हो गई है। वर्मा सोमवार को झाबुआ दौरे पर थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए वर्मा ने कहा कि बार-बार डॉग्स के तबादलों पर बयानबाजी की जा रही है। ऐसा कर रहे नेताओं की सोच कुत्ते जैसी हो गई है।

बड़े युद्धपोत डुबोने वाले भारी तारपीडो से लैस होगी नौसेना

- दो हजार करोड़ के सौदे के लिए रक्षा मंत्रालय ने मांगे टेंडर
- 100 बड़े व भारी तारपीडो खरीद जाने की तैयारी

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय नौसेना की हमले की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने दो हजार करोड़ रुपये मूल्य के 100 बड़े व भारी तारपीडो खरीद के सिलसिले में टेंडर मांगे हैं। ये तारपीडो मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बन रहीं छह स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियों में लगाए जाएंगे। पानी के भीतर तारपीडो से हमला करके ही दुश्मन के युद्धपोत डुबोए जाते हैं।

मूल रूप में फ्रांसीसी स्कॉर्पीन पनडुब्बी मझगांव में कलवरी क्लास पनडुब्बी के नाम से बनाई जा रही हैं। इनमें से पहली पनडुब्बी तैयार होकर नौसेना में शामिल हो चुकी है। नौसेना को बड़ी संख्या में ज्यादा वजन वाले बड़े तारपीडो की जरूरत है। लेकिन तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए 100 तारपीडो की खरीद विदेशी कंपनी से की जाएगी। लेकिन इसके बाद इसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही बनाने का इंतजाम किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) उन्नत तारपीडो के विकास के सिलसिले में कार्य शुरू कर चुका है।

बढ़ेगी ताकत

उन्नत किस्म का तारपीडो वजन में हल्का लेकिन मार करने में ज्यादा घातक होगा। फिलहाल फ्रांस, स्वीडन, रूस और जर्मनी की कंपनियां ज्यादा वजन वाले तारपीडो बना रही हैं। इन्हीं से भारत खरीद करेगा। पूर्व में इटली की फर्म वास के ब्लैकशार्क तारपीडो खरीद के लिए चुने गए थे लेकिन वीवीआइपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में शामिल कंपनी फिनमेकेनिका की कंपनी में हिस्सेदारी की वजह से सौदा रद कर दिया गया था।

अहम पड़ाव

पांच वर्ष में 30 हजार आम लोगों से मिले राज्यपाल राम नाईक, आम जनता से प्राप्त किए 2 .19 लाख पत्र

उत्तर प्रदेश के राजभवन के द्वार खुले तो लगीं कतारें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

पांच साल पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की शपथ लेने के बाद राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोलने का एलान करने वाले राम नाईक अपने कहे पर खरे उतरते दिख रहे हैं। सूबे के प्रथम नागरिक के तौर पर राज्यपाल ने सोमवार को जब अपने पांचवें वर्ष के कार्यवृत्त 'राजभवन में राम नाईक' को जारी किया तो उसमें दर्ज आंकड़े उनके संकल्प की गवाही दे रहे थे। पांच वर्षों के दौरान उन्होंने राजभवन में 30,225 आम लोगों से मुलाकातें कीं और उनके 2.19 लाख पत्र लेकर आगे बढ़ाया।

नाईक ने बताया कि उनकी कोशिश रही कि संबंधित पत्रों का निस्तारण कर चिट्ठी भेजने वाले को भी उससे अवगत कराया जाए। उन्होंने बताया कि पांच वर्षों में उन्होंने राष्ट्रपति को 119 और प्रधानमंत्री को 199 पत्र लिखे। इस अवधि में उनकी ओर से उप राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य प्रदेशों के राज्यपालों को भी 551 पत्र लिखे गए। राज्यपाल ने पहले दो वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री को 518 तथा चौथे व पांचवें वर्षों के दौरान 844 पत्र लिखे। वहीं तीसरे वर्ष यानी 2016-17 में उन्होंने मुख्यमंत्री को 326 पत्र लिखे। पहले दो वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, जबकि तीसरे वर्ष के दौरान मार्च 2017 में सरकार बदल गई और योगी आदित्यनाथ सूबे के नए मुख्यमंत्री बने। विगत पांच वर्षों के दौरान उन्होंने राज्य सरकार के मंत्रियों को 634 पत्र लिखे।

लखनऊ में सोमवार को राजभवन में पत्रकारों से बात करते राज्यपाल राम नाईक। जागरण

जब पत्नी ने रखी शर्त : राज्यपाल ने बताया कि जीवन के अच्छे-बुरे दिनों में उन्हें अपनी पत्नी कुंदा नाईक का भरपूर सहयोग मिला। युवावस्था में मुंबई में एक अच्छी कंपनी में नौकरी के दौरान उन्होंने जनसंघ को अपनी सेवाएं देने की सोची। पत्नी से जब उन्होंने अपनी इच्छा जताई तो उन्होंने कहा कि 'मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राजनीति में अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए मैं नौकरी करूंगी।' इसके बाद उनकी पत्नी ने बीएड कोर्स किया और फिर नौकरी।

नाईक ने गिनाई विशेष उपलब्धियां

- राज्यपाल की अध्यक्षता में कुंभ के लिए गठित समिति के सुझाव पर इलाहाबाद का नामकरण प्रयागराज होना। कुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन जिसमें राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों पहली बार आए। अक्षयवट और सरस्वती कूप जनता के दर्शनार्थ खोले गए।
- किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राष्ट्रपति की ओर से गठित राज्यपालों की समिति के अध्यक्ष नामित। समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट।
- उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन शुरू होना। उनके कहने पर ही 2018 में पहली बार 24 जनवरी को सरकारी स्तर से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया।
- वाराणसी, आगरा, मेरठ और लखनऊ में मराठी गीत रामायण का आयोजन।
- केंद्र में मत्स्य संवर्धन मंत्रालय का गठन।
- संस्मरणों पर आधारित पुस्तक 'चरैवेति! चरैवेति!!' के संस्करण 11 भाषाओं में उपलब्ध। पुस्तक हिंदी, मराठी व अंग्रेजी भाषाओं में ब्रेल लिपि में नेत्रहीनों के लिए भी सुलभ।

गुरु पूर्णिमा पर निशंक ने छेड़ा 'सेल्फी विद गुरु' अभियान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं का सम्मान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 'सेल्फी विद गुरु' नाम से सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की है। इस अभियान के तहत लोगों को अपने गुरु के साथ सेल्फी लेकर हैशटैग 'सेल्फी विद गुरु' लिखते हुए ट्वीट करना है।

मंत्री रमेश पोखरियाल ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के साथ अपनी एक सेल्फी ट्वीट की और कहा कि बाल्यकाल के गुरुओं का मेरे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन अब उनकी केवल स्मृतियां ही शेष हैं। हमने अपने जीवन में हमेशा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श और गुरु माना है। उन्होंने लोगों से इस मुहिम में शामिल होने व जिनके साथ सेल्फी ले रहे हैं उनका अपने जीवन में महत्व के उल्लेख का भी आह्वान किया।

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सक्सेना से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपित से सरकारी गवाह बने दुबई निवासी व्यापारी राजीव सक्सेना को अदालत ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने सक्सेना की जमानत रद करने के लिए राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में अर्जी दायर की है। उसने कहा कि राजीव सक्सेना ने जांच में सहयोग नहीं किया है। राजीव को दुबई से लाया गया था और कई दिन तक रिमांड पर रखने के बाद 31 जनवरी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसके बाद सक्सेना ने सरकारी गवाह बनने की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था। ईडी का आरोप है कि सक्सेना ने गौतम खेतान के साथ साठगांठ कर अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में 12 वीवीआइपी हेलिकॉप्टरों के करार को प्रभावित करने के लिए विभिन्न राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और वायुसेना अधिकारियों को भुगतान करने के उद्देश्य से अवैध धन के शोधन के लिए वैश्विक कारपोरेट ढांचा उपलब्ध कराया था।

2016 में जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी की 2653 घटनाएं हुई थीं, जबकि 2016 के छह महीनों में ऐसी केवल 40 घटनाएं ही हुईं। यह जानकारी गृहमंत्रालय ने एक रिपोर्ट में दी गई है।

सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मिलेगी पांच लाख की क्षतिपूर्ति

बदलेंगे नियम ▶ दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए संशोधन विधेयक पेश

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दो साल कारावास और 15,000 रुपये का लगेगा जुर्माना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अब तक की नाकाम कवायदों के बीच केंद्र ने सोमवार को लोकसभा में 'मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) बिल, 2019' पेश किया। इस विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वालों के हितों की रक्षा करने के उपायों के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सिर्फ चार साल से अधिक उम्र के बच्चों और व्यक्तियों को मोटरसाइकिल सहित दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट पहनने की आवश्यकता होगी।

सरकार ने जब यह विधेयक सदन में पेश करने का प्रस्ताव किया तो विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया। इस पर सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहकर विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को खारिज किया कि केंद्र ने किसी राज्य के अधिकार नहीं छीने हैं। उन्होंने 18 राज्यों के साथ परामर्श के बाद इस विधेयक का मसौदा तैयार किया है। उन्होंने सदन से विधेयक को पारित करने का आग्रह किया ताकि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जानें बचाई जा सकें।

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में भी यह विधेयक लेकर आई थी जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया था, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो सका था। यही वजह है कि सरकार यह विधेयक फिर लेकर आई है। नए विधेयक के तहत सड़क दुर्घटना में मौत की स्थिति में वाहन स्वामी या बीमा कंपनी को पांच लाख रुपये तथा घायल होने पर ढाई लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देनी होगी। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि शराब पीकर नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना और दो साल के कारावास की सजा मिलेगी।

नई दिल्ली में सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 'मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) बिल, 2019' से जुड़ी विपक्ष की आशंकाओं को खारिज किया (टीवी ग्रैब)। एएनआइ

विधेयक में लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। खास बात यह है कि इस विधेयक के कानून का रूप लेने पर दिव्यांगों को भी लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के इरादे से विधेयक में परमिट से संबंधित प्रावधानों को उदार बनाया गया है। साथ ही दुर्घटना में घायलों को बचाने के लिए सामने आने वाले राहगीरों के हितों के संरक्षण से संबंधित भी प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाता है और इस दौरान घायल की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति पर किसी भी तरह का मामला नहीं चलेगा। रोड सेफ्टी की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को स्पीड कैमरा, सीसीटीवी, स्पीड गन और बॉडी बियरेबल कैमरा जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

विपक्षी सदस्यों की आशंका दूर करने की कोशिश करते हुए गडकरी ने कहा कि मेरे विभाग की यह विफलता है कि बीते पांच साल में यह विधेयक पारित नहीं हुआ और दुर्घटनाओं में मात्र तीन से चार प्रतिशत की कमी आई है, जबकि समान अवधि में तमिलनाडु में दुर्घटनाओं में 15 प्रतिशत की कमी आई है।

तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसके कुछ प्रावधान राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण हैं और इससे उनकी शक्तियां छिन जाएंगी। तृणमूल की एक अन्य सदस्य मोहुआ मित्रा ने भी विधेयक के प्रावधानों पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद महीने भर के भीतर लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि को बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है जो उचित नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वह विधेयक का पूरी तरह विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि इसके कुछ प्रावधानों का ही विरोध कर रहे हैं।

रोके जा सकते हैं हादसे

सड़क हादसों का सहज पूर्वानुमान संभव है, इसलिए किसी अन्य समस्या की तुलना में इस पर रोक लगाना ज्यादा आसान है। कई देशों ने इसी मंत्र पर अमल करते हुए सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार वजहों को खत्म किया। आज उनकी सड़कें सुरक्षित हैं। हादसों में हताहतों के लिहाज से हम शीर्ष पर हैं। लिहाजा इससे निपटने के लिए हमें उतनी ही शिद्दत से जुड़ना होगा। इन वजहों को प्रभावकारी तरीके से खत्म करना होगा।

तेज रफ्तार

हादसों के इजाफे में इस कारक की बड़ी हिस्सेदारी है। सभी देशों में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। अपेक्षाकृत युवा लोग तेज रफ्तार वाहन चलाने के साथ नियम-कानूनों को भी ताक पर रख देते हैं। लिहाजा कई बार दूसरे वाहनों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। अगर यातायात की औसत रफ्तार को एक किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो गंभीर रूप से होने वाले हादसे 4-5 फीसद कम हो जाते हैं। हर क्षेत्र, सड़क आदि के लिए विशेष रफ्तार सीमा तय की जानी चाहिए और उसका सख्ती से अनुपालन कराया जाना चाहिए।

शराब पीकर वाहन चलाना

रक्त में शून्य स्तर से ऊपर अल्कोहल की मात्रा होने से किसी 30 साल से अधिक आयु वाले की तुलना में किशोर चालक द्वारा हादसे की आशंका पांच गुना अधिक हो जाती है। लिहाजा कम उम्र और गैर अनुभवी चालकों के लिए अल्कोहल सीमा के नए मानदंड लागू करके हादसों में 4-24 फीसद तक कमी लाई जा सकती है।

सीट बेल्ट

सड़क सुरक्षा को लेकर खोजे गए अब तक सभी उपकरणों में सीट बेल्ट ने सर्वाधिक जानें बचाई हैं। अकेले सीट बेल्ट के इस्तेमाल से हादसों में होने वाली सभी तरीके की चोटों को 40-50 फीसद कम किया जा सकता है जबकि गंभीर चोटों को 40-60 फीसद तक रोका जा सकता है।

बच्चों के लिए खास उपकरण

कार में शिशु और बच्चों की खास सीट एवं बूस्टर सीट हादसों के वक्त उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावकारी साबित होती हैं। ऐसे उपकरण हादसे में काल-कवलित होने वाले शिशुओं की संख्या में 71 फीसद कमी ला सकते हैं और बच्चों के मामले में 54 फीसद कमी लाने में सहायक हैं।

हेलमेट

दोपहिया वाहन से हादसों के दौरान सिर में सभी तरीके की चोटों से बचने का यह सबसे प्रभावी उपाय है। हेलमेट दुर्घटना के समय सिर की चोटों के जोखिम को 70% कम करता है।

आपातकालीन सेवाएं

स्वास्थ्य, अग्निशमन और पुलिस जैसी सेवाओं की कमी के चलते सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल लोग कई बार अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं।

सड़क डिजायन और आधारभूत संरचना

इसके तहत विभिन्न प्रकार के यातायात को अलग रखने की प्रणाली होनी चाहिए। पैदलयात्रियों और साइकिल सवारों की अलग लेन होनी चाहिए। फुटपाथ और सड़क पार करने की संरचनाएं होनी चाहिए। रफ्तार कम करने के लिए आवश्यकतानुसार स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था हो। काफी किफायती ये तकनीकें हादसों को कम करने में अहम साबित हो सकती हैं।

अब सैन्य अदालत करेगी रवींद्र मामले की सुनवाई

जागरण संवाददाता, नारनौल : देश की खुफिया जानकारी विदेशी एजेंट को भेजने के आरोपित सेना के जवान रवींद्र कुमार यादव को दो दिन की न्यायिक हिरासत के बाद सोमवार को सीजेएम प्रवेश सिंघल की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपित पक्ष के वकील की दलील पर केस को सेना की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। अब सेना की अदालत सुनवाई करेगी। औपचारिकताओं के बाद आरोपित को उसकी यूनिट को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

सोमवार को अदालत में पेशी के दौरान रवींद्र नजर झुकाए खड़ा था। परिजन भी अदालत कक्ष के बाहर खड़े थे। आरोपित के वकील ने अदालत में दलील दी कि रवींद्र यादव पुत्र रतन सिंह के केस की सुनवाई शहर कोर्ट की बजाए सेना की अदालत करे। सजा का फैसला भी वही करे। वकील ने कहा कि यह भारतीय सेना के अधिकारी ही तय कर सकते हैं कि रवींद्र ने फेसबुक व वाट्सएप पर चैट की और जो जानकारी दी, वह कितनी अहम थी। एक जवान के पास इस बारे में कितनी जानकारी होती है। वकील ने कहा कि लोकल पुलिस ऐसी जांच करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद अदालत ने आरोपित को और केस की फाइल को यूनिट कमांडिंग अफसर के हवाले करने के आदेश दिए। अब इस मामले की जांच को आर्मी के अधिकारी आगे बढ़ाएंगे। नारनौल पुलिस जल्द ही कोर्ट के आदेश पर ट्रांजेक्शन वारंट हासिल करके आरोपित और फाइल को पांच कुमाऊं रेजिमेंट अरुणाचल प्रदेश इसकी यूनिट के अधिकारियों के सुपुर्द करेगी।

महिला एजेंट ने मुझे जाल में फंसाया : मुझे पता नहीं था कि इस तरह की जानकारी शेयर करनी चाहिए या नहीं। पांच हजार तो मुझे बर्थ डे गिफ्ट पर कपड़े खरीदने के लिए दिए थे। वह बातों-बातों में वीडियो कॉलिंग करवा लेती थी। वह अपने को सेना में कैप्टन बताती थी। ये बातें हनीट्रैप में फंसे रवींद्र ने कोर्ट में पेशी पर जाते हुए पत्रकार से हुई बातचीत में कही। उसने बताया कि वह महिला के झांसे में फंस गया।

कोर्ट ने दिया साक्षी-अजितेश को सुरक्षा देने का निर्देश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

प्रेम विवाद से चर्चा में आए बरेली के बिथरी से भाजपा विधायक राजेश मिश्र उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा व उसके पति अजितेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। साथ ही इनके वैवाहिक जीवन में किसी के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याची के परिवार के लोगों को कोई भी व्यक्ति हानि न पहुंचाने पाये। याचिकाकर्ताओं के विवाह के मामले में कहा कि यह याचिका का नहीं, साक्ष्य का विषय है, जिसे किसी वैधानिक कार्यवाही में तय किया जा सकता है। कोर्ट ने याचीगण को दो माह के भीतर विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया और कहा कि रजिस्ट्रेशन न होने पर कोर्ट के संरक्षण का आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा।

कोर्ट ने राजेश मिश्र उर्फ पप्पू भरतौल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने साक्षी मिश्रा व अजितेश की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा

प्रयागराज में बमरौली एयरपोर्ट पर बैठे अजितेश व साक्षी। (वीडियो ग्रैब)

कि दोनों बालिग हैं, वह अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। लता सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि दो बालिग लोगों के अंतरजातीय या अंतर धार्मिक विवाह की स्थिति में पुलिस प्रेमी युगल की सुरक्षा करे। कोर्ट ने कई अन्य फैसलों का हवाला दिया। साथ ही याची अधिवक्ता व अजितेश के परिवार को धमकी देने के मामले में पुलिस को सुरक्षा करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि विधायक राजेश मिश्र की बेटी साक्षी ने अनुसूचित जाति के लड़के अजितेश से शादी की है। अपने पिता राजेश मिश्र और उनके दोस्त राजीव राणा से जान को खतरा बताया है। इसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

अजितेश से हुई मारपीट : याचिका की सुनवाई पूरी होने के बाद साक्षी व अजितेश कोर्ट से बाहर निकले तो बरामदे में उन्हें इस प्रकरण को मीडिया में फैलाने का विरोध झेलना पड़ा। लोगों में इस बात का गुस्सा था कि प्रेम प्रसंग को लेकर मां-बाप की सोशल मीडिया व अन्य मंचों पर ज्यादा ही फजीहत कराई जा रही है। इसे लेकर उनसे मारपीट की गई, लेकिन साथ आए पुलिस वाले किसी तरह बचाकर बगल के न्याय कक्ष में घुस गए। सूचना पर कोर्ट अफसर वहां पहुंचे। उन्होंने पुलिस बल बुलाकर दोनों को किसी तरह रजिस्ट्रार जनरल के चैंबर तक पहुंचाया। वहां पुलिस, महिला पुलिस व सीआरपीएफ के कड़े सुरक्षा में दो-तीन घंटे रखने के बाद परिसर से बाहर निकालकर एयरपोर्ट ले जाया गया।

'यह सिर्फ प्रेम विवाह है या सियासी साजिश'

जागरण संवाददाता, बरेली : अनुसूचित जाति के युवक अजितेश से प्रेम-विवाह रचाने पर साक्षी के पिता विधायक राजेश मिश्र उर्फ पप्पू भरतौल पहले ही कह चुके थे कि पूरे प्रकरण के पीछे राजनीतिक साजिश है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया। पूरे दिन चर्चा रही कि उन्होंने प्रमुख सचिव से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है। ऐसा होने पर बरेली प्रशासन को रिपोर्ट बनाकर भेजनी होगी। हालांकि स्थानीय अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। भाजपा से जुड़े सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री ने पूछा है कि क्या यह सिर्फ प्रेम विवाह है या फिर कोई सियासी साजिश। इस मामले की रिपोर्ट भेजने से पहले अफसर विधायक राजेश मिश्र का पक्ष भी जानेंगे। हालांकि वह पहले ही कह चुके हैं कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है।

प्रेम विवाह करने वाली दीक्षा के परिजन बोले, अब अपनी सुरक्षा वह खुद करे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की तैयारी में पुलिस
- शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और अन्य साक्ष्य मांगेगी पुलिस

बरेली के भाजपा विधायक की बेटी साक्षी का मामला सुर्खियों में आने के बाद प्रयागराज की दीक्षा के मामले में पुलिस फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। पूर्व उप महापौर की पोती दीक्षा अग्रवाल ने गैर बिरादरी के ऋतुराज सिंह से शादी कर घर वालों पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया है। उसके घर वालों ने ऋतुराज सिंह के खिलाफ अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने दीक्षा का बयान दर्ज कराने की तैयारी में है। इधर, सोमवार को पूर्व उप महापौर मुरारी लाल का कहना है कि दीक्षा ने अपनी मर्जी से शादी की है। अब अपनी सुरक्षा वह खुद करे।

सिविल लाइंस के रहने वाले पूर्व उप महापौर मुरारी लाल अग्रवाल के बेटे पवन अग्रवाल की बेटी दीक्षा पांच जुलाई की सुबह लापता हो गई थी। 13 जुलाई को घर वालों ने मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी ऋतुराज सिंह, उसके पिता बाल कृष्ण राजपूत और मां राजू देवी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद दीक्षा ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर आरोप लगाया कि शादी के कारण घर वाले उसे धमकी दे रहे हैं। चूंकि उसने भोपाल में शादी की है। ऐसे में उसके शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सिविल लाइंस पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दीक्षा से संपर्क कर पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी। फिर मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया जाएगा।

शादी का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ, मंदिर में शादी के प्रमाण आदि मांगे जाएंगे। पुलिस का कहना है कि वह बालिग है, ऐसे में अपहरण का मामला नहीं बनता। वह जिसके साथ चाहे रह सकती है।

दीक्षा के नाम कई करोड़ की संपत्ति, हो सकती है अनहोनी : घर वालों ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया है कि दीक्षा के नाम कई करोड़ की संपत्ति है, वह तीस लाख के जेवर और दो लाख नकद ले गई है। संपत्ति के लालच में उसके साथ अनहोनी हो सकती है। संपत्ति के मामले पर परिवार के लोगों ने कहा कि आगे देखा जाएगा कि दीक्षा के नाम की गई संपत्ति का क्या किया जाए।

ऋतुराज-दीक्षा की मुलाकात : दीक्षा इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। भोपाल के रहने वाले ऋतुराज सिंह से उसकी मुलाकात महाराष्ट्र के कल्याण स्थित एक आश्रम में हुई थी। वहां से वह पांच जुलाई को लापता हो गई। बाद में पता चला दोनों ने भोपाल में शादी कर ली।

चप्पल पहनकर घर के सामने से निकलने पर मां-बेटी को पीटा

नईदुनिया, राजगढ़ : चप्पल पहनकर घर के सामने से निकलने पर अनुसूचित जाति की मां-बेटी के साथ सवर्ण वर्ग के लोगों ने मारपीट की। दूसरी ओर अनुसूचित जाति के लोगों ने भी एक सवर्ण महिला को पीट दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का है।

थाना प्रभारी जेबी राय के अनुसार, घटना ग्राम कोलूखेड़ी के कांगनीपुरा की है। अनुसूचित जाति वर्ग की धापूबाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि है कि वह बेटी टमाबाई के साथ जा रही थी, तभी घर के सामने से चप्पल पहनकर निकलने पर अयोध्याबाई पत्नी कुमेर सिंह, ममताबाई पुत्री कुमेर सिंह, नारायण सिंह पुत्र देवीलाल और मांगीलाल पुत्र कुमेर सिंह सौंधिया ने अपशब्द कहते हुए मारपीट की। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद रविवार को धापूबाई की रिपोर्ट पर उक्त चारों आरोपितों के खिलाफ मारपीट के साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं, दूसरे पक्ष की शिकायत पर धापूबाई व उसकी बेटी पर भी मारपीट का मामला दर्ज किया गया है।

आजम खां के विधायक बेटे समेत तीन के खिलाफ केस

जागरण संवाददाता, रामपुर

- डीसीबी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, मीडिया प्रभारी के घर भी दी दबिश

मुकदमा पूरी तरह से फर्जी है। कोई धमकी नहीं दी गई है। पुलिस झूठे मुकदमे दर्ज कर परेशान कर रही है।

-अब्दुल्ला आजम खां, विधायक, स्वार

पुलिस ने अब सांसद आजम खां के बेटे व स्वार विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू और जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम भी शामिल हैं। सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया प्रभारी के घर भी पुलिस ने दी दबिश दी।

कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल लाला ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें कहा है कि वह सांसद आजम खां के गलत कामों का विरोध करते रहे हैं। आठ जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से विधायक अब्दुल्ला आजम, सांसद आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू और डीसीबी के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम उन्हें जहां-तहां रास्ते में निकलते हुए धमकी दे रहे हैं। उनके समर्थक सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। पुलिस ने जान से मारने की धमकी और आइटी एक्ट समेत तीन संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष सलीम कासिम को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। सलीम कासिम के बेटे फैसल का कहना है कि उनके घर पुलिस 10 गाड़ियों के साथ पहुंची और उनके पिता को गिरफ्तार कर ले गई। पुलिस ने शानू के घर भी छापेमारी की, लेकिन वह हाथ नहीं लग सके। गंज कोतवाली प्रभारी नरेंद्र त्यागी ने बताया कि एक आरोपित सलीम कासिम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

सारधा चिटफंड घोटाला मामले में कल से रोज होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, कोलकाता : कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी की रोक संबंधित याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक रोज दोपहर दो बजे इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बता दें कि हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें राजीव कुमार ने गिरफ्तारी से राहत दिलाने की मांग की है। सीबीआइ बहुचर्चित सारधा चिटफंड घोटाला मामले में राजीव की संलिप्तता की जांच कर रही है।

हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक की समय सीमा को 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था। आरोप है कि घोटाले की जांच के दौरान कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त ने दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और राजीव कुमार को सीबीआइ के सामने पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआइ ने राजीव कुमार से शिलांग में पूछताछ की थी।

अब राजस्थान में न्यायाधीशों को नहीं बोला जाएगा 'माई लॉर्ड'

जागरण संवाददाता, जयपुर

- राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला, रजिस्ट्रार ने जारी किए आदेश

सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट ने भी न्यायाधीशों को 'माई लॉर्ड' और 'लॉर्ड शिप' बोलकर संबोधित नहीं करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। यह पहली बार है, जब किसी हाई कोर्ट ने इन शब्दों के प्रयोग नहीं करने को लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया है।

राजस्थान हाई कोर्ट के जजों की पूर्ण पीठ ने सोमवार को ये फैसला दिया है। इसमें कहा गया है कि अब न्यायाधीशों के प्रति सर का संबोधन भी स्वीकार्य होगा। मुख्य न्यायाधीश एस. रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुए निर्णय को लागू करने को लेकर रजिस्ट्रार सतीश कुमार शर्मा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। शर्मा ने कहा है कि बार कौंसिल की ओर से आए प्रतिवेदन पर पूर्ण पीठ ने निर्णय लिया है, लेकिन निश्चित ही जजों को सम्मान और गरिमापूर्ण तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद माई लॉर्ड और यू आर लॉर्डशिप शब्दों से वकीलों की दूरी बनेगी।

राजस्थान हाई कोर्ट फाइल फोटो

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान छह जनवरी, 2014 को जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस एसए बोबडे की खंडनीठ ने कहा था कि हमने कब कहा है कि यह अनिवार्य है। आप हमें सिर्फ गरिमापूर्ण तरीके से संबोधित कर सकते हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट में वकील शिव सागर तिवारी ने एक जनहित याचिका दायर कर जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप से संबोधित करना गुलामी का प्रतीक बताया था।

डीआइजी पर रेलवे अधिकारी की पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप

नईदुनिया, जबलपुर : इंदौर से जबलपुर आ रही ओवरनाइट एक्सप्रेस के एसी कोच में रेलवे के प्रथम श्रेणी अधिकारी की पत्नी ने पश्चिम मध्य रेलवे के आरपीएफ (रेल सुरक्षा बल) डीआइजी विजय खातरकर (52) पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर जबलपुर जीआरपी (शासकीय रेल पुलिस) ने छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज कर लिया है।

शिकायत के मुताबिक ट्रेन के सेकंड एसी कोच में जबलपुर रेल मंडल के एक वरिष्ठ अधिकारी की 34 वर्षीय पत्नी अपनी छह वर्षीय बेटी के साथ भोपाल से जबलपुर की यात्रा कर रही थीं। उनके सामने वाली लोअर बर्थ पर आरपीएफ डीआइजी विजय खातरकर बैठे थे। सोमवार तड़के करीब चार बजे ट्रेन गाडरवारा से नरसिंहपुर के बीच पहुंची थी तभी डीआइजी ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। इससे उनकी नींद खुल गई और उन्होंने इसका विरोध किया। शोर सुनकर अन्य यात्री भी जाग गए। कुछ यात्रियों ने पीड़िता का हौसला बढ़ाया और जीआरपी थाने में शिकायत करने का सुझाव दिया।

समझौते का दबाव, मगर नहीं मानी पीड़िता : आरोप है कि पीड़ित महिला के थाने पहुंचते ही आरपीएफ और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और समझौते का दबाव बनाया जाने लगा। आरपीएफ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने माफी मांगकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता डीआइजी पर एफआइआर दर्ज कराने पर अड़ी रही। इसके बाद एफआइआर दर्ज कर ली गई। जीआरपी के मुताबिक, पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की वारदात उस वक्त हुई, जब ट्रेन गाडरवारा से नरसिंहपुर आ रही थी। इस वजह से जबलपुर में जीरो पर मामला कायम कर केस डायरी गाडरवारा जीआरपी को भेजी गई है। वहीं, मामला सामने आने के बाद पमरे (पश्चिम मध्य रेलवे) के वरिष्ठ अधिकारी और आरपीएफ आइजी की बैठक हुई, लेकिन जैसे ही यह जानकारी लगी कि जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है तो सभी ने चुप्पी साध ली।

इस मामले में आरोपी विजय खातरकर का कहना है कि महिला यात्री को मुझे लेकर गलतफहमी हुई थी। सुबह तकरीबन चार बजे जब मैं उठा, उस वक्त ट्रेन में अचानक झटका लगा, जिससे मेरा हाथ उनसे टच हो गया। इसके लिए मैंने उनसे माफी भी मांगी। छेड़छाड़ जैसी कोई घटना नहीं हुई है।

मिली सफलता

एनएसआइ में बनाया ईको फ्रेंडली साबुन और डिटरजेंट, पेटेंट कराने के बाद स्वीकृति के लिए नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन भेजा

गन्ने की खोई के साबुन से दमकेंगे कपड़े

विक्सन सिकरौड़िया, कानपुर

जल्द ही आपको नहाने और कपड़े धोने के लिए ऐसा केमिकल रहित साबुन व डिटरजेंट मिलने वाला है, जो त्वचा और कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि दोनों की दमक भी बढ़ाएगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) ने गन्ने की खोई (बगास) व नारियल के तेल से प्राप्त फैटी अल्कोहल डेकेनॉल की रासायनिक क्रिया करके इसे तैयार किया है। इस फार्मूले को पेटेंट कराने के बाद नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनआरडीसी) को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इसके बाद इंडस्ट्री के साथ मिलकर साबुन-डिटरजेंट बाजार में उतारे जाएंगे।

कार्बनिक रसायन के प्रोफेसर डॉ. विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव के निर्देशन में रिसर्च फेलो अनुष्का अग्रवाल ने दो साल अनुसंधान के बाद यह जैविक साबुन व डिटरजेंट बनाया है। इसका परीक्षण एनएसआइ की प्रयोगशाला और कुछ लोगों पर भी किया जा चुका है। अनुष्का ने बताया कि गन्ने की खोई में पाए जाने वाले जायलॉन व डेकेनॉल की रासायनिक क्रिया के पहले चरण में जॉयलोज बनता है, जबकि अगले चरण में ग्लाइकोसिडिक सर्फेक्टेंट में बदल जाता है। यह डिटरजेंट बनाने का मुख्य अवयव है। इस फार्मूले से डिटरजेंट के अलावा पपीता, संतरा, गुलाब, नीम व एलोवीरा फ्लेवर के नहाने के साबुन बनाए हैं।

एनएसआइ की कार्बनिक रसायन की प्रयोगशाला में ईको फ्रेंडली साबुन के फार्मूले पर काम करती रिसर्च फेलो अनुष्का अग्रवाल। जागरण

एनएसआइ में बनाया गया साबुन। जागरण

नदियां रहेंगी स्वच्छ

एनएसआइ निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि आमतौर पर डिटरजेंट व साबुन पेट्रोलियम पदार्थों से बनाए जाते हैं। जब यही डिटरजेंट मिला पानी नाली व नालों से नदियों में पहुंचता है तो उसका जल प्रदूषित कर देता है। ईको फ्रेंडली साबुन से नदियों का प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

हाथरस में दो युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा, सांप्रदायिक तनाव

जागरण संवाददाता, हाथरस

उत्तर प्रदेश के हाथरस में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। मारपीट का बदला लेने आए दूसरे समुदाय के दो युवकों को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा। बचाने आई पुलिस को लोगों ने मारपीट कर खदेड़ दिया। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस ने दोनों युवकों को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ओर से मामला दर्ज कराया गया है। घटना से क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव है।

हाथरस स्थित गांव बोझिया के वीरेंद्र व अन्य लोगों की रविवार को नगला सक्कन निवासी गुलफान से मारपीट हो गई थी। इसकी शिकायत गुलफान ने हाथरस गेट कोतवाली में की। इसके बाद गुलफान देर रात साथियों के साथ भोला के घर पहुंच गया। यहां दोनों पक्षों में फिर से मारपीट हुई।

ग्रामीणों के एकत्रित होने पर गुलफान व उसके साथी भागने लगे, मगर भोला व उनके परिवार वालों ने भागते समय कमरुद्दीन व हमीद खां को पकड़ लिया। दोनों को ग्रामीणों ने पेड़ से बांध कर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस को हाथापाई करते हुए खदेड़ दिया। मामला दो संप्रदाय के लोगों के बीच होने के कारण पुलिस के हाथ-पांव फूल गए। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पांच लोगों को गिरफ्तार कर ग्रामीणों के कब्जे से दोनों युवकों को छुड़ाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों ओर से मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने वीरेंद्र पक्ष के पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दूसरी ओर से भोला की बहन राजमाला निवासी गांव बोझिया ने गुलफान, कमरुद्दीन, हमीद खां, राज खां, रिजवान व अलीम के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इन पर एससी-एसटी एक्ट भी लगा है। कमरुद्दीन व हमीद जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी आरोपितों की तलाश की जा रही है।

10 हजार नौकरियां सृजित की गई हैं पिछले तीन सालों में सागरमाला के तहत जारी परियोजनाओं में। यह जानकारी पोत परिवहन मंत्रालय के मंत्री मनसुख लाल मांडावीया ने राज्यसभा में दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 16 जुलाई 2019

कार्रवाई ▶ बीएसएफ के जवानों ने नापाक इरादों को पूरा नहीं होने दिया

रामगढ़ में सीमा पार कर रहा पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर

आतंकियों का गाइड होने की जताई गई है आशंका

संवाद सहयोगी, रामगढ़

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अंधेरे की आड़ में सरहद पार करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के एक घुसपैठिये को सोमवार तड़के सीमा प्रहरियों ने मार गिराया। उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है।

तड़के करीब तीन बजे सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर की एसएम पुर अग्रिम चौकी पर सीमा सुरक्षा बल की 62 बटालियन के जवानों ने अंधेरे की आड़ में सीमा पार करने की कोशिश कर रहे एक घुसपैठिये को नाइट विजय डिवाइस पर देखा। वह पाकिस्तान की असलम पोस्ट की ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसके पिलर नंबर 34 के पास आने पर जवानों ने उसे रुकने की चेतावनी दी। इसके बाद उसे सचेत करने के लिए हवा में भी गोली चलाई। बावजूद इसके घुसपैठिया आगे बढ़ने लगा। इस पर सुरक्षाबलों ने उसे मार गिराया। उसकी आयु 70 साल के करीब बताई जा रही है। जामुनी रंग का खान सूट पहने घुसपैठियेए से दस-दस रुपये की पाकिस्तानी करंसी के दो नोट व एक टॉफी मिली। अक्सर आतंकियों के दल घुसपैठ करने के लिए गाइड को आगे भेजते हैं। आशंका जताई जा रही रही है कि मारा गया घुसपैठिया आतंकियों का गाइड भी हो सकता है। उससे कोई कागजात नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान हो सके।

सीमा सुरक्षा बल के डीआइजी ओपी उपाध्याय व कमांडेंट मनोज कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। डीआइजी उपाध्याय ने कहा कि दुश्मन देश का कोई भी घुसपैठिया यदि भारतीय सरहद को पार करने की कोशिश करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। गौरतलब है कि नवंबर 2017 में इसी अग्रिम सीमा की फतवाल चौकी पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमला करने वाले तीनों आतंकी बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे।

बाद में सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठिये के शव को पुलिस के हवाले कर दिया। उप जिला अस्पताल रामगढ़ में डॉ. राज काटल के नेतृत्व में टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया गया।

हाईवे पर मिली संदिग्ध वस्तु, दो घंटे आवाजाही रही ठप

जागरण संवाददाता, राजौरी : जम्मू संभाग के जम्मू-राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजौरी जिला मुख्यालय से करीब 25 किमी दूर चिंगस और नारिया के बीच सेना की रोड ओपनिंग पार्टी (आरओपी) के जवानों को एक संदिग्ध वस्तु पड़ी मिली, जिसे उन्होंने नाकाम कर दिया। इस दौरान सोमवार को सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े 11 बजे तक वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। हाईवे पर संदिग्ध वस्तु पड़ी देख सेना के जवानों ने तुरंत पुलिस अधिकारियों के साथ अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। इस बीच दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। सूचना मिलते ही सेना और पुलिस के बम निरोधक दस्ते के जवान भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हाईवे पर पड़ी संदिग्ध वस्तु की जांच की, लेकिन कुछ स्पष्ट न होने पर उसे बारूद के साथ लगाकर उड़ा दिया।

रमानी के आरोपों से खराब हुई अकबर की छवि : वीनू संदल

जासं, नई दिल्ली : पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पूर्व मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर मानहानि के मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अकबर की तरफ से पेश गवाह वीनू संदल ने कहा कि प्रिया के आरोपों से अकबर की छवि खराब हुई। उन्हें जानने वाले कई तरह के सवाल पूछते हैं।

वीनू संदल ने अदालत को बताया कि उन्होंने 1994 से लेकर 2009 तक उस अखबार में लेख लिखे हैं, जिसमें अकबर संपादक हुआ करते थे। वह एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड से जुड़े लेख लिखती रही हैं। अखबार के किसी भी कर्मचारी ने उन्हें एमजे अकबर द्वारा प्रिया रमानी के साथ कथित तौर पर किए गए अनुचित व्यवहार के बारे में कोई संकेत नहीं दिया।

प्रिया रमानी की अधिवक्ता रेबेका जॉन द्वारा की गई जिरह में वीनू संदल के कुछ लेख के बारे में भी पूछा गया, जो मीटू अभियान के दौरान लिखे गए थे। इस पर वीनू ने कहा कि वे अलौकिक एवं असाधारण गतिविधियों के बारे में लिखती रहती हैं। सोमवार को वीनू संदल से जिरह पूरी होने के बाद मामले की सुनवाई 17 जुलाई के लिए तय की गई है। उस दिन दूसरे गवाह से जिरह होगी। अक्टूबर 2018 में तत्कालीन विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर पर मीटू अभियान के तहत कई महिला पत्रकारों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद अकबर ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर महिला पत्रकार प्रिया रमानी पर आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था।

तमिलनाडु में आतंकी संगठन बनाने की कोशिश में एनआइए ने 14 को पकड़ा

चेन्नई, प्रेट्र: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने रविवार को तमिलनाडु में आतंकी संगठन बनाने की कोशिश के आरोप में 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्हें सऊदी अरब ने भारत को सौंपा था। विशेष विमान से इन संदिग्धों को चेन्नई लाया गया और यहां के पूनामल्ली में एनआइए की विशेष अदालत में पेश किया गया। संक्षिप्त सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश सेंथूर पांडियन ने सभी आरोपियों को 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एनआइए ने आरोप लगाया कि ये लोग तमिलनाडु में अंसारुल्ला नामक आतंकी संगठन के लिए धन एकत्र कर रहे थे और इन्हें हाल ही में सऊदी अरब ने भारत को सौंपा है। एनआइए ने कहा कि उसने शनिवार को इस मामले में दो संदिग्ध आतंकियों हसन अली और हरीश मुहम्मद को गिरफ्तार किया था।

दरअसल, एनआइए ने नौ जुलाई को तीन संदिग्धों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। ये संदिग्ध आतंकी चेन्नई और नागपट्टिनम जिले के रहने वाले थे। इनसे हुई पूछताछ के आधार पर शनिवार को दोनों शहरों के चार स्थानों पर छापेमारी की गई थी और इस्लामिक देश स्थापित करने के इरादे से देशभर में आतंकी हमले की तैयारी कर रहे एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था। जांच में पता चला था कि ये भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रच रहे थे। इन दहशतगर्दों ने अंसारुल्ला नाम का आतंकी संगठन बना रखा था। छापेमारी की कार्रवाई में नौ मोबाइल, 15 सिम कार्ड, सात मेमोरी कार्ड, 3 लैपटॉप, पांच हार्ड डिस्क, छह पेन ड्राइव, दो टैबलेट और तीन सीडी और डीवीडी बरामद हुई थीं। इसके अलावा तमाम मैग्जीन्स, बैनर्स, नोटिस, पोस्टर्स और किताबें भी बरामद की गई थीं।

वीरभूम से भारी मात्रा में विस्फोटकों के साथ 443 लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- 268 कच्चा बम, 180 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 630 डेटोनेटर एवं 125 जिलेटिन की छड़े जब्त
- हाल में कई टन विस्फोटकों की बरामदगी के बाद पुलिस ने चलाया जिलाव्यापी अभियान

पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले से हाल में एक साथ कई टन विस्फोटकों की बरामदगी के बाद पुलिस ने जिलाव्यापी अभियान चलाकर 443 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार को अभियान के दौरान 443 लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं भारी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त किए गए।

पुलिस के अनुसार, पारुई, लोकपुर, सदाईपुर, कंकरतल्ला, रामपुरहाट एवं मोहम्मद बाजार थाना इलाकों में चलाए गए अभियान में 268 कच्चा बम, 180 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 630 डेटोनेटर एवं 125 जिलेटिन की छड़े जब्त किया। इसके अलावा सदाईपुर, खायरासोल, दुबराजपुर, नलहाटी, मुरराई और मरग्राम थाना क्षेत्र से छह देशी हथियार एवं सात जिंदा कारतूस बरामद किया।

10 जुलाई को पुलिस ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर 11,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 80 हजार डेटोनेटर व हजारों जिलेटिन स्टीक के साथ 113 जिंदा देशी बम, चार बंदूके व 22 राउंड कारतूस जब्त किया था। जिले से विस्फोटकों की इतनी बड़ी खेप की बरामदगी के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के भी कान खड़े हो गए थे और इसका संज्ञान लिया था।

उप्र में विहिप नेता की गोली मारकर हत्या, चौकी इंचार्ज निलंबित

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़ : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में घर से जिला मुख्यालय जा रहे विश्व हिंदू परिषद (विहिप) नेता एवं अधिवक्ता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है।

प्रतापगढ़ स्थित महेशगंज क्षेत्र के कलिकापुर गांव निवासी अधिवक्ता ओम मिश्र (35) विश्व हिंदू परिषद कुंडा प्रखंड के जिलाध्यक्ष थे। वह सोमवार सुबह बाइक से जिला कचहरी के लिए निकले। लगभग 10.45 बजे सोनपुर गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास पीछे से आए मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने उनके सिर में तीन गोली मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। घर वाले मुख्यमंत्री के आने तक शव का पोस्टमार्टम न कराने पर अड़े रहे। डीआइजी कवींद्र प्रताप सिंह ने परिवार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। ओम के भाई प्रणव ने हिस्ट्रीशीटर पर हत्या कराने का आरोप लगाया। एसपी ने बताया कि जिस बदमाश पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, वह आजमगढ़ जेल में बंद है। घटना के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर वकीलों ने चक्काजाम भी किया।

1.93 लाख श्रद्धालु कर चुके बाबा अमरनाथ के दर्शन

राज्य ब्यूरो, जम्मू

बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह बना हुआ है। अब तक 193545 श्रद्धालु पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के 15वें दिन 10833 श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए। सोमवार को आधार शिविर यात्री निवास भगवती नगर जम्मू से 5210 श्रद्धालुओं का जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ।

रवाना हुए जत्थे में 3711 पुरुष, 1386 महिलाएं, 19 बच्चे और 94 साधु शामिल थे, जो 222 वाहनों पर सवार होकर यात्रा पर गए। एक जुलाई से शुरू हुई यात्रा 15 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन संपन्न होगी। यात्रा के लिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अधिकतर श्रद्धालु जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर में आए बिना सीधे पहलगाम और बालटाल पहुंच कर यात्रा पर जा रहे हैं।

मौसम की मेहरबानी श्रद्धालुओं के उत्साह को दोगुना कर रही है। राज्य के प्रवेश द्वार लखनपुर से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और पहलगाम, बालटाल व यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध और पर्याप्त सुविधाओं ने श्रद्धालुओं के मनोबल को बढ़ा दिया है। यात्रा में अभी एक महीने का समय शेष है। ऐसे में यात्रा का आंकड़ा तीन लाख पार करने की संभावना है।

देशभर से श्री बाबा अमरनाथ यात्रा पर आए साधु जम्मू के पुरानी मंडी स्थित राम मंदिर में बम-बम भोले के जयघोष करते हुए। जागरण

वनरक्षक को आत्महत्या के लिए किया गया था विवश

राज्य ब्यूरो, शिमला

हिमाचल के बहुचर्चित वनरक्षक होशियार सिंह की मौत मामले में सीबीआइ ने जांच पूरी कर ली है। जांच में पाया गया है कि करसोग की सेरी कतांडा बीट में तैनात होशियार सिंह को आत्महत्या के लिए विवश किया गया था। इसका मुख्य आरोप तत्कालीन डिप्टी रेंजर तेज राम पर लगा है। सूत्रों के अनुसार सीबीआइ ने चार्जशीट तैयार कर ली है जिसे कभी भी कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। मुख्य आरोपित तेज राम को बनाया गया है। अब उन पर कोर्ट में मुकद्दमा चलेगा।

इस मामले में हत्या होने के पुख्ता सुबूत नहीं मिल पाए हैं। जांच एजेंसी इस मामले में पहले क्लोजर रिपोर्ट तैयार करने के पक्ष में थी। लेकिन कानूनी सलाह लेने और निदेशालय के निर्देश पर जांच रिपोर्ट की दिशा बदली। मामले की तफ्तीश करने में करीब पौने दो साल लग गए। अब वन कटान से संबंधित दो और मामलों की जांच भी जन्द पूरी होगी। इसके बाद इनकी भी दो अलग- अलग चार्जशीट दायर की जाएंगी।

डिप्टी रेंजर, वनरक्षक हुए चार्जशीट : करसोग के तत्कालीन डिप्टी रेंजर तेज राम और वनरक्षक गिरधारी लाल पहले सस्पेंड व इसके बाद चार्जशीट किए गए। अब इस मामले की विभागीय जांच के लिए सरकार ने सुंदरनगर के वन प्रशिक्षण संस्थान (एफटीआइ) के संयुक्त निदेशक राहुल को जांच अधिकारी लगाया है।

सीबीआइ ने दर्ज किए हैं तीन केस : हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ की शिमला ब्रांच ने 26 अक्टूबर को तीन अलग-अलग केस दर्ज किए थे। इनमें दो केस वन कटान और एक हत्या का था।

पेड़ से उल्टा टंगा मिला था शव : जून 2017 में होशियार सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। पुलिस को नौ जून को उसका पेड़ से उल्टा टंगा शव बरामद हुआ था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। अगले दिन इसे आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में तबदील किया गया। इससे क्षेत्र के लोग भड़क गए थे। उन्होंने सड़क पर उतर कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

क्या खाया था वनरक्षक ने : पांच जून की सुबह शिक्षक पवन के घर में वनरक्षक होशियार सिंह ने चावल, दाल, सलाद, आलू मिक्स आदि खाए थे। यह भोजन आठ बजकर 45 मिनट से पहले किया गया था। उसका शव नौ जून को मिला। दस जून को पोस्टमार्टम के दौरान यह भोजन पेट में ही पाया गया था। होशियार सिंह ने पांच जून को दोपहर एक बजकर 17 मिनट पर अपनी दादी को अंतिम फोन कॉल की थी। तब वह मौका-ए-वारदात के नजदीक रहा होगा।

तीन लोग किए थे गिरफ्तार : सीबीआइ ने पिछले साल तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। ये सभी अवैध वन कटान के मामले से जुड़े थे। इनमें एक वन अधिकारी भी शामिल था। सीबीआइ ने हाईकोर्ट के निर्देश पर गत वर्ष 26 अक्टूबर को हत्या, अवैध कटान व लकड़ी चोरी करने के संबंध में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। इस संबंध में एसआइटी गठित की गई थी जिसके मुखिया डीएसपी रैंक के अधिकारी थे। नौ महीने के दौरान टीम कई बार मौके पर गई। सेरी कतांडा बीट में गरजूब के जंगलों की खाक छानी गई। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई। बीट में देवदार का अवैध कटान हुआ था। इस संबंध में पूर्व सरकार ने अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल एचएस डोगरा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। कमेटी ने जांच रिपोर्ट में पाया था कि क्षेत्र में बड़े पैमाने में अवैध कटान हुआ था। सीआइडी की सिफारिश पर वन अधिकारियों की संपत्ति की जांच मंडी विजिलेंस को सौंपी गई थी। लेकिन यह जांच सिरे नहीं चढ़ पाई।

सीआइडी ने पाया आत्महत्या का मामला

सीआइडी ने जांच में वनरक्षक की मौत को आत्महत्या का मामला करार दिया। इसके जांच अधिकारियों ने जांच में तीन सुसाइड नोट बरामद किए थे। इनमें आत्महत्या के लिए वन काटुओं को जिम्मेदार ठहराया गया था।

इनामी समेत आठ नक्सलियों का ग्रामीणों ने कराया आत्मसमर्पण

छत्तीसगढ़ के सुकमा में ग्रामीणों के साथ आत्मसमर्पण करने पहुंचे नक्सली। नईदुनिया

नईदुनिया, सुकमा

छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा का दंश झेल रहे सुकमा में पहली बार ऐसा हुआ, जब ग्रामीणों ने समझाकर आठ नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया। इनमें एक नक्सली पर एक लाख रुपये का इनामी घोषित है। रविवार को आठों नक्सलियों को लेकर ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे और आत्मसमर्पण कराया।

जिले के फुलबगड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पोंगाभेज्जी के सरपंच पुनेम सन्ना के नेतृत्व में ग्रामीण रविवार को एसपी कार्यालय पहुंचे। वहां एसपी शलभ सिन्हा के समक्ष आठ नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराया। ग्रामीणों में महिलाएं भी थीं। ग्रामीणों ने बताया कि काफी समझाने के बाद इन्हें तैयार किया है।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक लाख रुपये का इनामी मिलिशिया कमांडर पुनेम गंगा समेत मिलिशिया डिप्टी कमांडर दिरदो हुर्रा, सदस्य मदाम गंगा, दुधी गंगा, पुनेम मुक्का, पुनेम भीमा, पोड़ियाम नंदा व पोड़ियाम जोगा शामिल हैं।

झारखंड में दो युवकों को मार डालने पर उतारू थी भीड़, पुलिस ने बचाया

जेएनएन, सरायकेला/रामगढ़

झारखंड में उग्र भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेकर हिंसा पर उतारू हो जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार रात भी सरायकेला और रामगढ़ में हुई दो अलग-अलग घटनाओं में चोरी करते पकड़े गए दो युवकों को उग्र भीड़ पीट-पीट कर मार डालने पर उतारू थी। दोनों ही घटनाओं में समय पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को उग्र भीड़ से छुड़ाया और वे भीड़ हिंसा का शिकार होने से बचे। पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद दोनों युवकों का इलाज कराया। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

सरायकेला में तबरेज अंसारी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यहां उग्र भीड़ ने एक बार फिर कानून हाथ में लिया। रविवार देर रात सरायकेला थाना के कोलाबीरा ओपी क्षेत्र में चोरी के आरोप में लोगों ने सागर कैवर्त नामक युवक की पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ के चंगुल से आरोपित को बचाया। पुलिस की देखरेख में पीड़ित का सरायकेला सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि मुड़िया पंचायत के कोलाबीरा में सागर कैवर्त चोरी की नीयत से विपुल महतो के घर में घुस गया था। इसी बीच घरवालों और आसपास के लोगों ने उसे दबोच कर पिटाई शुरू कर दी। तभी कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जान बचा ली। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम सागर कैवर्त बताया है। वह अपने दो साथी तिरिलडीह के कृष्णा दास व कोलाबीरा के तपन नायक के साथ चोरी करने के लिए घर में घुसा था।

विपुल महतो के बयान पर सागर कैवर्त, कृष्णा दास व तपन नायक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सागर कैवर्त का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वस्थ्य होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। उधर कृष्णा दास व तपन नायक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामले की छानबीन जारी है।

उधर एक अन्य घटना में रामगढ़ के न्यू बगीचा कॉलोनी, गोलपार में रविवार रात पुलिस की सक्रियता के कारण एक युवक मॉब-लिंचिंग का शिकार होते-होते बचा। बताया जाता है कि रविवार रात न्यू बगीचा कॉलोनी स्थित एक मकान का वेंटीलेटर तोड़कर चोरी करने घुसे युवक को घरवालों ने रंगेहाथ पकड़ लिया। इसके बाद उग्र लोगों ने युवक के दोनों हाथ-पैर रस्सी से बांधकर लात-घूंसे, चप्पल और लाठी-डंडे से पिटाई की। इसी बीच किसी ने पुलिस को मामले की सूचना दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित चोर को ग्रामीणों से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घायल आरोपित युवक का सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम बिरजू भुइयां बताया है। वह बिहार के नवादा का रहनेवाला है और रामगढ़ में अपने एक रिश्तेदार के यहां कुम्हार टोली में ठहरा हुआ था। पुलिस युवक से रामगढ़ थाने में पूछताछ कर रही है।

चोरी के आरोप में पिटाई से घायल सागर की जांच करते डॉ बरियल मार्डी। जागरण

बहादुरी

जसविंदर और जगतार ने पेश की मिसाल, क्षेत्र में हो रही बहादुरी की प्रशंसा, जब महिला पगड़ी पकड़ नहीं पाई तो पेट से बांधकर युवक नहर में उतरा

युवकों ने पगड़ियां खोल बचाई डूब रही बुजुर्ग की जान

संवाद सूत्र, घनौली

पगड़ी सिखों की पहचान है। घर के बाहर पगड़ी को उतारना मर्यादा के खिलाफ माना जाता है, लेकिन अगर जब बात किसी की जान बचाने की आती है तो सिख अपनी पगड़ी की असली पहचान और इसकी शान बताकर मिसाल पेश करते हैं। ऐसी ही मिसाल सोमवार सुबह घनौली के गांव मलिकपुर से होकर गुजरने वाली भाखड़ा नहर के पास देखने को मिली।

एक बुजुर्ग महिला भाखड़ा नहर में बहती हुई आ रही थी। जान बचाने के लिए हाथ पैर मारते हुए मदद के लिए चिल्ला रही थी। गांव लाडल का जसविंदर सिंह और गांव बैरमपुर का जगतार सिंह अपने बाइक पर नहर के साथ से गुजरने वाली पटरी से नालागढ़ के लिए जा रहे थे। बुजुर्ग महिला को देख दोनों रुक गए और उसे बचाने के लिए अपनी पगड़ियां उतार दीं। दोनों पगड़ियों को जोड़कर एक कोना नहर में फेंक दिया। बुजुर्ग पगड़ी को नहीं पकड़ पाई तो जसविंदर और जगतार भागकर नहर के अगले हिस्से में पहुंचे। एक दस्तार को पेट से बांधकर नहर में उतरा और दूसरा बाहर खड़ा होकर पगड़ी का दूसरा हिस्सा संभाले खड़ा रहा। बहती महिला को युवक नहर के किनारे पर ले आया लेकिन उसे नहर की ढलान से ऊपर नहीं ला पाया। इसी बीच दूसरा युवक भी नहर की ढलान में उतर आया और दोनों ने काफी देर महिला को पकड़े रखा। बाद में वहां से गुजरने वाले लोगों से सहायता मांगकर युवक बुजुर्ग महिला को नहर से बाहर निकाल लाए।

जसविंदर और जगतार दोनों नालागढ़ में दुकान करते हैं। रोज इकट्ठे की एक बाइक पर सुबह करीब आठ बजे नहर के पास से गुजरते हैं। बुजुर्ग महिला के लिए दोनों सोमवार को फरिश्ता बनकर आए।

परिवार के लोग भी पहुंच गए तलाश करते : नहर से बाहर निकालने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उनसे उनका नाम और घर का पता करने की काफी कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग महिला कुछ बता नहीं पाई। इसी बीच वहां उनके परिजन भी पहुंच गए। उन्होंने दोनों युवकों का शुक्रिया अदा किया और कुछ देर बाद सामान्य होने पर बुजुर्ग महिला को अपने साथ ले गए।

भाखड़ा नहर में डूबती बुजुर्ग महिला को बाहर निकालते जसविंदर सिंह और जगतार सिंह। दोनों ने अपनी पगड़ी खोलकर बुजुर्ग महिला की जान बचाई। जागरण

युवकों की बहादुरी की हो रही प्रशंसा : एक घंटे से अधिक समय तक हुए इस घटनाक्रम के बाद लोग दोनों युवकों की बहादुरी की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशासन से स्थानीय लोग मांग करने लगे हैं कि युवकों को बहादुरी अवार्ड से सम्मानित किया जाए। कर्मचारियों ने कहा है कि उनकी बात को ध्यान में रखकर अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

सीआरपीएफ जवानों ने नाले में बह रही बच्ची को बचाया

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जनाब, मैं तो उम्मीद छोड़ बैठा था कि मेरी बच्ची जिंदा बचेगी। वह मेरी आंखों के सामने डूब रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसे पुकारूं। गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कोई आसपास नजर नहीं आ रहा था। मेरे लिए तो ये सीआरपीएफ के जवान खुदा के भेजे फरिश्ते हैं, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाल मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। अस्पताल में उपचाराधीन अपनी बेटी नगीना के पास खड़े मोहम्मद शरीफ दीन ने यह बातें कहीं।

उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के चनपोरा, कुंजर में सोमवार सुबह मोहम्मद शरीफ दीन निवासी नगरोटा, जम्मू की 13 वर्षीय बेटी नगीना फिरोजपोरा नाले के तेज बहाव में बह रही थी। उसे सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। खानाबदोश गुज्जर समुदाय का मोहम्मद शरीफ दीन अपने परिजनों और माल मवेशी के साथ इन दिनों चनपोरा, कुंजर में डेरा डाले हुए है। वह जम्मू के नगरोटा का रहने वाला है। सोमवार सुबह उसकी 13 वर्षीय बेटी नगीना कपड़े धोने नाले पर गई थी। ऊपरी इलाकों में हुई बारिश के कारण नाले में जलस्तर भी बढ़ा हुआ था और पानी का बहाव भी तेज था। कपड़े धोते हुए अचानक नगीना का पांव फिसला और वह नाले में गिर गई और बहने लगी। उसने मदद के लिए शोर मचाया।

जवानों ने लगाई नाले में छलांग : नाले से कुछ ही दूरी पर सीआरपीएफ की 176वीं वाहिनी का शिविर भी है। जवानों ने जब लड़की को बहते देखा तो तुरंत उसकी मदद को दौड़े। दो जवानों एमजी नायडू और एन उपेंद्रा ने नाले में छलांग लगा दी। इस दौरान एक जवान पानी में गिर भी पड़ा, लेकिन उन्होंने बह रही लड़की को पकड़ लिया। इस बीच, अन्य जवान भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लड़की को नाले से बाहर निकाला और मौके पर प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध करवाई, फिर उसे अस्पताल पहुंचाने में भी उसके परिजनों की मदद की।

1.59 करोड़ लोगों ने अब तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार का इस्तेमाल किया है। यह जानकारी राज्यसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार के इस्तेमाल पर अब पाबंदी लगा दी गई है।

बिहार में बाढ़ के पानी में लाखों लोग घिरे, 31 की गई जान

कहर ▶ 13 जिलों में पहुंचा बाढ़ का पानी, लोग कर रहे पलायन, दिल्ली में जोरदार बारिश

नीतीश ने पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों हवाई सर्वेक्षण किया

जेएनएन, नई दिल्ली

बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के पानी में लाखों लोग घिरे हुए हैं। सोमवार को 31 लोगों की डूबने से मौत हो गई। बाढ़ के पानी से बचने के लिए लोगों का पलायन जारी है। वहीं राहत और बचाव में देरी से लोगों में रोष भी है। बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों हवाई सर्वेक्षण किया। सोमवार को दिल्ली में भी जोरदार बारिश हुई। उधर, बारिश के कारण हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, झज्जर, करनाल और यमुनानगर जिलों में भी जनजीवन बेहाल हो गया है। पंजाब में आने वाले चार दिनों में जोरदार बारिश की संभावना है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है।

घरों में घुसा बारिश का पानी : बिहार के सीतामढ़ी में नदियों का कहर लगातार जारी है। शहर में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग हाईवे, प्रमुख सड़क, स्कूल और रेलवे पटरी पर तंबू लगा कर जैसे-तैसे रह रहे हैं। सैकड़ों की आबादी बाढ़ के पानी में घिरी हुई है। राहत और बचाव टीमें लोगों को सुरक्षित निकाल ऊंचे स्थान पर पहुंचाने में लगी है। शिवहर, पूर्वी चंपारण और पड़ोसी देश नेपाल से सड़क संपर्क भंग हैं। सीतामढ़ी-रक्सौल रेलखंड पर चैनपुर के पास धंसे पटरी को ठीक कर लिया गया है। मालवाहक ट्रेन का परिचालन कराया गया है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में कमी बाढ़ की स्थिति में सुधार है। मोतिहारी की सभी नदियां उफान पर हैं। मधुबनी में बाढ़ की स्थिति सोमवार को भी भयावह रही। कमला बलान, कोसी व अन्य नदियों के जलस्तर में तेजी है। कोसी मुख्य नहर सोमवार को दो जगह टूट गई। दरभंगा में कमला नदी का तटबंध टूटने के बाद सोमवार को जिले के नए हिस्सों को भी बाढ़ के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया।

दिल्ली में जमकर बरसे बदरा : दिल्ली वासियों के लिए सप्ताह का पहला दिन खुशनुमा मौसम लेकर आया। बारिश के लिए तरस रहे लोगों पर बदरा जमकर बरसे। यूं कहने को तो मानसून ने राजधानी में दस दिन पहले ही दस्तक दे दी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं हो रहा था। सोमवार को पहली बार इस मानसून की जोरदार बारिश हुई। दोपहर बाद तीन बजे के आसपास एकाएक इतना अंधेरा छा गया कि वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलानी पड़ गई। अंधेरे की वजह से शाम का अहसास हो रहा था। तेज हवा के साथ उड़ रही मिट्टी ने माहौल को धूल भरा भी बना दिया। इसके बाद जो झमाझम बारिश शुरू हुई, वह घंटे भर तक चली। यह बारिश भी दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में हुई। मंगलवार को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

हाल अन्य राज्यों का : हिमाचल प्रदेश में देर से पहुंचा मानसून छह दिन बाद कमजोर पड़ सकता है। मप्र के 34 जिलों में अगले 24 घंटे मौसम शुष्क बना रहेगा। 18 जिलों में मंगलवार को गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। जम्मू- श्रीनगर में अगले छह दिन तक हल्की से तेज बारिश होगी। उधर राजस्थान में लोगों को भी बारिश का इंतजार है । पिछले सप्ताह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और अजमेर में एक दिन हुई तेज बारिश से लोगों को लगने लगा था कि प्रदेश में मानसून आ गया है, लेकिन एक दिन प्रदेश के आधा दर्जन जिलों को भिगोने के बाद बारिश नहीं हुई। झारखंड के ज्यादातर जिलों में सोमवार को धूप खिली रही। ज्यादातर जिलों में अगले चार दिनों तक मध्यम बारिश हो सकती है।

असम में बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को पीने के पानी तक के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हैंडपंप, कुएं बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में लोग कामरूप जिले के बाढ़ग्रस्त गांव में सोमवार को नौका के सहारे कुएं तक पहुंचकर पीने का पानी भरती महिला। प्रेट्र

...तो क्या कोसी फिर लेगी करवट

भरत कुमार झा, सुपौल

कोसी अपनी धारा परिवर्तन की उच्छृंखलता के कारण ही बिहार का शोक कही जाती है। हालांकि, बिहार की अधिकांश नदियों का यही चरित्र है, लेकिन कोसी कुछ अधिक बदनाम इस कारण है कि वह दूसरी तमाम नदियों की तुलना में विस्तृत भूभाग में तेजी से धारा परिवर्तन करती है। 1731 में फारबिसगंज और पूर्णिया के पास बहने वाली कोसी धीरे-धीरे पश्चिम की ओर खिसकते हुए 1892 में मुरलीगंज के पास, 1922 में मधेपुरा के पास,1936 में सहरसा और दरभंगा-मधुबनी जिला के समीप पहुंच गई। इस प्रकार लगभग सवा दो सौ साल में कोसी 110 किमी पश्चिम खिसक गई।

1959 से किया पूरब की ओर रुख : 1959 से तटबंधों के बीच कैद कोसी पूरब की ओर लौटने को काफी व्यग्र दिखी। 1984 में नवहट्टा के समीप तटबंध का टूटना इसी व्यग्रता का परिणाम रहा। इसके बाद से लगातार कोसी पूर्वी तटबंध पर आक्रामक रुख अख्तियार किए रही है। 2008 में पूर्वी तटबंध पर पूर्वी इलाके में एक बड़े भूभाग में इसने उत्पात मचाया था।

मनमर्जी से बदलती है धारा : कोसी के आक्रमण से हर साल होने वाली बड़ी क्षति को देखते हुए ही सही, कोसी को तटबंधों के बीच कैद कर दिया गया। 126 किलोमीटर पूर्वी तथा 122 किलोमीटर पश्चिमी तटबंध का निर्माण कराया गया। 1959 में 56 फाटकों वाले 1149 मीटर लंबे बराज का निर्माण कराया गया। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार जिलों के 22.69 लाख एकड़ क्षेत्रफल में करीब 2887 किमी लंबी नहरों का जाल बिछाया गया। मकसद पानी के दबाव को तोड़ने तथा कोसी के पानी का सिंचाई में उपयोग करने का था। बावजूद, कोसी की धारा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सका। अपनी प्रकृति के अनुसार वह धारा बदलती उन्मुक्त होने को हमेशा व्यग्र दिखी है।

करने लगी पश्चिम की ओर रुख : 2016 से कोसी की नजर फिर पश्चिम की ओर जाने लगी। लगातार पश्चिमी तटबंध के कई बिंदुओं पर उसका दबाव बनता रहा। इस वर्ष जो उत्पात कोसी का पश्चिमी इलाके में दिख रहा है उससे तो स्पष्ट होने लगा है कि अब कोसी ने पश्चिम का रुख करना शुरू कर दिया है। हालांकि, एक मुख्यधारा अभी भी पूर्वी तटबंध से सटी बह रही है।

गांव डूबने के बाद तटबंध पर तंबू डाले कोसी पीड़ित । जागरण

हिमाचल प्रदेश के सोलन में 24 घंटे में पूरा हुआ बचाव अभियान, 13 जवानों समेत 14 की मौत

जागरण संवाददाता, सोलन

हिमाचल के सोलन स्थित कुमारहट्टी के पास नाहन मार्ग पर चार मंजिला इमारत गिरने से दबे लोगों को बचाने के लिए चलाया बचाव अभियान 24 घंटे बाद पूरा हो गया है। हादसे में मलबे में दबे 42 लोगों में से 14 की मौत हो गई। जबकि 28 को सकुशल निकाल लिया गया। मरने वालों में असम राइफल्स के 13 जवान और एक स्थानीय महिला थी। हादसा रविवार दोपहर बाद तीन बजे हुआ था।

असम राइफल्स के जवान डगशाई छावनी में तैनात थे। घायल और मृतकों में आठ राज्यों असम, त्रिपुरा, हरियाणा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और हिमाचल प्रदेश के थे। 30 जवान खाना खाने के लिए ढाबे में रुके थे, उनके अलावा 12 स्थानीय लोग भी भवन में मौजूद थे। बारिश से भवन का निचला हिस्सा धंस गया और देखते ही देखते 42 लोगों के साथ भवन ध्वस्त हो गया। रविवार रात में बचाव दलों ने सात लोगों को मृत निकाला था। सोमवार को सात अन्य को मृत निकाला गया।

मुख्यमंत्री ने बैठाई जांच, भवन मालिक पर एफआइआर : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए मैजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया है। वह अगले 15 दिन में मामले से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। भवन मालिक पर आइपीसी की धारा 336 और 304 के तहत एफआइआर दर्ज करवा दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हादसे की जगह का दौरा किया। उन्होंने एनडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इसके बाद वह घायलों का कुशलक्षेम जानने सिविल अस्पताल धर्मपुर और महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज भी गए। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

हिमाचल प्रदेश के सोलन में कुमारहटटी-नाहन मार्ग पर इमारत ढहने के बाद सोमवार को भी राहत-बचाव कार्य जारी रहा। रविवार को यह इमारत मूसलधार बारिश के चलते ढह गई थी। जागरण

- **सोलन के कुमारहट्टी में रविवार को ध्वस्त हो गई थी चार मंजिला इमारत**

मृतकों के परिजन को 20-20 हजार रुपये की फौरी राहत वितरित की है। घायलों का पांच से दस हजार रुपये की सहायता राशि दी है। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार के नियमानुसार 4-4 लाख रुपये दिए जाएंगे।

-केसी चमन, उपायुक्त

कांवड़ यात्रा पर आने से पहले थाने में देनी होगी सूचना

जागरण संवाददाता, देहरादून

- **पुलिस ने दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल को भेजा पत्र**
- **कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्था बनाने और अनहोनी पर रेस्क्यू होगा आसान**

कांवड़ यात्रा पर आने वाले हर कांवड़िये को अपने थाने में जानकारी देनी होगी। रास्ते में पड़ने वाली पुलिस चेकिंग पोस्ट में इसकी पुष्टि कराई जाएगी। कांवड़ यात्रा में हुड़दंग और व्यवस्था बनाने के लिए राज्य पुलिस ने यह रास्ता निकाला है। इसे लेकर सभी राज्यों के डीजी को पत्र भेजा गया है।

कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर दून, दिल्ली, नोएडा में पुलिस अधिकारियों की बैठकें हुईं। इन बैठकों में इस बार सुरक्षा पर विशेष चर्चा की गई। इसमें उत्तराखंड पुलिस की तरफ से हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, उत्तरकाशी, देवप्रयाग, केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री आदि जनपदों में आने वाले कांवड़ियों से व्यवस्था बनाने के लिए यात्रा पर आने से पहले अपने थाना क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने को कहा गया है। इस पर सभी राज्यों के अधिकारियों ने सहमति भी दे दी है। ऐसे में यात्रा पर आने वाले कांवड़िये अपने थाना क्षेत्र में अकेले या दल में आने का पूरा विवरण देंगे।

थाने से उन्हें पंजीकरण नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। रास्ते में पड़ने वाली पुलिस चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान इसकी पुष्टि कराई जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि यह व्यवस्था भले ही इस बार ट्रायल के रूप में लागू की जा रही हो, मगर इससे अप्रिय स्थिति से निपटने और रेस्क्यू में आसानी होगी। साथ ही लोगों को अपने परिजनों को ढूंढने में भी आसानी होगी।

इस बार थानों में कांवड़ियों का पंजीकरण कराने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कराया जाना है। उम्मीद है कि इस व्यवस्था का सभी पालन कराएंगे।

- अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था

केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश के दौरान यात्रा अनुमति नहीं

जागरण संवाददाता, देहरादून : राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिनचौली और भीमबली यात्रा पड़ाव स्लाइडिंग जोन बन चुके हैं। इससे बारिश के दौरान भूस्खलन एवं पत्थर गिर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों में यात्रा की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है।

उधर, भारी बारिश के चलते चमोली जिले के चार ब्लाकों के करीब 40 ग्रामीण पैदल मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गए। इससे करीब सौ गांव प्रभावित हैं। चमोली में ऋषिकेश-बदरीनाथ हाइवे लंगासू के पास दोपहर ढ़ाई बजे से करीब दो घंटे बाधित रहा। इसे दौरान एक हजार से अधिक यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश के पांच जिलों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी नैनीताल एवं उधम सिंह नगर में भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने संबंधित जिला अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के आपदा प्रबंधन टीम को भी मुस्तैद रहने को कहा है ताकि आपातस्थिति में उनका इस्तेमाल हो सके।

सावन में बाबा की पहली मंगला आरती दो घंटे देर से

जागरण संवाददाता, वाराणसी

आषाढ़ पूर्णिमा पर मंगलवार की देर रात से अगले दिन भोर तक चंद्र ग्रहण लगने से श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की सावन में पहली मंगला आरती दो घंटे विलंब से होगी। सावन के पहले दिन दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को भी 1.45 घंटा अधिक इंतजार करना होगा। आषाढ़ पूर्णिमा यानी रात 1.31 बजे खंड ग्रास चंद्रग्रहण लग रहा है जिसका मध्य रात तीन बजे और मोक्ष बुधवार को सावन की पहली भोर 4.30 बजे होगा। ऐसे में मंगला आरती तय समय 2.45 बजे के बजाय 4.45 बजे से 5.45 बजे तक की जाएगी। इसके बाद मंदिर के पट बाबा भक्तों को दर्शन-पूजन के लिए खोल दिए जाएंगे। वास्तव में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मंगला आरती के समय में 15 मिनट कटौती की गई है। आम दिनों में इसमें सवा घंटे का समय लिया जाता है। धर्मशास्त्रीय विधान के अनुसार चंद्रग्रहण में नौ घंटे पहले सूतक लग जाता है लेकिन मंगलवार की सांध्य व रात्रि कालीन आरती इससे बेअसर रहेगी। हालांकि सूतक के कारण संकट मोचन मंदिर के पट 4.30 बजे आरती कर बंद कर दिए जाएंगे जो बुधवार सुबह ग्रहण मोक्ष बाद खुलेंगे।

चंद्रग्रहण के सूतक काल में 12 घंटे बंद रहेंगे चारधाम के कपाट

जागरण संवाददाता, देहरादून

- **हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर आज दोपहर बाद तीन बजे और गंगोत्री धाम में शाम 3:45 बजे होगी गंगा आरती**

मंगलवार को मध्यरात्रि के बाद पड़ने वाले चंद्रग्रहण के सूतक के चलते चारों धाम समेत देवभूमि उत्तराखंड के सभी मंदिरों के कपाट मंगलवार शाम 4:25 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में भक्त बुधवार सुबह 4:40 बजे मंदिरों के शुद्धिकरण के बाद ही भगवान के दर्शन कर सकेंगे। चंद्रग्रहण को देखते हुए हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा आरती का आयोजन आज दोपहर बाद तीन बजे होगा। जबकि, गंगोत्री धाम में शाम 3:45 बजे गंगा आरती की जाएगी।

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने बताया कि मंगलवार को मध्यरात्रि के बाद 1:31 बजे ग्रहण का स्पर्श और ब्रह्ममुहूर्त में 4:30 बजे मोक्ष होगा। यानी चंद्रग्रहण की पूर्ण अवधि दो घंटा 59 मिनट की रहेगी। जबकि, ग्रहण का सूतक नौ घंटे पहले मंगलवार शाम 4:30 बजे आरंभ हो जाएगा।

दिन में ही होगी मां गंगा की आरती : चंद्रग्रहण के कारण दशाश्वमेध घाट समेत अन्य घाटों पर नैत्यिक सांध्य गंगा आरती मंगलवार को दिन में तीसरे पहर ही कर ली जाएगी। दिन में सूतक शुरू होने से तीन बजे आरती शुरू होगी।

गुरु दर्शन में ग्रहण का रोड़ा : शाम के साथ चंद्रग्रहण का सूतक लग जाने के कारण ज्यादातर मठ-आश्रमों में गुरु पूजन चार बजे तक ही किया जाएगा। इसके बाद सिर्फ जप-तप अनुष्ठान ही किए जाएंगे। पिछले साल भी रात में चंद्र ग्रहण के कारण इस तरह का व्यवधान हुआ था।

पवित्र कुरान की पांच प्रतियां बांटने की शर्त पर जमानत

जागरण संवाददाता, रांची : सोशल साइट पर एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद रांची की ऋचा भारती (19) को राहत मिल गई है। सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने उसे अनोखी सजा सुनाते हुए सशर्त जमानत दे दी। जज ने कहा, आरोपित को 15 दिनों के अंदर पवित्र कुरान की पांच प्रतियां बांटनी होंगी। अगर इसकी अवहेलना की गई तो जमानत रद हो सकती है। सात हजार के दो निजी बांड जमा करने के बाद सोमवार को ऋचा जेल से बाहर आ गई।

शैक्षणिक संस्थानों में बांटनी होगी कुरान की प्रति : आदेश के मुताबिक कुरान की एक प्रति शिकायतकर्ता सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया एवं अन्य चार प्रति रांची के सरकारी विश्वविद्यालय या कॉलेज या स्कूलों में बांटनी होगी। कुरान की प्रति बांटने के दौरान रांची पुलिस को उचित सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया गया। साथ ही, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दो में एक जमानतदार आरोपित के करीबी रिश्तेदार बनें। ऋचा भारती को 12 जुलाई को जेल भेजा गया था।

पेट्रोल पंप डीलरशिप देने के नाम पर 50 करोड़ की ठगी, दो वेब डेवलपर गिरफ्तार

नईदुनिया, भोपाल

- **मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस ने किया अंतरराज्यीय गिरोह का राजफाश**
- **गुजरात, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों के लोगों को बनाया निशाना**

पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए फर्जी वेबसाइट के जरिये लोगों से रुपये ऐंठने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस ने राजफाश किया है। दो वेब डेवलपर ने सरकारी सार्वजनिक और प्रतिष्ठित कंपनियों की 22 फर्जी वेबसाइट तैयार की थीं। इनके जरिये इन्होंने मप्र के भोपाल, कटनी, मुरैना शहर सहित गुजरात, राजस्थान व बिहार आदि राज्यों में कई लोगों से पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये ठग लिए। वेबसाइट बनाने वाले इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के वरुण कुमार मिश्रा और पठानवाड़ी मलाड (ईस्ट) मुंबई (महाराष्ट्र) के मोहम्मद अनवर खान को मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह की वेबसाइट बनवाने वाले मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है।

साइबर पुलिस के विशेष पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि भोपाल के एक पीड़ित संजय मीणा ने ठगी की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि 'पेट्रोल पंप डीलरशिप चयन डॉट को' वेबसाइट के माध्यम से पेट्रोल पंप डीलरशिप देने के नाम पर आवेदन मांगे गए थे। उक्त नाम के ही एक बैंक खाते में 15 लाख 32 हजार रुपये जमा कराए गए। संदेह होने पर उन्होंने साइबर पुलिस में शिकायत की।

शिकायत के बाद वेबसाइट के बैंक अकाउंट को फ्रीज कराकर पीड़ित के दो लाख 53 हजार रुपये वापस भी कराए गए। जांच में कटनी, मुरैना में भी इसी वेबसाइट के माध्यम से अन्य पीड़ितों से ठगी किए जाने की जानकारी मिली। मप्र में पेट्रोल पंप डीलरशिप दिलाने के नाम पर वेबसाइट संचालकों ने करीब 70 लाख रुपये ठगे। शर्मा ने बताया कि फर्जी पेट्रोल पंप डीलरशिप वेबसाइट का पता लगने के बाद जब दूसरी ऐसी वेबसाइट की पड़ताल की गई तो पेट्रोल पंप डीलरशिप की तीन अन्य फर्जी वेबसाइट के साथ फाइनेंस, मोबाइल कंपनियों की भी ऐसी 22 वेबसाइट मिलीं, जिन्हें तत्काल बंद कराया गया।

बैंक अधिकारियों की मिलीभगत की जांच : शर्मा ने बताया कि फर्जी वेबसाइट से लोगों को ठगने वाले अंतरराज्यीय गिरोह ने बेंगलुरु, बंगाल और झारखंड के भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में चालू खाते खुलवाए थे। इनमें वह लोगों से रुपये जमा करवाते थे। गिरोह के सदस्य चालू खाते का संचालन व्यक्तिगत रूप से करते और उसमें से दूसरे खातों में राशि ट्रांसफर करते थे।

शर्मा से जब पूछा गया कि चालू खाते खुलवाने वाले और जिन दूसरे बैंकों के खातों में राशि ट्रांसफर हुई है, उनके बारे में अब तक जांच में कुछ सुराग लगा तो उन्होंने कहा यह विवेचना में है। हालांकि, शर्मा ने यह जरूर कहा कि चालू खाते का व्यक्तिगत रूप से संचालन होने पर यह आशंका है कि धोखाधड़ी करने वालों के साथ बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत भी होगी।

जनहित याचिका

तीन महिलाओं ने दाखिल की जनहित याचिका, एमटीपी एक्ट के दो अनुच्छेदों को 'असंवैधानिक' करार देने की मांग

गर्भपात कानून की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र/एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को गर्भपात कानून के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की जांच के लिए राजी हो गया। इनमें केवल उसी स्थिति में महिला को गर्भपात की इजाजत दी जाती है, जब उसकी जान को खतरा होता है। आरोप है कि यह प्रावधान महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रजनन की पसंद व निजता का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन महिलाओं द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा है। याचिका में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिगनेंसी (एमटीपी) एक्ट के अनुच्छेद 3(2) (ए) और 3(2) (बी) को 'व्यर्थ व असंवैधानिक' करार देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई व दीपक गुप्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, 'नोटिस जारी करो।'

याचिकाकर्ता स्वाति अग्रवाल, गरिमा सेक्सेरिया व प्राची वत्स ने कहा कि एमटीपी एक्ट का एक प्रावधान गर्भपात के लिए पंजीकृत डॉक्टर की राय को अनिवार्य बनाता है। एक अन्य प्रावधान के मुताबिक, गर्भवती की जान की रक्षा के लिए ही 20 सप्ताह के बाद गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है। ये प्रावधान महिला के स्वास्थ्य, प्रजनन की पसंद व निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एमटीपी (संशोधन) बिल-2014 को लागू करने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। इसके अनुसार, गर्भपात के लिए किसी पंजीकृत चिकित्सक की राय जरूरी नहीं है। साथ ही इसमें गर्भपात की अवधि 24 सप्ताह किए जाने का भी प्रस्ताव है। याचिका में मांग की गई है कि यदि परिजन सहमति न दें तब भी नाबालिगों के लिए सुरक्षित गर्भपात की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

जस्टिस एए कुरैशी मामले में 22 को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसमें केंद्र सरकार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एए कुरैशी के नाम पर अंतिम फैसला करने में विलंब करने का आरोप है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और दीपक गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता गुजरात हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को याचिका की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के लिए कहा। मेहता इस मामले में सहयोग करेंगे। संघ का कहना है कि केंद्र ने दूसरे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। इनके नामों की संस्तुति गर्मी की छुट्टी से पहले सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्य वाली कोलेजियम ने की थी। कोलेजियम ने 10 मई को जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की संस्तुति कर दी थी। इसके बावजूद केंद्र ने उनकी नियुक्ति की फाइल को हरी झंडी नहीं दिखाई, जबकि सात जून को जस्टिस रविशंकर झा को मध्य प्रदेश का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई।

अधिवक्ता संघ ने कहा कि वर्ष 2004 में कुरैशी की नियुक्ति गुजरात हाई कोर्ट के जज के रूप में हुई थी। नवंबर 2018 में बांबे हाई कोर्ट में जब उनका स्थानांतरण हुआ, तब वह गुजरात हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।

एलआइसी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इन्कार : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक संगठन की उस याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया, जिसमें उसने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) पर 'जीवन सरल' बीमा योजना के जरिये लाखों ग्राहकों को भ्रमित करने व धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। याचिका मनीलाइफ फाउंडेशन की तरफ से दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि 50 साल से कम उम्र के अनेक लोगों को यह कहते हुए इस बीमा को लेने के लिए प्रेरित किया गया था कि निवेश के लिहाज से यह बहुत अच्छी पॉलिसी है।

मदरसा से हथियार बरामदगी मामले में एटीएस ने डाला डेरा

जागरण संवाददाता, बिजनौर

उप्र के बिजनौर स्थित शेरकोट के मदरसे में हथियार मिलने के मामले में सोमवार को यूपी एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) की टीम ने यहां डेरा डाल दिया। एसपी रैंक के अधिकारी ने टीम के साथ मदरसे में पहुंचकर जांच-पड़ताल की। एटीएस ने गांव वालों से जानकारी ली। उधर, रिमांड के लिए विवेचक ने कोर्ट में आवेदन किया है।

बिजनौर के शेरकोट में पुलिस ने 10 जुलाई को कांधला रोड पर मदरसा दारुल कुरान हमीदिया में छापेमारी की थी। मदरसा संचालक के कमरे से दवाई के डिब्बे से एक पिस्टल, दो मैग्जीन, चार तमंचे और 24 कारतूस बरामद किए थे। आइबी और एटीएस ने मदरसा पहुंचकर जांच-पड़ताल की थी। इस प्रकरण में मदरसे का संचालक मोहम्मद साजिद, रसोइया अजीजुर्रहमान व उसका बेटा फहीम अहमद, जफर इस्लाम, शिक्षक सिकंदर अली और मोहम्मद शाबिर को गिरफ्तार किया था। मुख्य सौदागर आरिफ व आसिफ अभी फरार चल रहे हैं। सोमवार को एसपी एटीएस विनोद कुमार टीम के साथ दो गाड़ियों से शेरकोट पहुंचे। एक टीम ने थाने पहुंचकर पूरा रिकार्ड खंगाला। दूसरी टीम मदरसे पहुंची और छानबीन की। आसपास के लोगों से भी जानकारी ली। टीम ने कुछ रिकार्ड भी कब्जे में लिया है।

फर्जी ढंग से चल रहा था मदरसा, खतौनी में किसान की जमीन : हथियारों की तस्करी का ठिकाना बना शेरकोट का मदरसा फर्जी ढंग से चल रहा था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मदरसे का कोई अभिलेख नहीं मिला है। पुलिस को जमीन की रजिस्ट्री नहीं दिखाई गई। चंदे की रसीद और यहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चों का भी रिकार्ड नहीं मिला। उधर, तहसील टीम ने मौके पर पहुंचकर मदरसे की जमीन की पैमाइश की है। राजस्व रिकार्ड में उक्त जमीन किसानों के नाम दर्ज है। इसमें मदरसे का कोई जिक्र नहीं है। शेरकोट के मदरसे से तमंचे व पिस्टल मिलने के बाद हर स्तर पर बारीकी से जांच की जा रही है।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 16 जुलाई 2019

दैनिक जागरण
नदी का प्रवाह तभी बनता है जब वह किनारों में बंधकर बहती है

कोलेजियम पर सही सवाल

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कोलेजियम व्यवस्था को लेकर राज्यसभा में सवाल उठने पर हैरानी नहीं। हैरानी तो तब होती जब संसद कोलेजियम को लेकर मौन धारण किए रहती, लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उच्च सदन में शून्य काल के दौरान यह मांग उठी कि उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का चयन अखिल भारतीय परीक्षा के जरिये किया जाए। यह अच्छा हुआ कि इस मसले पर विभिन्न दलों के सांसदों की दिलचस्पी को देखते हुए राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने यह कहा कि न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के अधिकारों और सीमाओं पर व्यापक चर्चा करने की जरूरत है। वास्तव में इस पर केवल व्यापक चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी कोई व्यवस्था भी बननी चाहिए जिससे उस दोषपूर्ण कोलेजियम से छुटकारा मिले जिसके तहत न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ऐसा किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं होता। ऐसा केवल भारत में ही होता है और वह भी तब जब खुद सुप्रीम कोर्ट यह स्वीकार कर चुका है कि कोलेजियम व्यवस्था दोषपूर्ण है। कायदे से इस स्वीकारोक्ति के बाद या तो इस व्यवस्था के दोष दूर किए जाने चाहिए थे या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई व्यवस्था बननी चाहिए थी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से किसी को यह बताना चाहिए कि ऐसा अब तक क्यों नहीं हो सका है? यह लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के अनुकूल नहीं कि न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्तियां खुद करें।

निःसंदेह यह सुखद नहीं रहा कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में संविधान संशोधन के जरिये जिस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहरा दिया। इस फैसले से इस आयोग के गठन के लिए की गई लंबी कवायद व्यर्थ साबित हुई। यह संभव है कि इस आयोग के कुछ प्रावधान न्यायसंगत न रहे हों, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता कि उन्हें सुसंगत बनाने पर जोर दिया जाता? कम से कम अब तो यह काम किया ही जाना चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि कोलेजियम व्यवस्था के तहत होने वाली नियुक्तियों को लेकर सवाल उठते ही रहते हैं। चूंकि यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं इसलिए सवाल कुछ ज्यादा ही उठते हैं। जहां तक निचली अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किए जाने की मांग है तो इसका समय आ चुका है। सच तो यह है कि अब तक इस सेवा का गठन हो जाना चाहिए था। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के साथ ही कोलेजियम व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम प्राथमकिता के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्यायिक तंत्र में सुधार के लिए और भी कई कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को समय पर न्याय सुलभ नहीं हो रहा है। भारत सरीखे लोकतांत्रिक देश में इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के पहले इसे लेकर आशंकित रहें कि उन्हें वहां से समय पर न्याय मिलेगा या नहीं? आज ऐसी ही स्थिति है। जब तक यह स्थिति बनी रहती है, न्यायपालिका सवालों से घिरी रहेगी।

रुके भीड़ की हिंसा

झारखंड में लगातार हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं ने एक बार फिर यह सोचने को विवश किया है कि सरकार और पुलिस-प्रशासन से लेकर पूरे समाज को इसे रोकने पर गंभीरता से विचार करना होगा। यूं देखें तो भीड़ की हिंसा एक क्षणिक उन्मादी प्रवृत्ति है जिसे किसी एक घटना की प्रतिक्रिया में सामूहिक रूप से अंजाम दिया जाता है। झारखंड में अभी सरायकेला में तबरेज अंसारी की चोरी के आरोप में पिटाई के बाद मौत का मामला थमा भी नहीं था कि गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और फिर सरायकेला में भी ऐसी घटनाएं लगातार हुईं। शनिवार को गिरिडीह के बगोदर में हुई घटना में तो हिंसा के शिकार व्यक्ति को बचाने गई पुलिस पर भी भीड़ ने पथराव कर दिया। इससे पहले रामगढ़ में दो साल पहले अलीमुद्दीन अंसारी को भीड़ ने प्रतिबंधित मांस ले जाने के आरोप में पीट-पीट कर मार डाला था। वहीं सरायकेला में बच्चा चोरी के आरोप में भी कुछ लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दिए जाने के मामले सामने आए थे। हाल की घटनाओं से पता चलता है कि भीड़ किसी एक कारण से उग्र नहीं होती। कभी सामान चोरी के कारण तो कभी बच्चा चोरी के कारण और कभी किसी युवक-युवती के प्रेम संबंध के कारण तो कभी गोरक्षा और प्रतिबंधित मांस के नाम पर ये घटनाएं हो रही हैं। झारखंड में तो डायन-बिसाही के नाम पर अंधविश्वास में मार डालने की भी घटनाएं आम हैं। कारण चाहे जो भी हों, लेकिन इस तरह कि घटनाएं सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकतीं। हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं। साथ ही यह भी कि ऐसा करना गंभीर अपराध है। एक ओर जहां भावनाएं भड़काकर इस तरह की घटनाओं को हवा देने वालों को चिन्हित कर उन्हें कड़ी सजा देने की जरूरत है वहीं लोगों को भी जागरूक करना होगा। अपराधी को पुलिस के हवाले कर कानून के तहत उसे सजा दिलाने की प्रवृत्ति आम लोगों में विकसित करने के लिए सरकार और पुलिस-प्रशासन को बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।

वक्त की जरूरत है निजीकरण

डॉ. भरत झुनझुनवाला

एयर इंडिया के निजीकरण के विरोध में दिए जा रहे तर्क कहीं टिकते नहीं। सरकार को चाहिए कि इस नीति को सभी सार्वजनिक उपक्रमों खासतौर से बैंकों पर भी लागू करे

मोदी सरकार ने एयर इंडिया का निजीकरण करने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक इकाइयों के निजीकरण के विरुद्ध पहला तर्क मुनाफाखोरी का दिया जा रहा है। जैसे ब्रिटिश रेल की लाइनों का निजी कंपनियों द्वारा निजीकरण कर दिया गया। उसमें पाया गया कि रेल सेवा की गुणवत्ता में गिरावट आ गई। रेलगाड़ियों ने समय पर चलना बंद कर दिया। सुरक्षा पर खर्च में कटौती हुई, परंतु रेल का किराया नहीं घटा। इसी तरह के कई अनुभव दक्षिण अमेरिकी देशों में देखने को मिले। निजी कंपनियों ने पानी, बस आदि सेवाओं के दाम बढ़ा दिए, लेकिन सेवा की गुणवत्ता में ह्रास हुआ, परंतु यह समस्या एकाधिकार वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। जैसे पाइप से पानी की आपूर्ति का निजीकरण कर दिया जाए तो उपभोक्ता कंपनी की गिरफ्त में आ जाता है। कंपनी द्वारा पानी का दाम बढ़ा दिया जाए तो उपभोक्ता के पास दूसरा विकल्प नही रह जाता है, लेकिन एयर इंडिया प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में सक्रिय है। यदि एयर इंडिया के क्रेता द्वारा हवाई यात्रा का दाम बढ़ाया जाता है तो उपभोक्ता दूसरी प्राइवेट एयरलाइन से यात्रा करेंगे। इसलिए नागर विमानन एवं बैंकिंग जैसे क्षेत्रो में निजीकरण का यह दुष्परिणाम उत्पन्न नहीं होगा।

मुनाफाखोरी को रोकने के लिए ही इंदिरा गांधी ने साठ के दशक में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। चूंकि उनके द्वारा आम आदमी को सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही थीं। वे मुख्य रूप से बड़े शहरों में ही शाखाएं खोल रहे थे जहां ज्यादा मुनाफा था। इंदिरा गांधी ने उनका राष्ट्रीयकरण किया जिससे इनके द्वारा आम आदमी को बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो जाए। ऐसा हुआ भी। 1970 के दशक में बैंकों की पहुंच में भारी विस्तार हुआ, परंतु दूसरी समस्या भी उत्पन्न हो गई। भ्रष्ट बैंक अधिकारियों और जालसाज उद्यमियों की मिलीभगत से सरकारी बैंको ने घटिया लोन दिए जो खटाई में पड़ते गए और देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था आज रसातल में पहुंचती दिख रही है। हम एक गड्ढे से निकले और दूसरी खाई में जा गिरे। इस उद्देश्य को हासिल करने का दूसरा उपाय यह था कि रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंकों के प्रति सख्ती की जाती। उन्हें चिन्हित स्थानों पर शाखाएं खोलने को मजबूर किया जाता और ऐसा न करने पर भारी हर्जाना लगाया जाता जैसे नकद आरक्षित अनुपात आदि नियमों का अनुपालन न करने पर किया जा रहा है। आम आदमी तक बैंकिंग सेवा का न पहुंचना वास्तव में रिजर्व बैंक के नियंत्रण की नाकामी थी। इस बीमारी का सीधा उपचार था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को बर्खास्त कर दिया जाता। रिजर्व बैंक के कर्मचारी ठीक हो जाते तो निजी बैंक भी लाइन पर आ जाते, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस सीधे रास्ते को न अपनाकर निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अनायास ही उसी बैंकिंग नौकरशाही का विस्तार कर दिया जो कि समस्या की जड़ थी। इंदिरा गांधी के उस निर्णय का खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं।

यह सही है कि निजीकरण की आड़ में मुनाफाखोरी हो सकती है, परंतु इसका हल सरकारी नियंत्रण है न कि सार्वजनिक उपक्रमों के सफेद हाथी को ढोना। निजीकरण के खिलाफ दूसरा तर्क सार्वजनिक संपत्ति का औने-पौने दाम पर बेचा जाना है। जैसे ब्रिटिश रेल लाइनों को 1.8 अरब पौंड में बेच दिया गया। खरीदारों ने उन्हीं लाइनों को मात्र सात माह बाद 2.7 अरब पौंड में बेच दिया। अर्थ यह हुआ कि सरकार ने बिक्री कम दाम पर कर दी थी। अपने देश में कोल ब्लाक एवं 2-जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में भी इसी प्रकार का घोटाला पाया गया, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। बाद में कोल ब्लाक और स्पेक्ट्रम कई गुना अधिक मूल्य पर बेचा गया। हमारे इस अनुभव से निष्कर्ष निकलता है कि समस्या निजीकरण की मूल नीति में नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन में है। जैसे सब्जी को तेज आंच पर पकाया जाए और वह जल जाए तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सब्जी को पकाना ही नहीं चाहिए।

अवधेश राजपूत

निजीकरण के विरुद्ध तीसरा तर्क है कि निजी उद्यमियों की आम आदमी को सेवाएं मुहैया कराने में रुचि नहीं होती। 1960 के दशक में बैंकों के निजीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया था, लेकिन दूसरे अनुभव इसके विपरीत बताते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने टेलीफोन, एलपीजी गैस और पानी की सेवाओं का निजीकरण कर दिया। इंटर अमेरिकन बैंक द्वारा कराए गए एक अध्ययन में पाया गया कि निजीकरण के बाद टेलीफोन, गैस और पानी के कनेक्शन की संख्या मे भारी वृद्धि हुई थी। इन सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। भारतीय शहरों में बिजली आपूर्ति के निजीकरण के बाद ऐसा ही अनुभव सामने आया है। गरीब और अमीर के हाथ में नोट का रंग नही बदलता। जहां क्रय शक्ति है वहां निजी कंपनियां पहुंचने को उतारू होती हैं। फिर भी यह सही है कि जहां आम आदमी की क्रय शक्ति नहीं होती है वहां सस्ती सरकारी सेवा का महत्व होता है। जैसे गरीब अक्सर सस्ते सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, मगर गरीब को सब्सिडी वाली इस सेवा का भारी आर्थिक हर्जाना देना होता है। आज सरकारी अध्यापक औसतन 60,000 रुपये का वेतन उठाते है और उनके द्वारा पढ़ाए गए आधे बच्चे फेल होते हैं जबकि 10,000 का वेतन लेकर प्राइवेट टीचर द्वारा पढ़ाए गए 90 प्रतिशत बच्चे पास होते हैं। सस्ती सेवा के चक्कर में गरीब के बच्चे फेल हो रहे हैं। इस समस्या का हल आम आदमी की क्रय शक्ति में वृद्धि हासिल करना है न कि उसकी सेवा के लिए सार्वजनिक इकाइयों को पालना।

सार्वजनिक इकाइयों के निजीकरण के खिलाफ चौथा तर्क रोजगार का है। यह सही है कि निजी इकाई में रोजगार का हनन होता है। जैसे एयर इंडिया में तीन वर्ष पूर्व प्रति हवाई जहाज 300 कर्मी थे जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक लगभग 100 से 150 कर्मचारियों का है। बीते तीन वर्षों में एयर इंडिया ने इस मानक में सुधार किया है। यदि एयर इंडिया का निजीकरण तीन वर्ष पूर्व किया जाता तो निश्चित ही क्रेता द्वारा कर्मियों की संख्या में कटौती की जाती। सच यह है कि मंत्रियों एवं सचिवों के इशारों पर सार्वजनिक इकाइयों में अनावश्यक भर्तियां की जाती हैं जो कि वाणिज्यिक दृष्टि से नुकसानदेह होती हैं। इसलिए निजी क्रेता द्वारा कर्मियों की संख्या में कटौती की जाती है, परंतु यह निजीकरण का केवल सीधा प्रभाव है। कुल रोजगार पर निजीकरण का प्रभाव फिर भी सकारात्मक पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकासशील देशो में किए गए निजीकरण के अध्ययन में पाया गया कि इससे सीधे रोजगार का हनन होता है, लेकिन कुल रोजगार बढ़ता है। इस प्रकार देखें तो एयर इंडिया के निजीकरण के विरोध में दिए जा रहे तर्क कहीं टिकते नहीं। सरकार को चाहिए कि इस नीति को सभी सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू करे विशेषकर सरकारी बैंको पर।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

नेताओं–नौकरशाहों का अनैतिक गठजोड़

प्रेमपाल शर्मा

नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के किए राजनीतिक मूल्यों में भी सुधार की जरूरत है

हाल में कई बेईमान अफसरों के घरों में छापे मारकर नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारी चोट की गई है। भ्रष्टाचार के इस खेल में इनकम टैक्स, कस्टम से लेकर दर्जनों विभागों के अधिकारी लिप्त पाए गए हैं। इनमें आइएएस अफसर भी हैं। बुलंदशहर की पूर्व डीएम बी चंद्रकला का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अभय सिंह नाम के एक और अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई कार्रवाई की जद में आ गए। अभी जांच जारी है फिर भी इन अधिकारियों में कई समानताएं हैं। ये अभी 40 की उम्र तक भी नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले कई-कई जिलों के डीएम रह चुके हैं और इन पर आरोप भी खनन माफियाओं को नियम-कानून तोड़कर फायदा पहुंचाने के हैं। दो वर्ष पहले बिहार में तैनात एक प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी पर भी ट्रेनिंग के दौरान ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। पिछले वर्ष सिविल सेवा परीक्षा के दौरान तो एक अनूठा मामला सामने आया था। केरल कैडर का एक आइपीएस अधिकारी फिर से आइएएस बनने के लिए परीक्षा में बैठा था। वह परीक्षा हॉल में ब्लूटूथ के जरिये नकल करते हुए पकड़ा गया था। यह तो बेईमानी की इंतहा है! भविष्य में ऐसे नौजवानों से नैतिकता की कितनी उम्मीद की जाए जो किसी भी हाल में परीक्षा दुर्ग को तोड़ने में ही सारे मूल्यों को तहस-नहस करने पर उतारू हैं।

पूरे देश के लिए और स्वयं सिविल सेवा परीक्षा के लिए यह एक सबक रहा कि इस अधिकारी ने सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य अध्ययन के एक पेपर 'नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति' में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए थे। साफ जाहिर है कि दीवारों पर उपदेश लिखना, नैतिक मूल्यों को रखना एक पक्ष है और उन्हें जीवन में उतारना बिल्कुल दूसरा। इसका सबसे दुखद पक्ष यह है कि जब देश के करोड़ों नौजवान ऐसी अनैतिक लिप्सा से घिरे हों तो देश का भविष्य क्या होगा? ऐसा नहीं की है ये अभी की अनोखी घटनाएं हैं। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अमेरिकी पत्रकार से बातचीत में स्वीकार किया था कि मैं जिन कामों को नहीं कर पाया उनमें नौकरशाही में सुधार भी शामिल हैं। याद कीजिए उन दिनों की नौकरशाही की तारीफ यदा-कदा होती रही है, लेकिन बावजूद इसके उनमें उपनिवेशी संस्कार इस हद तक कूट-कूट कर भरे हुए थे कि वे बदलती सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों में कई बार रोड़ा अटकाते थे। 1960 के दशक में ही संथानम कमेटी नौकरशाही में भ्रष्टाचार दूर करने और दूसरे सुधारों के लिए बनी थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग और दूसरी संस्थाएं भी लगातार इस दिशा में सक्रिय रही हैं। लोकपाल

का गठन भी इसी कड़ी का हिस्सा है, लेकिन अंजाम वही ढाक के तीन पात वाला है। सवाल है कि क्या सिर्फ नौकरशाही ही ऐसे भ्रष्ट आचरण के लिए जिम्मेदार है? नौकरशाही सरकार के तीन स्तंभों में से एक कार्यपालिका का हिस्सा है, जिसके शीर्ष पर मंत्री होता है। क्या बिना मंत्री के सहयोग के भ्रष्टाचार संभव है? हाल में उत्तर प्रदेश के जिन अधिकारियों पर अंगुली उठी है उनके सीधे-सीधे संबंध तत्कालीन सत्ता प्रतिष्ठान से रहे हैं। हो सकता है कि ये अधिकारी राजनीतिक दबाव के चलते अनुचित कार्यों में भागीदार बने हों। यह ध्यान रहे कि कुछ अधिकारी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के साथ जेल में हैं तो कुछ चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद के साथ।

यह एक दुखद पक्ष यह है कि अरबों रुपये के घोटाले उन योजनाओं में ज्यादा हुए जिन्हें सामाजिक उत्थान, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए लागू किया गया था। हालांकि संजीव चतुर्वेदी, अशोक खेमका जैसे कुछ अधिकारी तबादले की परवाह न करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। उम्मीद की गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना के अधिकार के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि वर्ष 2005 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से तुलना करें तो मामूली सुधार जरूर हुआ है। आज हम दुनिया के 180 देशों में भ्रष्टाचार के मामले में 78वें नंबर पर हैं, मगर दक्षिण एशियाई देशों में अभी भी सबसे भ्रष्ट हैं। 2009 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौकरशाही से काम निकलवाना सबसे मुश्किल है। नौकरशाही में भ्रष्टाचार रोकने के लिए समय-समय पर सरकारें कुछ कदम उठाती भी रही हैं, लेकिन आधे-अधूरे मन से। 1993 में पूर्व गृह सचिव एनएन वोहरा समिति ने भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों के अनैतिक गठजोड़ को रेखांकित किया था। इसी को आधार मानकर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कुछ कदम उठाने के लिए भी कहा था। कई सामाजिक संगठन भी बार-बार आवाज उठाते रहे हैं। सूचना का अधिकार सरकारी भ्रष्टाचार से लड़ने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण कानून भी संसद पास कर चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल इसका मुख्य कारण है राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी। उस राजनीति में इच्छाशक्ति आ ही नहीं सकती जिसके तमाम सदस्य किसी न किसी तरह के भ्रष्ट आचरण में लिप्त हों। यही कारण है कि चाहे उन्हें मंत्री बनने के बाद अपना निजी सचिव चुनना हो या जिले का डीएम या पुलिस कप्तान, वे उस अधिकारी को चुनते हैं जो उनकी जी हजूरी कर सके। आजादी के बाद यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। तमाम नौकरशाह ऐशोआराम और वैभव की जिंदगी जीने के लिए सिविल सेवाओं में आ रहे हैं। लाखों की कोचिंग और कई-कई साल तैयारी करने के बाद उनका कहना होता है कि हमें ठाठ से रहना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े।

भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के कदमों के तौर पर सिविल सेवा परीक्षाओं में नैतिक मूल्यों का एक पेपर शामिल करना कहीं से भी फायदेमंद नहीं रहा है। क्या कोई भी ऐसे प्रश्नों के उत्तर से सदाचारी बन सकता है? क्या दीवारों पर लिखे उपदेश नैतिक मूल्य दे सकते हैं? जब शिक्षा व्यवस्था ही नकल और उड़ाए हुई शोध के खंभों पर टिकी हो, जहां चुनाव के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हों और जहां हर बात को जाति और संप्रदाय के चश्मे से देखा जाता हो वहां नौकरशाही में सुधार लाना बहुत टेढ़ी खीर है। निश्चित रूप से नौकरशाही के साथ-साथ राजनीतिक मूल्यों में भी एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई मोदी सरकार अपने इरादों में सफल होगी।

(लेखक रेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वाणी

हृदय की इच्छाओं, भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रमुख आधार वाणी है। वाणी के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है। मीठी वाणी कल्याण का प्रमुख अमोघ अस्त्र-शस्त्र है। वाणी के माध्यम से किसी को खुश और प्रसन्न किया जा सकता है तथा उन्हें नाराज करके रुलाया भी जा सकता है। वाणी मनुष्य के जीवन का सौंदर्य है। ईश्वर ने किसी मनुष्य को सुंदर शरीर और चेहरा दिया हो, लेकिन वाणी रूपी यंत्र की शक्ति नहीं दी हो तो उसका जीवन नीरस, बेकार, मृतप्राय हो जाता है। वाणी के माध्यम से हम किसी को अपना मित्र भी बना सकते हैं और दुश्मन भी। वाणी की शक्ति से मनुष्य संसार में विजय का परचम लहरा सकता है और दीन-हीन भिखारी का जीवन भी जी सकता है, लेकिन उसे वाणी को अभिव्यक्त करने की अद्भुत कला मालूम होनी चाहिए।

मीठे वचन से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और कठोर वचन से मित्र शत्रु बन जाते हैं। वाणी के चार प्रकार हैं। परा, पश्यंति, मध्यमा, बैखरी। मनुष्य अपने मन एवं हृदय की बातों को व्यक्त करने के लिए वाणी रूपी यंत्र का प्रयोग करता है। संत-महात्मा अपनी ओजस्वी वाणी से लाखों-करोड़ों व्यक्तियों को अपना बना लेते हैं। अक्षर, शब्द, वाक्य वाणी के द्वारा ही व्यक्त किए जाते हैं। कटु वाणी वाण से भी घातक, शक्तिशाली, पीड़ादायक और विनाशकारी होती है। वहीं मीठी वाणी बोलकर किसी व्यक्ति को वर्षों के लिए प्रसन्न किया जा सकता है, अपना बनाया जा सकता है। किसी क्रोधी व्यक्ति का क्रोध शांत किया जा सकता है। कटु वाणी हृदय में वर्षों तक कांटे की तरह चुभन-वेदना का आभास कराती रहती है।

ऐसे में वाणी तौलकर बोलनी चाहिए। जिस वाणी को बोलना हो, उसका परिणाम पूर्व सोचकर बोलने में ज्यादा अच्छा होता है। वाणी का संयम और नियंत्रण आवश्यक है। वाक्पटुता बहुत बड़ी कला है। कहा भी गया है कि बिना विचारे जो कहे या जो करे, वो पाछे पछताए। वाणी के द्वारा व्यक्ति लोगों के हृदय को छू लेते हैं और वे प्रेम में जान देने को तैयार रहते हैं। मीठी वाणी वशीकरण मंत्र के समान होती है। इससे व्यक्ति मोहित हो जाता है। मीठी वाणी से संसार को जीता जा सकता है।

मुकेश ऋषि

बड़ा बनने की चाहत

फिर से

हर वर्ग में बड़े होने की होड़ मची है, लेकिन बड़े होने का उत्तरदायित्व किसी के पास नहीं है

हम बड़े हैं, हम बड़े हैं यही तो! फोर्ड गाडी का विज्ञापन देखा ही होगा। सदियों से हमारी रग-रग में बसा है कि हम बड़े हैं। कोई उम्र से बड़ा है, कोई ज्ञान से बड़ा है, कोई पैसे से बड़ा है और कोई जाति से बड़ा है। बड़े होने का बहाना हर किसी के पास है। इस दौर में राजनेता कहते हैं कि हम बड़े हैं, इस पर कानून के पहरेदार कहते हैं कि हम बड़े हैं। इन सबको पीछे धकेलते हुए पत्रकार कहते हैं कि हम बड़े हैं। जनता तो सबसे बड़ी है ही। बड़े होने का दर्प सभी को है, लेकिन बड़े होने का उत्तरदायित्व किसी के पास नहीं है। मैं टीवी पर डीडी समाचार के अतिरिक्त कुछ नहीं देखती हूं। जागते रहो जैसी सनसनी फैलाने वाले समाचार बरसाती नालों की तरह होते हैं। कुछ दिन उफनते हैं फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन अपनी गंदगी का प्रभाव छोड़ जाते हैं। मीडिया जगत केवल यह सिद्ध करने में लगा है कि हम बड़े हैं, हमारे पास शक्ति है, हमारी गाड़ी बड़ी है, हमें सारे अधिकार प्राप्त हैं।

सदियों से इस देश की सबसे बड़ी समस्या यही रही है। हर वर्ग में बड़े होने की होड़ मची है। कोई ना कोई किसी ना किसी से बड़ा बन रहा है और नीचा दिखाने की मारकाट मचाने की जिद पर अड़ा है। अब तो सोशल मीडिया भी बड़ा बनता जा रहा है। अपना बड़प्पन दिखाने के स्थान पर बड़े होने की जिद इसे भी सवार है। किस समाचार को कितना दिखाना, कितनी प्रतिक्रिया करना, सोशल मीडिया भी भूलता जा रहा है। लग रहा है कि दो गाड़ियों की रेस है, दोनों एक-दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में हैं। एक गाड़ी दूसरी को कट मारकर आगे निकल जाती है तो दूसरे का बंदा चिल्लाता है कि वह कैसे हमें कट मार गया, हम बड़े हैं, उसे तू ने कैसे आगे निकलने दिया? बस हम भी ऐसे ही लगे हैं। तभी दूसरा विज्ञापन आता है, गाड़ी वाला घायल व्यक्ति को उठाकर गाड़ी में बैठाता है। हम घायल को वहीं छोड़ रहे हैं। समाज की समस्या का समाधान कैसे हो, कोई नहीं सोच रहा है। बस बड़ा कौन है, सब यही सिद्ध करने में लगे हैं।

आजादी के बाद कुछ लोगों ने बड़े होने का सर्टिफिकेट जारी करवा लिया। धीरे-धीरे वे किनारे होने लगे, बस सारा उत्पात यहीं से शुरू हुआ। क्या देश और क्या विदेश, एक ही राग गाया जा रहा है कि देश बर्बाद हो रहा है। 20 करोड़ अल्पसंख्यकों पर जुर्म हो रहे हैं! 10 साल तक देश में एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री था और उन्हें चलाने वाला भी अल्पसंख्यक ही था, फिर कैसे अत्याचार हो गया?

भारत में एक अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति अत्याचार की बात करने वाले यह नहीं समझा पा रहे हैं कि दुनिया में इतने मुस्लिम देश होते हुए भी रोहिंग्या और बांलादेशी भारत में ही शरण क्यों लेना चाह रहे हैं? यहां अत्याचार है तो शरण क्यों? हमने चूहों के लिए बिल्ली पाली, अब बिल्ली के लिए कुत्ता पाल रहे हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जज बिठाए, फिर मीडिया बनाया, लेकिन ना जज न्याय दे पाए और ना ही मीडिया तटस्थ रह पाया। अब सोशल माडिया के रूप में एक और रक्षक तैनात किया है, लेकिन वह भी अराजकता फैलाने में माहिर हो गया है। सब बड़े बन गए हैं, लेकिन दुख की बात है कि कोई बड़प्पन नहीं दिखा रहा है।

(अजित गुप्ता का कोना ब्लॉग से साभार)

मेलबाक्स

विज्ञान को मिले बढ़ावा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के तेजी से आसमान की ओर बढ़ते कदमों पर प्रकाश डालते हुए सृजन पाल सिंह ने चांद को छूने की नई चाहत शीर्षक से लिखे अपने लेख में इसरो की उपलब्धियों का जिक्र किया है। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि इसरो चंद्रयान-2 मिशन शुरू करने जा रहा है। यह दिखाता है कि भारत के वैज्ञानिक दुनियाभर के देशों के वैज्ञानिक से कम नहीं हैं। इससे यह भी पता चलता है कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें तराशने के लिए हमारी सरकारें बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई दे रही हैं। बहुत से भारतीय मूल के वैज्ञानिक दूसरे देशों में जाकर अद्भुत उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। अगर सरकारें देश में विज्ञान की पढ़ाई के लिए माहौल तैयार करें और शिक्षण संस्थानों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएं तो भारत को तकनीकी के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। आज युवा विज्ञान की पढ़ाई करने में रुचि इसलिए भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद नहीं होती कि विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद उन्हें आगे बढ़ने या फिर विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाने का मौका मिलेगा। ऐसे में आज जरूरत इस सोच को दूर करने की है। अगर सरकारें विज्ञान की पढ़ाई को देश में दुरुस्त करने के लिए गंभीरता दिखाएं तो हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति कर सकता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

संजीदगी पैदा करतीं फिल्में

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा था, लेकिन आज सिनेमा समाज का दर्पण बनकर उभरा है। वर्तमान में जब सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे मुख्यधारा की मीडिया से दूर नजर आते हैं और उनके द्वारा खाली किए गए स्थान को तमाम झगड़ों ने भर दिया है, ऐसे समय में आर्टिकल 15 और सुपर 30 जैसी फिल्में सूखे से जूझ रही धरती को बरसात जैसा सुकून देती हैं। यह महज फिल्में नहीं हैं, यह एक लड़ाई है जो सदियों से लड़ी जाती रही है। बस इस लड़ाई को बड़े पर्दे पर ला दिया गया है जिसे लड़ते हुए न जाने कितने नायक जमींदोज हो गए और निर्लज्ज समाज ने उनकी लाशों के ऊपर 21वीं सदी के भारत की इबारत गढ़ दी। जातिवाद की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार मात्र करने से मन व्यथित और प्रश्नाकुल हो जाता है। हम कैसे समाज में जी रहे हैं? कुछ ऐसी ही समस्याओं की चर्चा करती हुई फिल्म आर्टिकल 15 समाज की एक कड़वी सच्चाई को हमारे सामने रखती है और हमारे अंदर कोलाहल करते हुए कुछ प्रश्नों के अंकुर फोड़ देती है। वहीं सुपर 30 शिक्षा माफिया का जिक्र करते हुए शिक्षा जैसी पवित्र चीज में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए हमें यह संदेश देती है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि वो बनेगा जो हकदार होगा। शिक्षा में बाजारवाद किस तरह हावी है यह फिल्म इसे समझने की कोशिश करती है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फिल्म बनाने के साहस के लिए इनके निर्माताओं और निर्देशकों की सराहना होनी चाहिए और हमें भी अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ समय निकालकर इन्हें देखना चाहिए। नारों और भाषणों के बीच वैसे भी मुद्दे और समाज हाशिये पर आ गए हैं। ऐसी फिल्में जड़ हो चुके समाज में कुछ हलचल करके थोड़ी बहुत संजीदगी जरूर पैदा कर देती हैं।

मुकुल सिंह चौहान, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

महिला शक्ति की उड़ान

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण को तकनीकी कारणों से फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन इस घटनाक्रम को मिशन की असफलता नहीं मान ली जानी चाहिए। इसरो ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अत्यधिक सावधानी बरतते हुए उपग्रह के लांचिंग को स्थगित किया गया है तथा इसके लिए नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। हम देशवासी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसरो, चंद्रयान-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर इतिहास रचेगा। इस उपग्रह की खास बात यह भी है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर, तीनों प्रमुख उपकरणों को भारत में ही बनाया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह मिशन पूरी तरह से स्वदेशी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मिशन की डायरेक्टर रितु करिधल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम. वनीता दोनों महिला हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मिशन की सफलता भारतीय महिला शक्ति की भी ऊंची उड़ान साबित होने वाली है।

chandankarn9470@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी–210–211, सेक्टर–63, नोएडा
ई–मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

89 प्रतिशत भूजल का दोहन खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जबकि शेष 11 प्रतिशत का उपयोग घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है।

आजकल

भूजल के दोहन से मंडराता खतरा

नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि वर्ष 2020 तक देश के 21 बड़े महानगरों में भूजल का अभाव हो जाएगा। इन महानगरों में दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु आदि शामिल हैं। वहीं केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को एक रिपोर्ट सौंपी है कि वर्ष 2000 तक दिल्ली के करीब 27 फीसद इलाके में भूजल स्तर पांच मीटर तक था, जबकि अब करीब 11 फीसद इलाका ही ऐसा बचा है जहां जमीन के अंदर पांच मीटर की गहराई तक पानी उपलब्ध है

पंकज चतुर्वेदी
पर्यावरण मामलों के जानकार

जमीन की गहराइयों में पानी का अकूत भंडार है। यह पानी का सर्वसुलभ और स्वच्छ जरिया है, लेकिन यदि एक बार यह दूषित हो जाए तो इसका परिष्करण लगभग असंभव होता है। भारत में आबादी बढ़ने के साथ-साथ घरेलू इस्तेमाल, खेती और औद्योगिक उपयोग के लिए भूगर्भ जल पर निर्भरता साल-दर-साल बढ़ती जा रही है। पाताल से पानी निचोड़ने की प्रक्रिया में सामाजिक और सरकारी कोताही के चलते भूजल खतरनाक स्तर तक नीचे तो जा ही रहा है, जहरीला भी होता जा रहा है।

भारत में दुनिया की सर्वाधिक खेती होती है। यहां पांच करोड़ हेक्टेयर से अधिक जमीन पर जोताई होती है, इस पर 460 बीसीएम (बिलियन क्यूसेक मीटर) पानी खर्च होता है। खेतों की जरूरत का 41 फीसद पानी सतही स्रोतों से और 51 प्रतिशत भूगर्भ से मिलता है। विगत पांच दशकों के दौरान भूजल के इस्तेमाल में 115 गुना का इजाफा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली इसकी बानगी है कि हम भूगर्भ से जल उलीचने के मामले में कितने लापरवाह हैं। राजधानी के भूगर्भ में 13,491 मिलियन क्यूसेक मीटर (एमसीएम) पानी मौजूद है। इसमें से 10,284 एमसीएम पानी लवण और रसायन युक्त है। सिर्फ 3,207 एमसीएम पानी ही साफ है। दिल्ली में हर साल 392 एमसीएम भूजल का दोहन होता है। जबकि 287 एमसीएम पानी ही रिचार्ज किया जाता है। इस तरह भूजल के स्टॉक से हर साल 105 एमसीएम पानी अधिक दोहन हो रहा है।

दिल्ली के निकट बसे गुरुग्राम को भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए पसंदीदा जगह माना जाता है। यहां की आबादी करीब 25 लाख है। वर्ष 2018 में यहां पानी की अधिकतम मांग रोजाना 410 एमजीडी थी। अनुमान है कि वर्ष 2021 तक यहां की आबादी 35 लाख हो जाएगी जिनके लिए पानी की मांग 600 एमजीडी होगी। आज गुरुग्राम की पानी की मांग का आधा हिस्सा भूजल से ही पूरा होता है। यमुना नदी से नहरों से लाए गए पानी के माध्यम से बसई जलशोधन संयंत्र से 270 एमजीडी और एक अन्य संयंत्र से 140 एमजीडी पानी आता है। शेष 90 एमजीडी पानी की आपूर्ति पर माफियाओं का कब्जा है जो जमीन के भीतर से पानी निकाल कर टैंकरों के माध्यम से बेचकर व्यापक पैमाने पर कमाई करते हैं।

गुरुग्राम में भूजल के हालात गंभीर हैं। यहां जल स्तर हर साल डेढ़ से दो मीटर नीचे गिर रहा है। यहां का पानी इस स्तर पर रसायनयुक्त हो चुका है कि साधारण फिल्टर से इसके कुप्रभावों को दूर किया ही नहीं जा सकता। दिल्ली से ही सटे उत्तर प्रदेश के बागपत जिले को भूजल के मामले में डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। यहां गन्ने की खेती व्यापक पैमाने पर होती है और उसमें भूजल का इस्तेमाल होता है।

हरियाणा से सीखने की जरूरत

हरियाणा सरकार ने इस मामले में इस वर्ष एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। हरियाणा में धान की खेती छोड़ने वाले किसान को सरकार कई सुविधाओं के साथ पांच हजार रुपये प्रति एकड़ का अनुदान भी दे रही है। दरअसल राज्य सरकार यह समझ गई है कि धान की खेती के लिए किसान जमीन को बहुत गहरा छेद कर सारा पानी निकाल चुके हैं। धान की जगह मोटा अनाज उगाने से कम पानी लगेगा और भूजल भी बचेगा। वैसे पंजाब सरकार ने भी धान की बोआई का समय घटाया है। लेकिन इसका असर भूजल दोहन पर विपरीत होने की आशंका है, क्योंकि किसान कम समय में बोआई के चलते बरसात का इंतजार करने के बनिस्पत बोरवेल चलाएगा।

दुरुपयोग होने से बचाव

भूजल कभी भी पेयजल के लिए नहीं होता। इसके बावजूद भारत की बड़ी आबादी खेती के अलावा पीने के पानी हेतु इस पर निर्भर है। भारत में भूजल की अपेक्षा सतही जल की उपलब्धता अधिक है। हमारे यहां हजारों नदियां, तालाब, जोहड़ आदि हैं। समाज ने उनकी दुर्गति कर दी और आसानी से उपलब्ध भूजल पर हमला कर दिया। भारत की कृषि और पेय जलापूर्ति में उसकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। हर साल निकाले जाने वाले भूजल का 89 प्रतिशत हिस्सा सिंचाई क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। नौ फीसद पीने व घरेलू निस्तार में और कारखानों में दो फीसद पानी का इस्तेमाल होता है। शहरों में जल की 50 प्रतिशत और गांवों में जल की 85 प्रतिशत घरेलू आवश्यकता भूजल से पूरी होती है।

पानी निचोड़ने से बेहाल धरती

हाल ही में लोकसभा से साझा किए गए केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार देश के 16 फीसद तालुका, मंडल, ब्लॉक स्तरीय इकाइयों में भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है। जबकि देश के चार फीसद इलाकों में भूजल स्तर इतना गिर चुका है कि इसे 'विकट स्थिति' या डार्क जोन बताया जा रहा है। हद से ज्यादा भूजल का दोहन करने वाले राज्य हैं- पंजाब (76 फीसद), राजस्थान (66 फीसद), दिल्ली (56 फीसद) और हरियाणा (54 फीसद)। इस संस्थान ने 6,584 ब्लॉक, मंडलों, तहसीलों के भूजल स्तर का मुआयना किया है। इनमें से केवल 4,520 इकाइयां ही सुरक्षित हैं, जबकि 1,034 इकाइयों को अत्यधिक दोहन की जाने वाली श्रेणी में डाला गया है। इसमें 681 ब्लॉक, मंडल के भूजल स्तर में (जो कुल संख्या का 10 फीसद है) अर्ध विकट श्रेणी में रखा गया है, जबकि 253 को विकट श्रेणी में रखा गया है। ये आंकड़े 2013 के मूल्यांकन के आधार पर हैं जिसके अनुसार 6,584 ब्लॉक, तालुका, मंडलों, जल क्षेत्रों में 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 1,034 इकाइयों का अत्यधिक दोहन किया गया है। इससे भूजल स्तर नीचे चला गया है। अत्यधिक दोहन वाले वह स्थान कहे जाते हैं जहां लंबी अवधि में जलस्तर में कमी देखी गई हो।

और भी खतरे हैं इसके

देश के कई हिस्सों में जमीन फटने की घटनाएं आमतौर पर सामने आती रहती हैं। बुहत सी जगह कुओं के पानी का स्तर अचानक नीचे गिर जाने या तालाब का पानी गायब होने की बातें सुनने में आती हैं। असल में यह सब अनियोजित और अनियंत्रित भूजल दोहन का दुष्प्रभाव ही है। भूजल दोहन का सबसे बड़ा खतरा भूकंप है। हम जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे जवान पहाड़ हिमालय की गोद में बसा है। हिमालय लगातार बढ़ रहा है और इसके कारण हमारे भूगर्भ में सतत टकराव व गतिविधियां चलती रहती हैं। किसी स्थान से अचानक पानी निकालने या चट्टानों को मशीनों से तोड़ कर पाताल से पानी निकालने वालों के लिए स्पेन से सबक लेना होगा। स्पेन के लरका शहर में 2011 में आए एक भूकंप के कारणों ने हमारी पेशानी में बल दिए हैं। स्पेन के इस शहर में आया विनाशकारी भूकंप चंद सेकेंड में पूरे शहर को लील गया था। वैज्ञानिक जांच से पता चला था कि यहां भूकंप का कारण अत्यधिक जलदोहन था। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑनटेरियो के प्रोफेसर पैब्लो गॉनजालेज और उनके सहयोगियों ने सेटेलाइट राडार के जरिये भेजे गए आंकड़ों के अध्ययन के बाद पाया कि स्पेन के शहर लरका में आए भूकंप में भूमि सतह के केवल तीन किलोमीटर नीचे जमीन का एक हिस्सा अपनी जगह से फिसला था। वैज्ञानिकों के अध्ययन से पता चला है कि किस तरह बोरिंग के जरिये वर्षों तक जमीन से पानी निकालने से भूकंप आने का खतरा बढ़ सकता है।

जलापूर्ति का बहुमूल्य स्रोत है भूजल

बरसात होने पर जो पानी चट्टानों और मिट्टी से रिस कर भूमि के नीचे जमा हो जाता है, वही भूजल या भूमिगत जल है। जिन चट्टानों की शरण में भूजल जमा होता है, उन्हें जलभृत (एक्विफर) कहा जाता है। सामान्य तौर पर, जलभृत बजरी, रेत, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से बने होते हैं। इन चट्टानों से पानी नीचे बह जाता है, क्योंकि इनके बीच में ऐसी बड़ी और परस्पर जुड़ी हुई जगहें होती हैं, जो चट्टानों को पारगम्य (प्रवेश के योग्य) बना देती हैं। जलभृतों में जिन जगहों पर पानी भरता है, वे संतृप्त जोन (सैचुरेटेड जोन) कहलाते हैं। सतह में जिस गहराई पर पानी मिलता है, वह जल स्तर कहलाता है। जल स्तर जमीन से नीचे एक फुट तक उथला भी हो सकता है और वह कई मीटर गहराई तक भी हो सकता है। भारी वर्षा से जल स्तर बढ़ सकता है और लगातार दोहन करने से इसका स्तर गिर भी सकता है। भारतीय प्रायद्वीप में कठोर चट्टान वाले जलभृत ज्यादा हैं, लगभग 65 फीसद। इनमें से अधिकांश मध्य भारत में ही हैं। यहां जमीन की कुछ गहराई के बाद कठोर चट्टानों का राज है। इन चट्टानों से सतह पर ऐसी जटिल और निम्न संग्रहण वाली जलभृत व्यवस्था तैयार होती है कि अगर एक बार जल स्तर में दो-छह मीटर से अधिक की गिरावट हो जाती है तो फिर जल स्तर तेजी से गिरने लगता है। इन जलभृत की भेद्यता बहुत कम है जिस कारण बारिश होने पर भी वे दोबारा जल्दी नहीं भरते। इसका अर्थ यह है कि इन जलभृतों का पानी दोबारा भरने योग्य नहीं है और निरंतर प्रयोग किए जाने के कारण सूख सकता है। सिंधु-गंगा के मैदानों में कछारी जलभृत में पानी के संग्रहण की अद्भुत क्षमता है। इसलिए इन्हें जलापूर्ति का बहुमूल्य स्रोत माना जाता है। फिर भी भूजल को बड़े पैमाने पर उलीचा जा रहा है, जबकि इन स्रोतों के दोबारा भरने की दर निम्न है।

सामुदायिक जल प्रबंधन पर ज्यादा जोर

देश के 360 जिलों को भूजल स्तर में गिरावट के लिए खतरनाक स्तर पर चिन्हित किया गया है। भूजल रिचार्ज के लिए तो कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन खेती, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण जहर होते भूजल को लेकर लगभग निष्क्रियता का माहौल है। बारिश, झील व तालाब, नदियों और भूजल के बीच यांत्रिकी अंतर्संबंध है। जंगल और वृक्ष वाटर रिचार्ज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रक्रिया में कई जहरीले रसायन जमीन के भीतर रिस जाते हैं। दूषित पानी पीने के कारण कई इलाकों में त्वचा रोग, पेट खराब होना आदि महामारी का रूप ले चुका है।

भारत में खेती, पेयजल व अन्य कार्यों के लिए अत्यधिक जल दोहन से धरती का भूजल भंडार अब दम तोड़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 5,723 ब्लॉकों में से 1,820 ब्लॉक में जल स्तर खतरनाक हद पार कर चुका है। जल संरक्षण न होने और लगातार दोहन के चलते 200 से अधिक ब्लॉक ऐसे भी हैं, जिनके बारे में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने संबंधित राज्य सरकारों को जल दोहन पर पाबंदी लगाने का सुझाव दिया है। लेकिन कई राज्यों में इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा सका है। उत्तरी राज्यों में हरियाणा के 65 फीसद और उत्तर प्रदेश के 30 फीसद ब्लॉकों में भूजल का स्तर चिंताजनक हो चुका है। इन राज्यों को जल संसाधन मंत्रालय ने अंधाधुंध दोहन रोकने के कई उपाय भी सुझाए हैं। इनमें सामुदायिक भूजल प्रबंधन पर ज्यादा जोर दिया गया है। राजस्थान जैसे राज्य में 94 प्रतिशत पेयजल योजनाएं भूजल पर निर्भर हैं। और अब राज्य के 30 जिलों में जल स्तर का सब्र समाप्त हो गया है। भूजल विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दो सालों में राजस्थान के 140 ब्लॉकों में शायद ही जमीन से पानी उलीचा जा सकेगा। ऐसे में यह समस्या और गहरा सकती है।

खरी-खरी

'तरबतर' होने की कामना

डॉ. अतुल चतुर्वेदी

वे बोले- कुछ भी कहें, बरस तो रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। मैंने पूछा- कौन सी बात? अजी वही मजे वाली बात...! बारिश के दिन याद कीजिए जब मामला तरबतर हो जाता था। सड़कों पर नावें निकल आती थीं और विभाग बाढ़ राहत के लिए बड़ा बजट आवंटित करता था।

मैंने कहा, कभी गरीबों की भी सोचें जो खुले आकाश तले पड़े हैं और रोज कमाकर खाते हैं। लेकिन वो कहां सोचने वाले थे। उन्हें तो तरबतर होने का जुनून सवार था। चहकते हुए बोले, कोई भी हो साहब, एक बार उन्मुक्त होकर भीगना चाहता है, क्योंकि हर शख्स के अंदर एक बच्चा मौजूद रहता है जो वातावरण देखकर बाहर आने को छटपटाता है। फिर उन्होंने तुरंत अपनी दार्शनिकता पर काबू किया और भौतिकता की पिच पर गेंदें डालने लगे। तीन बार विभाग को रिमाइंडर भेज चुका, लेकिन कानों पर जूं ही नहीं रेंग रही। अब इस बार बरस ही नहीं रहा, न बस्तियां डूब रही हैं, बस नदी का जलस्तर ही बढ़ने की खबरें आ रही हैं। सर्दियों में ठंड भी कायदे की नहीं पड़ी। न शीत प्रकोप से दो-चार मरे। कंबल बंटते, अलाव के बजट जलते तो दो-चार परिवार हरिया जाते।

मैंने पूछा, आजकल कहां हैं आप? अरे भाई, हूं तो आपदा प्रबंधन में, लेकिन आपदा आए तब न प्रबंधन करूं! वो अतीत की गलियों में निकल लिए...पहले तो बरसात के दिनों में टॉर्च, बरसाती, छाते और भोजन के पैकेट्स आदि से ही बच्चों की स्कूल की साल भर की फीस जमा हो जाती थी। समझिए, जित्ती झमाझम बारिश, उत्ते तरबतर हम। अब देखिए मानसून इतना बेवफा हो गया है कि चाहे मेघदूत बांचो या कुछ और, पसीजता ही नहीं। न नायिकाएं बिजुरी की चमक देख सीने से चिपकती हैं, न बागों में बेटियां झूलों पर पेंगे लेती हैं। नई पीढ़ी तो पैग और स्वैग में ही व्यस्त है जी।

इन दिनों वे रोज लौटते में नदी के पुल पर से होते हुए घर जाते हैं। नदी के जलस्तर और खतरे के निशान का फासला देख उनका दिल डूबा-डूबा हो जाता है। कल बोले, देखो नासा के वैज्ञानिकों ने बारिश वाले बादल बना डाले, ये हमारे वाले क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, वे मंगल पर काम कर तो रहे हैं! वे खीझकर बोले- अरे मंगल पर कौन-सी बस्ती डूब रही है जो वहां लगे पड़े हैं! यहां बरसात नहीं होने से हम जैसों के दिल और घर दोनों डूब रहे हैं। जरा यहां बादल-वादल फटवाएं तो हम तैरें!

ट्वीट-ट्वीट

नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि बारिश के कारण मैच रद होने पर दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जाता। तब आखिर स्कोर बराबर होने और फिर सुपर ओवर में बराबरी के बाद आखिर क्या बदल गया?

डीन जोंस@ProfDeano

यह समझ नहीं आता कि विश्व कप फाइनल जैसे मुकाबले का नतीजा बाउंड्री लगाने के आधार पर हो। यह आइसीसी का हास्यास्पद नियम है। इससे बेहतर इसे टाई घोषित किया जाता। बेहद कांटे का फाइनल मुकाबला खेलने वाली इंग्लैंड और न्यूजीलैंड टीम को बधाई।

गौतम गंभीर@GautamGambhir

इस विश्व कप के लिए संयुक्त विजेता घोषित होने चाहिए थे। अगर इंग्लैंड ने बाउंड्री अधिक लगाईं तो न्यूजीलैंड ने अधिक विकेट चटकाए। आइसीसी का पैमाना गलत है। सभी 22 खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया और कोई किसी से कम नहीं था। तब आखिर 11 को ही यह क्यों महसूस हो कि वे दूसरों से बेहतरीन थे।

शाहिद कपूर@shahidkapoor

कुशल कोठियाल
राज्य संपादक, उत्तराखंड

उत्तराखंड डायरी

सियासत में छाया रहा तमंचे पर डिस्को

हरिद्वार जिले के खानपुर क्षेत्र के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खुद के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की भी अच्छी खासी किरकिरी कर डाली। तंमचे पर डिस्को करने वाले चैंपियन का यह चरित्र भाजपा के लिए काफी समय से गरम दूध बना हुआ था। अनुशासनहीनता के मामले में तीन माह का निलंबन झेल रहे चैंपियन अब बर्खास्तगी की कगार पर हैं। चैंपियन जब कांग्रेस में भी रहे तो पार्टी एवं सरकार के लिए परेशानी पैदा करते रहे। कांग्रेस से बगावत कर जब भाजपा से जुड़े तो सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई थी कि भाजपा चैंपियन को कैसे पचा पाएगी। और हुआ भी यही, भाजपा ने वादे के मुताबिक विधानसभा का टिकट तो दे दिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी अनुशासन में नहीं रख पाई। कई मौकों पर पार्टी को अपने इस विधायक की हरकतों के चलते शर्मसार होना पड़ा। विधानसभा में संख्या दृष्टि से मजबूत भाजपा को चैंपियन से दामन छुड़ा लेना ही ज्यादा मुनासिब लगा। अब उनके तीन असलहों के लाइसेंस भी निरस्त किए जा चुके हैं, जिनके दम पर वह डिस्को और जनता को भयभीत करते रहे हैं। वर्तमान में कोई राजनीतिक पार्टी उन्हें अपनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। यहां तक कि बसपा ने भी दरवाजे बंद कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अपराधियों को दलों में समायोजित किया जा सकता है, लेकिन तमाशा करने वालों को पार्टी का बैनर देना संभव नहीं है। खासतौर पर उत्तराखंड जैसे राज्य में।

आपसी होड़ में कांग्रेस सक्रिय : कांग्रेस आजकल प्रदेश में खासी सक्रिय दिख रही है। इसकी वजह भी अजीबोगरीब है। ऐसा नहीं कि पार्टी नेता एकजुट हो कर जनता के मुद्दों पर सड़कों पर उतर रहे हैं या इसका उद्देश्य राज्य में कांग्रेस को मजबूत करना है। दरअसल इसकी असली वजह पार्टी की धड़ेबंदी में छिपी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दे कर राज्य की जमीनी राजनीति में सक्रियता क्या दिखाई, दूसरे धड़े ने भी प्रदेश कांग्रेस में पकड़ बनाए रखने के लिए सक्रियता को नए सिरे से धार देना शुरू कर दिया। इस आपसी होड़ के चलते प्रदेश में कांग्रेस जिंदा सी दिखाई देने लगी है। कभी हरीश रावत की अगुआई में गिरफ्तारी दी जा रही है तो कभी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में जुलूस प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपाई बेफिक्र इसलिए बैठे हैं कि वास्तव में प्रदर्शन भाजपा सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही एक-दूसरे धड़े के खिलाफ है। अलबत्ता कांग्रेस कार्यकर्ता इसलिए खुश हैं कि एक-दूसरे के खिलाफ ही सही, लेकिन पार्टी के झंडे-बैनर दिखाई तो दे रहे हैं।

मोदी बिन सब सून : विगत सप्ताह बाजपुर एवं श्रीनगर नगर पालिका परिषद के प्रतिष्ठित चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से मुंह की खानी पड़ी। इन दोनों सीटों पर राज्य के दो मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, लिहाजा प्रत्याशी चयन में भी उनकी मर्जी चली। मंत्री की मर्जी पर पूर्व में हरिद्वार नगर निगम में बुरी तरह मुंह की खाई भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया और इस बार भी दो महत्वपूर्ण निकायों को मंत्रियों के रहमोकरम पर छोड़ दिया। अब भाजपा के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि विधानसभा एवं लोकसभा में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर अच्छे वोट समेट लिए, लेकिन निकायों के चुनाव में मोदी का नाम नहीं था इसलिए हार का मुंह देखना पड़ा। पार्टी के गंभीर, लेकिन हाशिये पर खड़े नेताओं का मानना है चुने हुए माननीयों एवं मंत्रियों की जनता से सीधा संवाद टूटता जा रहा है। ढीली पड़ती पकड़ ही इन दोनों निकायों के परिणामों में दिखाई दी है।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

कांग्रेस की राज्य इकाइयों में अस्थिरता शीर्ष नेतृत्व में अनिश्चितता के कारण उत्पन्न हुई है?

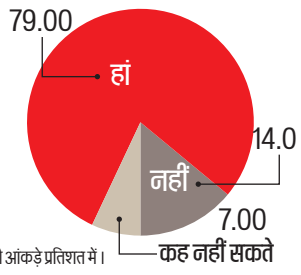

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या चौके-छक्कों से विश्व कप विजेता तय करने का आइसीसी का नियम सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

विश्वविजेता बन गया आज भले इंग्लैंड,
किंतु न रत्ती भर कहीं कम था न्यूजीलैंड।
कम था न्यूजीलैंड बराबर की थी टक्कर,
दिलवा बैठा हार नियम का बेढब चक्कर।
पा दूजा स्थान रहो खुश कीवी बेटा,
बना क्रिकेट का बाप आज जब विश्वविजेता।

– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

निजी क्षेत्र की जवाबदेही का सवाल

वर्ष 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंक और कोयला आदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन धीरे-धीरे सरकारी बैंकिंग सिस्टम की खामियां सामने आने लगीं। आज बाजार के दबाव में फिर से निजीकरण की राह अपनाई जा रही है

हरेंद्र प्रताप
पूर्व सदस्य, बिहार विधान परिषद

हाल के वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। बैंकिंग/ बीमा, उड्डयन और दूरसंचार आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के प्रवेश से आज उपभोक्ताओं के समक्ष विकल्प की कमी नहीं है। आजादी के बाद देश भर में निजी क्षेत्र में केवल टाटा, बिड़ला और डालमिया के नाम ही लोगों की जुबान पर थे। केंद्र की सत्ता में आने से पहले तक चुनावों के दौरान विपक्ष में रहने वाली भाजपा, कांग्रेस पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का उसी प्रकार आरोप लगाती थी, जिस प्रकार आजकल अंबानी और अडानी को संरक्षण देने का आरोप लगाया जा रहा है। पहले नारा था- टाटा-बिड़ला की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आजकल नारा है- अंबानी-अडानी की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।

कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से ध्यान हटाने के लिए वर्ष 1969 में इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया तथा राजा-महाराजाओं को दिए जाने वाले पेंशन (प्रिवीपर्स) को समाप्त कर बैंक, कोयला आदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में यह दलील दी कि बैंकों में आम जनता अपनी बचत का धन जमा करती है, पर निजी बैंक न तो आम जन को कर्ज देते हैं और न ही आम जन के विकास के लिए सरकारी योजनाओं में अपनी रकम लगाते हैं। कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया था कि अब आम जन का धन सुरक्षित है, क्योंकि कोई निजी बैंक अब उनका धन लेकर फरार नहीं हो सकता।

राष्ट्रीयकरण के हिमायती वामपंथियों ने इसका पुरजोर स्वागत इसलिए किया था, क्योंकि 'निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों को काम का प्रदर्शन ठीक नहीं रहने पर कभी भी नौकरी चले जाने का जो भय' बना रहता है वह समाप्त हो गया था। उनके मजदूर संगठनों ने इसे अपने संघर्ष के विजय के रूप में देखा था।

माना कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उन पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ और सरकार ने आम जन के विकास में बैंकों में जमा आम जन के धन का उपयोग भी किया, पर सरकारी बैंकों की सेवा का स्तर लगातार गिरने लगा। सरकारी बैंकों की सेवा से जो निराशा उत्पन्न हो रही थी, उसका आकलन कर एक बार फिर से निजी क्षेत्र ने बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर पकड़ मजबूत कर ली है।

सरकारी बैंकों में बचत पर मिलने वाला ब्याज साल दर साल घटता जा रहा है। बचत पर ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर लूटने के लिए हजारों चिटफंड कंपनियां बाजार में कूद गईं और आम जनता के हजारों करोड़ रुपये लूट कर फरार हो गईं। पश्चिम बंगाल के शारधा और रोज वैली चिट फंड घोटाले में राजनेताओं की संलिप्तता सामने आई है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई को ज्यादा ब्याज के लालच में इन संगठनों में जमा किया था, लेकिन आज वे ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

निजी क्षेत्र के लुटेरों ने न केवल आम जन को लूटा, बल्कि राजनेताओं और सरकारी बैंक के लोगों से मिलीभगत करके सरकारी बैंकों को भी लूटा। विजय माल्या, नीरव मोदी आदि तो भाग कर विदेश चले गए, पर लगभग चार लाख करोड़ रुपये का जो एनपीए है, उसमें कौन-कौन शामिल हैं, यह उजागर होना शेष है। आए दिन सरकारी बैंकों के घोटाले परत दर परत खुल रहे हैं। ताजा मामला भूषण स्टील का सामने आया है। बैंकों से चार हजार करोड़ रुपये के कर्ज के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है।

इसी तरह भारत में हवाई यात्रियों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर विमानन उद्योग का तेजी से विकास हुआ। विमानन क्षेत्र में उतरे निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों ने क्या-क्या गुल खिलाया यह सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। निजी क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों ने एयर इंडिया के महत्वपूर्ण रूट और समय पर अपना कब्जा जमाया। निजी क्षेत्र के भी छोटे-मोटे कारोबारी इनके समक्ष घुटने टेकने को बाध्य हुए। डेक्कन एयरवेज को विजय माल्या के किंगफिशर ने तथा सहारा एयरलाइंस को जेट एयरवेज ने बाजार से बाहर कर दिया।

निजी क्षेत्र की कंपनियों को महत्व देने के पीछे जो तर्क दिए जाते हैं कि इनका प्रबंधन और संचालन सही ढंग से होने के कारण ये मुनाफे में रहती हैं, यह देश की कसौटी पर सही साबित नहीं हो पा रहा है। किंगफिशर के विजय माल्या और जेट एयरवेज के नरेश गोयल का उदाहरण सबके सामने है। विजय माल्या तो देश से भाग गए और नरेश गोयल को हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। आज जेट एयरवेज के करीब 20 हजार कर्मचारियों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रबंधन और संचालन को सुधार कर अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों को निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय कैबिनेट ने अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ हवाई अड्डे को पीपीपी यानी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत अडानी इंटरप्राइजेज ग्रुप को 50 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया है। अब इन हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास की जवाबदेही इसी कंपनी की है। पीपीपी मोड के तहत अडानी इंटरप्राइजेज ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहले ही हासिल कर लिया था। केंद्र सरकार ने रेलवे में भी निजीकरण को बढ़ावा देना तय किया है। रेलवे स्टेशनों के रखरखाव के साथ ही जल्द ही पटरियों पर दौड़ने वाली 'तेजस एक्सप्रेस' को निजी क्षेत्र को देने की तैयारी कर ली गई है।

कुल मिलाकर पीपीपी मोड पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी असफलता का पर्याय है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भविष्य में कोई भारत में घोटाला कर विदेश न भाग जाए इसके लिए प्रभावकारी और परिणामकारी कदम उठाने होंगे।

राष्ट्रीय संस्करण
मंगलवार 16 जुलाई 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

गेल का दो कंपनियों में हो सकता है विभाजन

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार गेल (इंडिया) लिमिटेड को दो कंपनियों में बांटना चाहती है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि गेल के पाइपलाइन कारोबार को अलग कर एक नई कंपनी बनाने और उसे रणनीतिक निवेशक को बेच देने की योजना पर काम चल रहा है। गेल प्राकृतिक गैस के मार्केटिंग और व्यापार के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा देश के 16,234 किलोमीटर के पाइपलाइन नेटवर्क में से दो-तिहाई से अधिक हिस्से पर गेल का अधिकार है।

आइएमएआइपी बुलियन एंड ट्रेडिंग के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को शिकायतें मिली थीं। इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
– अनुराग ठाकुर, वित्त राज्यमंत्री

सेंसेक्स 38,896.71 ▲ 160.48	निफ्टी 11,588.35 ▲ 35.85	सोना प्रति दस ग्राम ₹ 35,470 ▼ ₹100	चांदी प्रति किलोग्राम ₹39,175 ▼ ₹25	डॉलर ₹68.54 ▼ ₹0.15	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल $ 66.75

कारपोरेट हलचल

असम में कछार, हेलाकांडी, करीमगंज और कामरूप जिले में सिटी गैस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए गेल इंडिया ने दो अन्य कंपनियों के साथ करार किया है। कंपनी ने असम गैस कंपनी लिमिटेड और ऑयल इंडिया के साथ गुवाहाटी में इस आशय के एक करार पर हस्ताक्षर किये। असम गैस की भागीदारी 48 फीसद और ऑयल इंडिया व गेल की हिस्सेदारी 26-26 फीसद की रहेगी।

चौधरी बने एआइसी के कार्यवाहक सीएमडी

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया (एआइसी) के महाप्रबंधक राजीव चौधरी को कंपनी का कार्यवाहक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चौधरी भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद से स्नातकोत्तर हैं। चौधरी एलएलबी व एलएलएम भी हैं।

जुलाई के पहले पखवाड़े में मनाए गए स्वच्छता पखवाड़े के दौरान नोएडा स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पाइपलाइंस मुख्यालय में स्वच्छता पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा की अध्यक्षता पाइपलाइंस विभाग के कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) गौतम घोषाल ने की। पदयात्रा का उद्देश्य कार्यालय के आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता कराना था।

बीमा लेने का फैसला किसानों पर छोड़ने की तैयारी

खामियों को दूर करने के लिए पीएमएफबीवाई में हो रहा बदलाव

प्रस्तावित बदलावों पर केंद्र सरकार ने राज्यों से मांगी है उनकी राय

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की सदस्यता लेने का फैसला पूरी तरह से किसानों पर ही छोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने पर विचार हो रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा कि योजना में प्रस्तावित बदलावों में सभी किसानों के लिए फसल बीमा को वैकल्पिक बनाना, ऊंचे प्रीमियम वाले फसलों को योजना से बाहर करना और राज्यों को उनकी पसंद के उत्पाद जोड़ने की अनुमति देना भी शामिल है। प्रस्तावित बदलावों पर राज्यों की राय मांगी गई है।

अधिकारी ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने 'स्टेट लेवल कॉर्पस फंड' स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा बचत को एक राष्ट्रीय स्तर के इंश्योरेंस रिस्क पूल में स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव है, ताकि आम लोगों की इस धारणा को दूर किया जा सके कि इस योजना से बीमा कंपनियां फायदा उठा रही हैं। इसके अलावा प्रीमियम की अधिकतम सीमा का भी प्रस्ताव है। इसके तहत किसी फसल के लिए सींचित क्षेत्र यदि 50 फीसद से अधिक होगा, तो अधिकतम प्रीमियम 25 फीसद होगा। प्रीमियम की दर में सालाना आधार पर संशोधन होगा। किसी फसल के लिए सींचित क्षेत्र यदि 50 फीसद से कम होगा, तो उस फसल के लिए अधिकतम प्रीमियम 30 फीसद तय करने का प्रस्ताव है।

पीएमएफबीवाई की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। इसके तहत बोआई के पहले से लेकर फसल की कटाई के बाद तक के लिए अपरिहार्य प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध व्यापक फसल बीमा उपलब्ध कराया जाता है। खरीफ फसलों के लिए इसका प्रीमियम दो फीसद, रबी फसलों के लिए 1.5 फीसद और बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए पांच फीसद है। मंत्रालय ने इस योजना में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए कई बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है और इस पर राज्यों की राय मांगी है।

प्रमुख प्रस्तावित बदलावों में कर्ज लेने वाले किसानों सहित सभी किसानों के लिए योजना को वैकल्पिक बनाने का सुझाव है। इसका कारण यह है कि कर्ज लेने वाले किसानों की अनिवार्य सदस्यता के प्रावधान के कारण इस योजना के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। मंत्रालय ने फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए उपज का मूल्यांकन करने की दो चरणों वाली प्रक्रिया का भी सुझाव दिया है।

डेढ़ सौ जिलों पर जलवायु परिवर्तन की मार सबसे पहले

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश के डेढ़ सौ जिलों पर जलवायु परिवर्तन की मार सबसे पहले पड़ने वाली है। इसका सबसे बुरा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा। इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले 151 जिलों को चिन्हित उनके हिसाब से योजनाएं तैयार की गई हैं, जो बाढ़ और सूखे से प्रभावित होने वाले जिलों में लागू की जाएंगी।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए सूखा व बाढ़-रोधी बीज तैयार किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा बारिश होने, सूखा पड़ने और तापमान बढ़ने की दशा में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए ऐसे बीजों की सख्त जरूरत होगी। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हीं की बदौलत देश न सिर्फ खाद्यान्न पैदावार में आत्मनिर्भर, बल्कि दुनिया के खाद्यान्न निर्यातकों में शामिल हो गया है। जावड़ेकर ने एक पूरक सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन से कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है। इसके मुताबिक देश में चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली, चना और आलू जैसी फसलों पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।

मंत्री ने कहा कि खतरे के कगार पर खड़े इन जिलों में आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जा रहा है। फसलों के साथ पशुधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि मौसम के बिगड़े मिजाज में स्थानीय किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इससे पहले किसानों को प्रशिक्षण के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। जावड़ेकर ने कहा कि देश के 33 राज्यों ने जलवायु परिवर्तन की चेतावनी को गंभीरता से लेकर प्राथमिकता पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।

दो साल के निचले स्तर पर थोक महंगाई

- जून में थोक महंगाई की दर 2.02 फीसद पर आई
- आयात में कमी से व्यापार घाटे में गिरावट, 15.28 अरब डॉलर रहा घाटा

कच्चे तेल का दाम स्थिर रहने से महंगाई दर नियंत्रण में। फाइल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सब्जियों और ईंधन वर्ग में कीमतों के नीचे आने से थोक मूल्यों पर आधारित महंगाई की दर में लगातार दूसरे महीने गिरावट जारी रही। जून 2019 में थोक महंगाई की दर 2.02 फीसद पर आ गई है। यह पिछले 23 महीने में सबसे कम है। उधर विदेश व्यापार के मामले में जून का महीना मिलाजुला रहा। इस दौरान निर्यात में 9.71 फीसद की कमी आई, लेकिन व्यापार घाटा घटकर 15.28 अरब डॉलर (करीब 1.05 लाख करोड़ रुपये) पर आ गया। निर्यात में नौ महीने के बाद गिरावट आई है। इससे पहले सितंबर 2018 में निर्यात में 2.15 फीसद गिरावट दर्ज की गई थी।

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई की दर मई 2019 में 2.45 फीसद पर थी। जबकि जून 2018 में यह 5.68 फीसद पर रही थी। खाद्य वस्तुओं के सूचकांक वर्ग में महंगाई की दर जून में मामूली घटकर 6.98 फीसद पर आ गई। यह मई 2019 में 6.99 फीसद पर थी।

महंगाई की दर में कमी लाने में सब्जियों की कीमत की भूमिका अहम रही। जून में सब्जियों की महंगाई दर मई के 33.15 फीसद से घटकर 24.76 फीसद पर आ गई। आलू के दामों में महंगाई दर शून्य से 24.77 फीसद नीचे रही। लेकिन प्याज की कीमतों में बढ़त अभी भी बनी हुई है। इसकी महंगाई दर मई के 15.89 फीसद से बढ़कर जून में 16.63 फीसद पर पहुंच गई। जुलाई 2017 के बाद जून के महीने में यह यह अब तक की सबसे कम थोक महंगाई दर है। उस वक्त यह 1.88 फीसद रही थी।

जहां तक विदेश व्यापार के मोर्चे पर प्रदर्शन की बात है तो निर्यात के मामले में जून का महीना खराब बीता। इस अवधि में निर्यात घटकर 25 अरब डॉलर पर आ गया। पिछले साल के इसी महीने में देश से 27.7 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। निर्यात में कमी जेम एंड ज्वैलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और पेट्रोलियम उत्पादों के शिपमेंट में गिरावट की वजह से आई।

दूसरी तरफ जून में आयात में भी नौ फीसद की कमी आई। पिछले महीने देश में 40.29 अरब डॉलर का आयात हुआ। जबकि जून 2018 में 44.3 अरब डॉलर का आयात हुआ था। निर्यात के साथ-साथ आयात में भी कमी के चलते व्यापार घाटा जून 2018 के 16.6 अरब डॉलर से घटकर पिछले महीने 15.28 अरब डॉलर रह गया।

सुधारों को प्रोत्साहन की जगह मोटर बिल में जुर्माने पर जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दुर्घटना पीड़ितों को फौरी मामूली हर्जाने से बीमा कंपनियों को होगा फायदा
- अनपढ़ ड्राइवर नई तकनीक व प्रक्रियाओं को समझने में होंगे असमर्थ

लोकसभा में पेश मोटर संशोधन बिल का मकसद दुर्घटना के मूल कारणों को दूर करने के बजाय नियम तोड़ने वालों, विशेषकर वाहन चालकों से दंड के नाम पर अधिकाधिक जुर्माना वसूलने पर है। इसमें दुर्घटना के शिकार लोगों के मुकाबले बीमा कंपनियों तथा ट्रांसपोर्टरों की सुविधा का ज्यादा ख्याल रखा गया है।

नया बिल 1988 के पुराने मोटर एक्ट में संशोधन के लिए लाया गया है। इसके लिए पुराने बिल में 88 संशोधन किए गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के संयोजक एसपी सिंह का कहना है कि यदि इतने अधिक संशोधन करने थे, तो सरकार नया विधेयक ही ले आना चाहिए था। वर्ष 2014 में पहले कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने सड़क परिवहन सुरक्षा एवं प्रबंधन विधेयक के जरिए यही किया था। उसमें अमेरिकी और आस्ट्रेलियाई मोटर कानूनों के सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों जैसे हादसे में मृत्यु पर 20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति, नियम उल्लंघन करने पर ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित और रद करने, ओवरलोडिंग करने वाली या अनफिट गाड़ी को जब्त करने तथा त्रुटिपूर्ण वाहन बनाने वाले निर्माता पर जुर्माना लगाने जैसे प्रभावकारी प्रावधान थे। लेकिन इससे स्थिति में कोई विशेष बदलाव आएगा, इसमें संदेह है। तीस वर्षों में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हालात, सड़कें, वाहनों की तकनीक और ड्राइविंग के तौर-तरीके एकदम बदल चुके हैं। ऐसे में संशोधनों के बजाय नए बिल की जरूरत थी।

बिल में यातायात उल्लंघन करने वाले चालकों पर पांच-दस गुना अधिक जुर्माना लगाकर दुर्घटनाओं में कमी की कल्पना की गई है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जुर्माने बढ़ाने से हादसों में कमी नहीं होती। इससे पहले केंद्रीय मोटर नियमावली के जरिये जुर्माने की राशि बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वैसे भी सारे जुर्माने चालकों से वसूले जाते हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा मिलेगा, मगर हादसे कम होने की कोई गारंटी नहीं।

बिल में ड्राइवरों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, जो अभी आठवीं पास है, को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। तर्क दिया गया है कि मेवात क्षेत्र में अनेक कुशल ड्राइवर हैं, लेकिन अनपढ़ होने के कारण उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। इस छूट से उनके लाइसेंस बनेंगे जिससे बेरोजगारी दूर करने में मदद मिलेगी। लेकिन वर्तमान में नई तकनीक के वाहनों के साथ सड़क व टोल ढांचे का आधुनिकीकरण हो रहा है। प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के अलावा नियम-कायदे जटिल होते जा रहे हैं। ऐसे में अनपढ़ ड्राइवर इन चुनौतियों का किस तरह मुकाबला करेंगे, यह सोचने का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तव में तो ड्राइवरों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाए जाने तथा उनके वेतन और कार्यदशाओं को सुधारे जाने की जरूरत है। इससे इंटर पास और ग्रेजुएट युवा ड्राइविंग के पेशे में आते। इससे देश में ड्राइविंग का स्तर सुधारने और हादसे कम करने में मदद मिलती।

एसपी सिंह के मुताबिक बिल अपने नए स्वरूप में दुर्घटना पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के मौजूदा नियमों को शिथिल करता है। मौजूदा कानून में क्षतिपूर्ति का फैसला एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल करता है जिसमें मृतक और घायल के लिए उसकी आयु, आय, आश्रितों के अनुसार हर्जाने का प्रावधान है जो हजारों से लाखों और करोड़ों रुपये में जा सकता है। परंतु अब तुरंत राहत के नाम पर मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि को अधिकतम 5 लाख रुपये तथा घायल होने पर ढाई लाख रुपये पर सीमित कर दिया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे ज्यादातर मामलों में बीमा कंपनियां न्यून राशि देकर बच निकलेंगी। क्योंकि हादसे के बाद पीड़ित की मनस्थिति यह होती है कि तत्काल जो मिल रहा है उसे ले ले लिया जाए। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब प्रीमियम पर कोई सीमाबंदी नहीं है तो क्षतिपूर्ति पर कैसे हो सकती है।

लॉजिस्टिक्स टर्मिनल के लिए भेल ने किया सीसीआइ से करार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) अब रेल लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। इसके लिए कंपनी ने रेलवे की लॉजिस्टिक्स कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक संयुक्त कार्य समूह बनाने का एलान किया है। भेलकॉन के नाम से स्थापित यह समूह हरिद्वार में रेल आधारित लॉजिस्टक्स टर्मिनल बनाएगा।

भेल ने इस आशय का एलान करते हुए सोमवार को बताया कि इस टर्मिनल को आगे चलकर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स सुविधा के तौर पर विकसित किया जा सकेगा। यह टर्मिनल भेल की अपनी जरूरतों के अतिरिक्त हरिद्वार के आसपास के औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों की पूर्ति करेगा। इस क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों को टर्मिनल बन जाने से सस्ते रेल परिवहन का लाभ मिलेगा।

एसबीआइ पर सात करोड़ रुपये जुर्माना

मुंबई, प्रेट्र : बैंकिंग क्षेत्र के नियामक आरबीआइ ने देश के सबसे बड़े सरकारी कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) पर सात करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर फंसे कर्ज (एनपीए) की पहचान तथा धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समेत कई अन्य नियमों की अनदेखी के आरोप हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने एसबीआइ को आय पहचान एवं संपत्ति वर्गीकरण (आइआरएसी) मानकों तथा चालू खाता खोलने और उसके परिचालन के लिए बनाए गए आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। इसके साथ ही एसबीआइ पर सेंट्रल रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआइएलसी) तथा धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उनकी जानकारी देने संबंधी मानकों का समुचित पालन नहीं करने संबंधी आरोप हैं।

आरबीआइ ने कहा कि 31 मार्च, 2017 को एसबीआइ की वित्तीय स्थिति को लेकर उससे कुछ जानकारियां मांगी गई थीं। इनमें

आइआरएसी मानकों और सीआरआइएलसी आंकड़ों से संबंधित जानकारियां थीं। इस बारे में एसबीआइ के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर नियामक ने पाया कि बैंक के खिलाफ उसके आरोप सही साबित होते हैं। आरोपों के सही साबित होने की स्थिति में बैंक पर जुर्माना लगाया गया।

हालांकि आरबीआइ ने स्पष्ट किया कि एसबीआइ पर जो भी जुर्माना लगाया गया है, वह नियामकीय मानकों के उल्लंघन के खिलाफ हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि बैंक ने ग्राहकों के साथ लेनदेन के किसी नियम का उल्लंघन किया है।

यूनियन बैंक पर 10 लाख रुपये जुर्माना : आरबीआइ ने सरकारी क्षेत्र के कर्जदाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर साइबर सुरक्षा संबंधित दिशानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप है। आरबीआइ ने कहा कि वर्ष 2016 में स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से बैंक में 17.1 करोड़ डॉलर (तत्कालीन मूल्य पर 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) के सात से ज्यादा धोखाधड़ी संबंधित संदेश मिले। उसके बाद बैंक के साइबर सुरक्षा तंत्र की जांच की गई। उसमें पता चला कि इस मोर्चे पर बैंक ने कई स्तरों पर लचरता दिखाई है। वैसे, आरबीआइ ने स्पष्ट किया है कि इस जुर्माने का मतलब यह नहीं है कि बैंक ने ग्राहकों के साथ किसी तरह के करार का उल्लंघन किया है।

चीन की विकास दर 27 वर्षों के निचले स्तर पर

बीजिंग, प्रेट्र : चीन की विकास दर इस साल की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में 6.2 फीसद के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। यह 27 साल का निचला स्तर है। पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में विकास दर 6.4 फीसद रही थी।

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की विकास दर के घटकर इतने निचले स्तर पर चले आना चिंता का विषय है, क्योंकि 2009 के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट के दिनों में भी चीन की विकास दर 6.4 फीसद से नीचे नहीं आई थी। निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण उस वक्त चीन को भारी नुकसान पहुंचा था। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा कि इस वर्ष पहली छमाही (जनवरी-जून) में चीन की विकास दर 6.3 फीसद रही। इस दौरान चीन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आकार 6.56 लाख करोड़ डॉलर (करीब 450 लाख करोड़ रुपये) रहा।

मुश्किलें दूर करने की कोशिशें जारी : डीएचएफएल

नई दिल्ली, प्रेट्र : बेहद खराब माली हालत का सामना कर रही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) ने सोमवार को कहा कि वह कर्जदाताओं के साथ मिलकर मौजूदा संकट से निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि वह सभी साझेदारों और कर्जदाताओं के साथ मिलकर ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिससे किसी भी कर्जदाता को नुकसान नहीं उठाना पड़े। कंपनी कर्जदाता बैंकों के साथ हुए करार के तहत समाधान योजना पेश करने के विशिष्ट चरणों में है। योजना के तहत समाधान प्रक्रिया की शर्तें 25 जुलाई तक पूरी कर ली जाएंगी, और प्रक्रिया पर 25 सितंबर से पहले काम शुरू हो जाएगा।

डीएचएफएल ने शनिवार को कहा था कि पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2019) में उसे 2,223 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। तिमाही नतीजे जाहिर करते हुए ही कंपनी के चेयरमैन व एमडी कपिल बधावन ने यह कह दिया था कि मौजूदा परिस्थितियों में कारोबार जारी रखने की कंपनी की क्षमता पर संदेह पैदा हो गया है। यह बेहद चिंता की बात है।

वधावन ने सोमवार को कहा कि पिछले नौ महीनों में हमने हर तरह की देनदारियों का भुगतान किया है। हम जल्द से जल्द सामान्य तरह से कारोबार करने की हालत में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी ने पिछले वर्ष सितंबर के आखिर तक 41,800 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया है। कंपनी का कहना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के सेक्टर की पिछले कुछ समय से जो हालत है, वह सभी को पता है।

आइएलएंडएफएस मामले में बावा की पत्नी, बेटी पहुंचीं एनसीएलटी

मुंबई, प्रेट्र : इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) के पूर्व प्रमुख रमेश चंद्र बावा की पत्नी आशा किरण और बेटी आकांक्षा के वकील ने सोमवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में एक याचिका दाखिल की। याचिका में मांग की गई है कि उनके बैंक खातों पर लगी रोक हटाई जाए, क्योंकि न तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआइओ) की रिपोर्ट और न ही आरोप पत्र में दोनों का नाम शामिल किया गया।

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय हालांकि उनके खातों पर रोक जारी रखना चाहता है। मंत्रालय के वकील ने कहा कि एसएफआइओ की जांच के निष्कर्षों के मुताबिक बावा के जिन बैंक अकाउंट्स पर रोक लगाई गई है, याचिकाकर्ता उन अकाउंट्स के 12 करोड़ रुपये के फंड की लाभार्थी हैं। एसएफआइओ ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि एनसीएलटी ने पिछले साल दिसंबर में बावा के लॉकर्स पर रोक लगाने का आदेश दिया था। लेकिन इन लॉकर्स पर रोक लगाने के बाद भी बावा की पत्नी और बेटी ने तीन-चार बार इन लॉकर्स का उपयोग किया है। इस तरह से उन्होंने ट्रिब्यूनल के आदेश का उल्लंघन किया है।

आइएलएंडएफएस को दो टावर से 480 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद : इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) समूह ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में स्थित अपनी संपूर्ण वाणिज्यिक रियल एस्टेट संपत्तियों को बेचने के लिए बोली आमंत्रित की है। सूत्रों के मुताबिक इन संपत्तियों की बिक्री से समूह को करीब 480 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। समूह ने सोमवार को एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि वह दो टावर्स (गिफ्ट वन और गिफ्ट टू) को नीलाम करना चाहता है।

आइएलएंडएफएस ने अपनी तीन कंपनियों के सुरक्षित कर्जदाताओं के साथ बाध्यकारी समझौते किए हैं। इन तीन कंपनियों पर 5,071 करोड़ रुपये का कर्ज है। इन तीन कंपनियों में मोरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे लिमिटेड, झारखंड रोड प्रोजेक्ट्स और वेस्ट गुजरात एक्सप्रेसवे लिमिटेड शामिल हैं।

हलचल

सेंसेक्स 160 .48 अंकों की तेजी के साथ 38,896 .71 पर बंद, निफ्टी 35 .85 अंकों के उछाल के साथ 11,588 .35 पर स्थिर

इन्फोसिस और आर्थिक आंकड़ों के दम पर शेयर बाजार उछले

मुंबई, प्रेट्र : आइटी शेयर इन्फोसिस में भारी उछाल और थोक महंगाई के बेहतर आंकड़ों के कारण सोमवार को शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई। जून की थोक महंगाई दर घटकर 23 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। बीएसई का सेंसेक्स 160.48 अंकों की तेजी के साथ 38,896.71 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 35.85 अंकों की तेजी के साथ 11,588.35 पर बंद हुआ।

वित्तीय नतीजों में तेजी के बाद ही शेयर बाजारों को दिशा मिलने की उम्मीद। फाइल

सेंसेक्स में इन्फोसिस में सर्वाधिक 7.20 फीसद तेजी रही। सन फार्मा 3.61 फीसद, मारुति सुजुकी, टीसीएस, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स और बजाज फाइनेंस एक फीसद से अधिक उछले। दूसरी ओर इंडसइंड बैंक में सर्वाधिक 2.38 फीसद गिरावट रही। लार्सन एंड टुब्रो, भारती एयरटेल, आइटीसी, आइसीआइसीआइ बैंक और यस बैंक एक फीसद से अधिक लुढ़के। अन्य प्रमुख शेयरों में इंटरग्लोब एविएशन में 1.81 फीसद तेजी रही। इंटरग्लोब एविएशन विमानन कंपनी इंडिगो का परिचालन करती है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज में 5.15 फीसद गिरावट रही। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) ने फ्यूचर इंटरप्राइजेज के सीएफओ और कार्यकारी निदेशक (ईडी) को गिरफ्तार किया है। उन पर करीब 14.58 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क चोरी का आरोप है।

सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के आइटी इंडेक्स में सर्वाधिक 3.53 फीसद तेजी रही। टेक्नोलॉजी सेक्टर 2.96 फीसद उछला। दूसरी ओर पूंजीगत वस्तु सेक्टर में सर्वाधिक 1.46 फीसद गिरावट रही। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में 0.61 फीसद और स्मॉलकैप में 0.63 फीसद गिरावट रही। सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि इन्फोसिस जैसे टेक्नोलॉजी शेयरों और फार्मा व धातु शेयरों में तेजी से निफ्टी में तेजी रही। तिमाही नतीजे का रुझान बाजार की उम्मीद से बेहतर रहा है। इसके साथ ही सकारात्मक विदेशी रुझानों के कारण बाजार को बल मिला। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, हैंगसेंग और निक्केई में तेजी रही, जबकि कोस्पी में गिरावट रही। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का माहौल रहा।

इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 17,636 करोड़ रुपये उछला

नई दिल्ली : आइटी कंपनी इन्फोसिस के शेयर बीएसई पर 7.20 फीसद उछलकर 779.45 रुपये पर बंद हुए। इसके साथ ही कंपनी के बाजार पूंजीकरण (एमकैप) में 17,636.08 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर इन्फोसिस में सर्वाधिक तेजी रही। कंपनी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जून तिमाही के शुद्ध लाभ में 5.3 फीसद बढ़ोतरी की घोषणा की थी। कंपनी का नतीजा बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहा है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी आय बढ़ोतरी के अनुमान में भी बढ़ोतरी की है।

इलाहाबाद बैंक 7.74 फीसद लुढ़का

नई दिल्ली : इलाहाबाद बैंक के शेयर बीएसई पर 7.74 फीसद गिरकर 43.50 रुपये पर बंद हुए। बैंक ने आरबीआइ को दी गई सूचना में कहा है कि भूषण पावर एंड स्टील ने बैंक में 1,774.82 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। इसी महीने के शुरू में पंजाब नेशनल बैंक ने भी कहा था कि भूषण पावर एंड स्टील ने 3,805.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

मुनाफावसूली के कारण सोना 100 रुपये फिसला

- सोना 100 रुपये लुढ़ककर 35,470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेशी बाजारों के कमजोर रुझान और मुनाफावसूली के कारण सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोना 100 रुपये लुढ़ककर 35,470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से खरीदारी घटने से चांदी भी 25 रुपये कमजोर होकर 39,175 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी रिसर्च प्रमुख हरीश वी ने कहा कि चीन में उम्मीद से बेहतर आर्थिक आंकड़े आने से अंतरराष्ट्रीय सुस्ती को लेकर चिंता में थोड़ी कमी आने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई मुनाफावसूली के कारण सोने में गिरावट आई। हालांकि चीन में दूसरी तिमाही की विकास दर के 27 साल के निचले स्तर पर आने से कमोडिटी में अधिक गिरावट नहीं आई। न्यूयॉर्क में सोने में 1,416.80 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 15.41 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ। राष्ट्रीय राजधानी के हाजिर

सराफा बाजार में दिशा का अभाव। प्रतीकात्मक

बाजार में 99.9 फीसद खरा सोना 100 रुपये लुढ़ककर 35,470 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतनी ही गिरावट के साथ 35,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी 27,400 रुपये प्रत्येक के भाव पर कायम रही। चांदी हाजिर 25 रुपये कमजोर हुई। वीकली डिलीवरी 10 रुपये चढ़कर 38,400 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई। चांदी के सिक्कों की कीमत प्रति सैकड़ा 81,000 रुपये खरीद और 82,000 रुपये बिक्री के स्तर पर कायम रही।

11 लोगों की मौत हो गई दक्षिणी अफगानिस्तान में एक वाहन के विस्फोट की चपेट में आने से। हादसे में 34 लोग घायल हुए हैं। अफगान अधिकारियों का कहना है कि बम तालिबान ने लगाया था। वहीं, अभी किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

विपक्षी महिला सांसदों पर टिप्पणी कर घिरे ट्रंप

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- चार डेमोक्रेट सांसदों से कहा, जिस देश से आई हैं, वहीं लौट जाएं
- विरोधियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को नस्ली टिप्पणी बताया

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विवादों से पुराना नाता है। अपनी टिप्पणियों के चलते वह कई बार आलोचनाओं का शिकार हो चुके हैं। कुछ विपक्षी महिला सांसदों पर टिप्पणी कर वह फिर विवादों में घिर गए हैं। डेमोक्रेट पार्टी की चार अल्पसंख्यक महिला सांसदों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'सरकार कैसे चलाई जाए, अमेरिकी लोगों को यह बताने के बजाय वे जिन देशों से आई हैं वहीं लौट जाएं।' ट्रंप अपने इस बयान से विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने ट्रंप के बयान को गलत और नस्ली करार दिया है।

ट्रंप ने रविवार को ट्विटर पर लिखा, 'यह उन प्रगतिशील डेमोक्रेट्स महिला सांसदों के लिए देखना कितना दिलचस्प है कि वे मूल रूप से जिन देशों से आई हैं, वहां की सरकारें पूरी तरह तबाह, सबसे भ्रष्ट और दुनिया में सबसे अयोग्य हैं। वे अमेरिकी लोगों से चिल्लाकर और क्रूरतापूर्वक कह रही हैं कि हमारी सरकार को किस तरह चलाया जाए? वे जहां से आई हैं वहीं वापस क्यों नहीं चली जातीं और उन तबाह व अपराध प्रभावित जगहों की समस्या को दूर करने में मदद क्यों नहीं करतीं?' संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की स्पीकर और डेमोक्रेट नेता नैंसी पेलोसी समेत उनकी पार्टी के कई नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, 'हमारी विविधता और एकता हमारी ताकत है। सांसदों पर हमला करने के बजाय ट्रंप को हमारे साथ आव्रजन नीति और अमेरिकी मूल्यों पर काम करना चाहिए।'

इन सांसदों पर साधा निशाना : ट्रंप ने किसी महिला सांसद का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर तौर पर उनके निशाने पर पहली बार संसद पहुंचने वालीं अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कार्टेज, इल्हान उमर, रशीदा तालिब और अयान प्रेसली हैं। उमर का जन्म सोमालिया में हुआ है। तालिब का फलस्तीन और अलेक्जेंड्रिया का प्यूर्टोरिको से ताल्लुक है। प्रेसली पहली अफ्रीकी अमेरिकी सांसद हैं।

इस वजह से बनीं निशाना : महिला सांसदों ने ट्रंप की आव्रजन नीति और शरणार्थियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की आलोचना की थी। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे शरणार्थियों को निकालने के लिए रविवार से अभियान शुरू किया गया है। तालिब कई बार इजरायल की आलोचना कर चुकी हैं। उमर ने श्वेत राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

पहले भी दिए विवादित बयान : ट्रंप पहले भी कई बार अपने बयानों के चलते विवादों में घिर चुके हैं। उन्होंने पिछले साल जनवरी में हैती और अफ्रीकी देशों के आप्रवासियों पर नस्ली टिप्पणी की थी। उन्होंने गत अक्टूबर में अमेरिका की ओर बढ़ रहे होंडुरास के हजारों शरणार्थियों के काफिले में आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताई थी। वह शरणार्थियों पर भी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल होने वाले शरणार्थियों को जानवर करार दिया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एएफपी

नेपाल में बाढ़ से अब तक 60 लोगों की गई जान, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से मदद मांगी

काठमांडू, प्रेट्र : बाढ़ से जूझ रहे नेपाल ने जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से मदद की अपील की है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण नेपाल में अब तक करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। गत गुरुवार से हो रही भारी बारिश के कारण इस हिमालयी देश के 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।

काठमांडू पोस्ट अखबार के अनुसार, बारिश के चलते हुए नुकसान का आकलन करने के लिए रविवार को राजधानी काठमांडू में आपात बैठक बुलाई गई। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ समेत कई अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

बैठक में स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय की ओर से स्थापित स्वास्थ्य आपात संचालन केंद्र ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से मदद मांगी। इस केंद्र के प्रमुख चूड़ामणि भंडारी ने कहा, 'हमने उनसे यह आग्रह भी किया कि वे प्रभावित इलाकों में अपने स्थानीय तंत्र को सक्रिय कर दें। हमारी सभी साझीदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हर तरह की मदद मुहैया कराने को राजी हैं।' उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को डॉक्टरों की आपात टीमें गठित करने का आदेश दिया है। इन टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा जाएगा।

नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से हालात काफी खराब हो चुके हैं। राजधानी काठमांडू के आवासीय इलाकों में बारिश का पानी भर जाने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। रायटर

न्यूज गैलरी

ऑस्ट्रेलिया में बच्चों ने चुराई कार, किया हजार किमी सफर

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया में चार बच्चों ने मस्ती के लिए ना सिर्फ एक कार चोरी की बल्कि उससे एक हजार किलोमीटर का सफर भी तय कर लिया। 10 से 14 साल तक के इन बच्चों में एक लड़की भी शामिल थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्वींसलैंड प्रांत के रॉकहैंप्टन शहर से शनिवार को इन बच्चों ने पहले एक रिश्तेदार की कार चोरी की और फिर रुपये-पैसे और मछली पकड़ने वाले कांटे लेकर पड़ोसी राज्य न्यू साउथ वेल्स की ओर निकल पड़े। एक बच्चे द्वारा इसकी सूचना घर में दिए जाने से उनके कारनामे का पता चला। पुलिस ने उन्हें रविवार रात एक हजार किलोमीटर दूर ग्राफ्टन शहर में पकड़ा। जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने बताया कि घर से निकलने के बाद उन्होंने बारी-बारी से कार ड्राइव की। इन बच्चों में एक लड़के की उम्र 14 साल, दो लड़कों की 13 साल और लड़की की उम्र महज दस साल है। (एएफपी)

नाइजीरिया के गांव पर हमले में 10 लोगों की मौत

कानो (नाइजीरिया): उत्तर पश्चिम नाइजीरिया के एक गांव में करीब 300 बंदूकधारियों द्वारा बदले के इरादे से किये गये हमले में 10 लोगों की मौत हो गयी। पुलिस ने बताया कि बंदूकधारियों ने कारों में आग लगा दी और वे मवेशियों को भी चुराकर ले गये। क्षेत्रीय पुलिस प्रवक्ता गैंबो ईसाह ने एक बयान में कहा कि शनिवार को हमलावरों ने कतसीना राज्य के किरतावा गांव पर धावा बोला और ग्रामीणों पर गोलियां बरसाने लगे। वे उनकी गायें भी चुराकर ले गये। (एएफपी)

इंडोनेशिया में भूकंप से दो लोगों की मौत

जकार्ता: इंडोनेशिया के नॉर्थ मलुकु प्रांत में रविवार को 7.3 तीव्रता के आए भूकंप से दो लोगों की मौत हो गई। भूकंप का केंद्र प्रांत की राजधानी तेरनाटे से 166 किलोमीटर दूर और धरती की सतह से 10 किलोमीटर अंदर था। भूकंप और उसके बाद आ रहे छोटे-छोटे झटकों के डर से हजारों लोग घर से बाहर निकल आए। अधिकारियों ने भूकंप की वजह से सुनामी के किसी खतरे से इंकार किया है। (एपी)

ईयू ने रूस से परमाणु मिसाइल संधि मानने की अपील की

ब्रसेल्स: 'इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस' (आइएनएफ) संधि में रूस द्वारा अपनी भागीदारी निलंबित करने के फैसले के बाद यूरोपीय संघ (ईयू) ने रूस से इस संधि का सम्मान करते रहने की अपील की। ईयू की विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोघेरिनी ने एक बयान में कहा, 'हम आइएनएफ संधि के संबंध में हुए घटनाक्रम को लेकर काफी फिक्रमंद है जो दो अगस्त 2019 को खत्म हो सकती है।' उन्होंने कहा कि यूरोप की सुरक्षा के लिए अहम इस संधि को बचाने के लिए बातचीत का अंतिम मौका प्रदान करेंगे। (एएफपी)

हाफिज सईद को पाक कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

दोहरा रवैया ▶ मदरसे के लिए जमीन के अवैध उपयोग के मामले में 31 अगस्त तक मिली जमानत

तीन सहयोगियों के साथ 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर हुई जमानत

लाहौर, प्रेट्र : मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक आतंक रोधी अदालत से सोमवार को अग्रिम जमानत मिल गई। उसे यह जमानत मदरसे के लिए जमीन के अवैध उपयोग के मामले में मिली है।

डॉन अखबार के अनुसार, लाहौर की आतंक रोधी अदालत ने सईद और उसके तीन सहयोगियों हाफिज मसूद, अमीर हमजा और मलिक जफर की 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर 31 अगस्त तक अंतरिम जमानत मंजूर की है। सुनवाई के दौरान सईद के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि जमात-उद-दावा ने अवैध तरीके से किसी भी जमीन का उपयोग नहीं किया। इसलिए जमानत याचिकाएं मंजूर की जाएं। अधिकारियों के अनुसार, जमात-उद-दावा करीब 300 मदरसों, स्कूलों, अस्पतालों का संचालन करता है। उसका अपना एक प्रकाशन गृह और एंबुलेंस सेवा भी है। गत मार्च में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने कहा था कि जमात-उद-दावा और उसकी धर्मार्थ संस्था फलाह-ए-इंसानियत से जुड़े 160 मदरसों, 32 स्कूलों, दो कॉलेजों, चार अस्पतालों, 176 एंबुलेंस और 153 डिस्पेंसरी को जब्त कर लिया गया है। माना जाता है कि सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा 2008 के मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। अमेरिका ने 2012 में सईद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के साथ ही उस पर एक करोड़ डॉलर का इनाम भी रखा था।

हाफिज सईद फाइल

हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस : लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सईद और उसके सात सहयोगियों ने आतंकी फंडिंग और मनी लांड्रिंग के आरोपों को चुनौती दी है। इस याचिका पर कोर्ट ने संघीय सरकार और पंजाब की सरकार के साथ ही आतंक रोधी विभाग को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अंतरराष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने आतंकी फंडिंग मामले में जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, फलाह-ए-इंसानियत के खिलाफ जांच शुरू की है।

दर्ज की गई हैं 23 एफआइआर : पंजाब प्रांत के आतंक रोधी विभाग ने गत तीन जुलाई को सईद समेत जमात-उद-दावा के 13 पदाधिकारियों के खिलाफ आतंकी फंडिंग के आरोप में 23 एफआइआर दर्ज की थीं। सईद ने लाहौर हाई कोर्ट में गत शुक्रवार को इन एफआइआर को चुनौती दी थी।

गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग बोले- वे जम्मू-कश्मीर का हैं अभिन्न अंग

- यहां के लोगों ने जम्मू-कश्मीर की आजादी की मांग करने वाले संगठनों को संबोधित करते हुए लिखा सीधा खत
- कहा, पाकिस्तान की हैसियत देखभाल करने वाले से ज्यादा की नहीं, उसे सीमाएं बदलने का अधिकार नहीं

गिलगित-बाल्टिस्तान, एएनआइ : पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों ने खुला पत्र लिखकर कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ उनकी देखभाल करने वाला है। उनकी रिहायश वाला यह हिस्सा वस्तुतः जम्मू-कश्मीर राज्य का भाग है। पाकिस्तान की हैसियत देखभाल करने वाले से ज्यादा की नहीं है। उसे सीमाएं बदलने का कोई अधिकार नहीं है।

यह खुला पत्र जम्मू-कश्मीर की आजादी की मांग करने वाले संगठनों को संबोधित है। गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों ने कहा- संयुक्त राष्ट्र के संकल्प और 28 अप्रैल, 1949 को हुए कराची समझौते के अनुसार गिलगित-बाल्टिस्तान का इलाका जम्मू-कश्मीर का अंग है। इसलिए पाकिस्तान की हैसियत सिर्फ देखभाल करने वाले की है, उसे सीमाएं बदलने का कोई अधिकार नहीं है। पत्र में साफ किया गया है कि समूचे जम्मू-कश्मीर की स्थिति विवादित है और यह तथ्य नियंत्रण रेखा के दोनों ओर बसे जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है।

पत्र में लिखा है- 1947 में जब जम्मू-कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटा गया, तब छिड़े युद्ध के संघर्षविराम के बाद तीसरे व उत्तरी इलाके गिलगित लदाख को दो हिस्से में बांट दिया गया।

28,000 वर्ग मील का यह इलाका श्रीनगर और मुजफ्फराबाद से अलग था। इसी में से 2,000 वर्ग मील का इलाका पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया था। इसी प्रकार से गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके को पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा से जोड़कर वहां के जमीनी हालात बदलने की कोशिश की गई है। यह जम्मू-कश्मीर की सीमा को खत्म करने का पाकिस्तान का प्रयास है। पत्र में जम्मू-कश्मीर की पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्षरत सभी संगठनों और दलों से ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर आगे बढ़ने की अपील की गई है। कहा गया कि गिलगित-बाल्टिस्तान जम्मू-कश्मीर के अभिन्न अंग हैं।

गुलाम कश्मीर में बादल फटने से 23 की मौत

इस्लामाबाद, प्रेट्र : गुलाम कश्मीर के नीलम घाटी क्षेत्र में बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ से 23 लोगों की मौत हो गई। घाटी के लासवा इलाके में बादल फटने से कई मकान बह गए। दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे हैं। कई जगहों से भूस्खलन की खबर है। लासवा के मुख्य बाजार में पानी के तेज बहाव में कई मकानों समेत दो मस्जिद भी बह गईं। इलाके में परिचालन बाधित होने के अलावा टेलीफोन और इंटरनेट सेवा भी प्रभावित हुई हैं। बाढ़ से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन कर्मी और पुलिस के जवान राहत कार्यों में जुटे हैं। पिछले सप्ताह चितराल जिले में एक झील पर बना बांध टूटने से गोलेन गोल इलाके के कई गांव पानी में डूब गए थे।

पाक की गुरुद्वारा कमेटी में फिर खालिस्तान समर्थक !

इस्लामाबाद, एएनआइ : भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में खालिस्तान समर्थक पदों पर बने हुए हैं। यही कमेटी पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारा समेत सभी गुरुद्वारों की व्यवस्थाएं संभालती है।

इस संस्था में कुख्यात खालिस्तानी नेता बिशेन सिंह का भाई अमीर सिंह शामिल किया गया है। यह जानकारी रविवार को करतारपुर कॉरीडोर के निर्माण के सिलसिले में हुई दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक के एक दिन बाद सामने आई है। दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक में भारत ने अपनी चिंता से पाकिस्तान को अवगत कराया भी था।

इससे पहले खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला के कमेटी में होने के विरोध में भारत करतारपुर कॉरीडोर पर होने वाली बैठक को अघोषित रूप से टाल रहा था। पाकिस्तान ने दिखावे के तौर पर गोपाल सिंह को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हटा दिया लेकिन अमीर सिंह को शामिल कर लिया। इस बीच यह भी खुफिया रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान पंजाब को अशांत करने के लिए करतारपुर कॉरीडोर का इस्तेमाल कर सकता है और इसके जरिये आतंकियों को भारत में भेज सकता है। जम्मू-कश्मीर में कट्टरपंथियों के पस्त होते हौसले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर पंजाब को सुलगाने की कोशिश में है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कॉरीडोर के चालू होने पर धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने वाले लोग एक बार फिर सक्रिय हो जाएंगे।

तालिबान की धमकी पर अफगान रेडियो स्टेशन बंद

काबुल, रायटर : तालिबान के एक संदिग्ध कमांडर की ओर से लगातार मिल रही धमकी के बाद अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में निजी रेडियो स्टेशन समा को बंद कर दिया गया है। रेडियो स्टेशन के निदेशक रामेज अजीमी ने सोमवार को बताया कि समा चैनल में महिलाओं को रोजगार दिए जाने के खिलाफ तालिबान कमांडर ने कार्रवाई की धमकी दी थी। अजीमी ने बताया कि रेडियो स्टेशन बंद करने की चेतावनी देने कमांडर उसके घर भी आया था।

यह घटना ऐसे वक्त पर सामने आई है जब अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता में तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर नरम रुख अपनाने की बात स्वीकारी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने अपने किसी कमांडर की ओर से रेडियो स्टेशन को धमकी दिए जाने से इन्कार किया है। जबीहुल्ला ने कहा कि मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक अपने शासन के दौरान तालिबान ने महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। महिलाओं के काम के लिए बाहर निकलने और लड़कियों के पढ़ाई के लिए स्कूल जाने और अन्य विभिन्न प्रकार के काम करने तक पर पाबंदी थी।

पर्यावरण को लेकर कोर्ट के बाहर प्रदर्शन

जलवायु परिवर्तन को लेकर चल रहे विश्वव्यापी अभियान के अंतर्गत हजारों पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सोमवार को लंदन स्थित रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि पर्यावरण में सुधार के लिए शीघ्र ठोस व कारगर कदम नहीं उठाए गए तो इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ी को उठाने होंगे। रायटर

प्रतिबंध हटने पर अमेरिका से वार्ता को तैयार ईरान : रूहानी

- यूरोपीय शक्तियों ने तनाव दूर करने के लिए बातचीत की अपील की
- अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का दौर गत वर्ष मई में शुरू हुआ
- ईरान ने 2015 में परमाणु करार किया था

तेहरान, आइएएनएस : अमेरिका के साथ जारी तनातनी के बीच ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि अगर प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो उनका मुल्क अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार है। इस बीच तीन यूरोपीय शक्तियों ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए बातचीत की अपील की है।

ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी में रूहानी के हवाले से कहा गया है, 'हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं आपसे कहता हूं कि धौंस दिखाना बंद कर दें और प्रतिबंधों को हटाकर फिर से तार्किक और गंभीर बन जाएं। हम तैयार हैं।' ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते में शामिल तीन यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने रविवार को एक बयान जारी कर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर चिंता जाहिर की। इन देशों ने कहा, 'हमारा मानना है कि जिम्मेदारी के साथ काम करने, तनाव दूर करने के रास्ते तलाशने और बातचीत बहाल करने का समय आ गया है।'

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का दौर गत वर्ष मई में उस समय शुरू हुआ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु करार से हटने का एलान कर दिया था। इसके बाद उन्होंने ईरान पर कई प्रतिबंध थोप दिए।

हसन रूहानी। एएफपी

ईरान ने 2015 में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और जर्मनी के साथ परमाणु करार किया था। ईरान से खतरे को देखते हुए अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपने विमानवाहक पोत और बमवर्षक विमान तैनात किए हैं। ईरान ने हाल में कहा था कि उसने परमाणु करार का उल्लंघन करते हुए यूरेनियम संवर्धन बढ़ा दिया है।

नया मोड़

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किया दावा, हालांकि, प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने राष्ट्रपति के दावों से इत्तेफाक नहीं जताया है

'श्रीलंका में हुए धमाकों के पीछे ड्रग माफिया'

कोलंबो, एएफपी: श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सोमवार को दावा किया कि श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए बम धमाकों के पीछे ड्रग माफियाओं का हाथ है, जबकि पूर्व में हमलों के लिये इस्लामी आतंकियों को आरोपी ठहराया गया था।

मादक द्रव्यों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के बीच यह बयान तब आया है जब राष्ट्रपति सिरिसेन मादक द्रव्य से जुड़े अपराधों के लिये फिर से मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करना चाहते हैं।

अधिकारियों ने कहा था कि अप्रैल में चर्चों और होटलों पर हुए आत्मघाती बम धमाकों के लिये स्थानीय जिहादी संगठन नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) जिम्मेदार है। इन धमाकों में 258 लोगों की जान चली गई थी। बाद में इस्लामिक स्टेट समूह ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी। सिरिसेन के कार्यालय ने बम धमाकों के एक दिन बाद कहा था कि इन हमलों के लिये स्थानीय आतंकवादी और अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन जिम्मेदार हैं। वहीं, उनके कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी किये गए दस्तावेज के मुताबिक, सिरिसेन ने कहा कि हमले में अंतरराष्ट्रीय ड्रग डीलरों की कारस्तानी थी।

उन्होंने कहा, ड्रग तस्करों ने मेरी छवि बिगाड़ने और मादक द्रव्यों के खिलाफ मेरे अभियान को हतोत्साहित करने के लिये इन्हें अंजाम दिया। मैं डिगूंगा नहीं। सिरिसेन संसद में अपने गठबंधन शासन के मृत्युदंड खत्म करने के प्रयासों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के एक प्रवक्ता ने राष्ट्रपति के दावों से इत्तेफाक नहीं जताया है। सुदर्शन गुनावर्धन ने एएफपी को बताया, पुलिस ने करीब दो हफ्तों में जांच पूरी कर ली थी। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में ड्रग डीलरों के शामिल होने का कोई जिक्र नहीं है। हमारे पास अपनी जांच पर संदेह का कोई कारण नहीं है।

मैत्रीपाल सिरिसेन फाइल

उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करों के लिये मृत्युदंड से कहीं ज्यादा प्रतिरोधक त्वरित न्याय होगा। गुनावर्धन ने कहा, हम नहीं मानते कि लोगों को मृत्युदंड देने से समस्या का समाधान होगा, खासतौर पर यह ध्यान में रखते हुए कि एक सजा दिलाने में कई दशकों का वक्त लग जाएगा। श्रीलंकाई अदालत में हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों में मुकदमा पूरा करने में औसतन 17 साल का वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि विक्रमसिंघे मृत्युदंड के खिलाफ हैं क्योंकि यह उनकी युनाइटेड नेशनल पार्टी की नीतियों के विपरीत है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 21 अप्रैल को हुए आत्मघाती हमलों की जांच अभी जारी है। हिरासत में लिये गए लोगों में से 100 श्रीलंकाई हैं।

नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने एएफपी से कहा, हम इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कि यह ऐसा अपराध है जो साजिश से लेकर अंजाम तक कट्टरपंथी श्रीलंकाई मुसलमानों के समूह का काम है। उन्होंने कहा कि हमले में शामिल सभी लोग या तो मर चुके हैं या हिरासत में हैं।

पाक के सामान पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा

जागरण संवाददाता, अमृतसर : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान से आयात किए गए व इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आइसीपी) अटारी पर डंप सामान पर फैसला रिजर्व रख लिया है। इंपोर्टर्स ने पुरानी कस्टम ड्यूटी पर ही डंप माल को रिलीज करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। डबल बैंच की अदालत ने इससे पहले 11 जुलाई को सुनवाई करते हुए फैसले के लिए 15 जुलाई तय की थी। लैंडपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डंप माल की नीलामी पर फिलहाल 19 जुलाई तक रोक लगाई है। गौर हो कि पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेते हुए पाक से मंगवाए जाने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 200 फीसद कर दी थी। इसके बाद से ही अमृतसर, दिल्ली, इंदौर और मुंबई की 17 इंपोर्टर्स का 68 ट्रक माल आइसीपी पर पड़ा है। इनमें सीमेंट बैग, जिप्सम, छुआरा, मुलट्ठी और पुराने टायर-ट्यूब आदि शामिल हैं।

ईयू वार्ता से पहले ब्रिटेन का ईरान से तनाव कम करने का आह्वान

लंदन, एएफपी: यूरोपीय संघ के अपने समकक्षों के साथ वार्ता से पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने सोमवार को कहा कि ईरान की कार्रवाई काफी अस्थिरता फैलाने वाली हैं, लेकिन वह पश्चिम एशिया में तनाव घटाना चाहते हैं।

हंट ने ट्वीट किया, 'ईरान के साथ तनाव कैसे कम किया जाए। इस पर जरूरी बातचीत करने के लिए मैं ब्रशेल्स जा रहा हूं।' उन्होंने कहा, 'पश्चिम एशिया के प्रति उनका रूख बहुत ही अस्थिरता फैलाने वाला है लेकिन हम ग्रेस 1 टैंकर को लेकर तनाव बढ़ाना नहीं, घटाना चाहते हैं और क्षेत्र में परमाणु होड़ से बचना चाहते हैं।' यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर 2015 में हुए करार पर चर्चा करने के लिए बैठक होने जा रही है, क्योंकि इस विषय पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका इस करार से पीछे हट गया है जिससे उसके उन यूरोपीय सहयोगियों को बड़ी निराशा हुई है जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किये थे। ईरान इस बात से नाराज था कि इस करार के तहत उसे प्रतिबंध संबंधी जिस राहत का आश्वासन दिया गया था, वह उसे नहीं मिल रही है। तब उसने अपना संवेदनशील यूरेनियम संवर्धन कार्य तेज कर दिया जिससे बाद अमेरिका ने उसे चेतावनी दी।

ब्रिटेन तब इस विवाद में उलझ गया जब उसके छोटे से क्षेत्र जिब्राल्टर में उसके अधिकारियों ने इसी माह के प्रारंभ में ईरानी तेल टैंकर ग्रेस 1 को जब्त कर लिया। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि यह टैंकर प्रतिबंधों का उल्लंघन कर तेल लेकर सीरिया जा रहा था। इस पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

ICC CRICKET WORLD CUP ENGLAND & WALES 2019

क्रिकेट महाकुंभ

दैनिक जागरण

www.jagran.com

मंगलवार 16 जुलाई 2019

ये भी जानिए

विश्व कप इतिहास में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाले केन विलियमसन न्यूजीलैंड के दूसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले 1992 विश्व कप में मार्टिन क्रो को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया था।

क्या न्यूजीलैंड के साथ धोखा हुआ?

- तीन-तीन फैसले न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ गए
- सुपर ओवर टाई होने का नियम इसी टीम के खिलाफ गया

विश्व कप में दैनिक जागरण

अभिषेक त्रिपाठी • लंदन

क्या एक चौका, चार सिंगल से बड़ा होता है? क्या एक छक्का तीन डबल से बड़ा होता है? क्या ज्यादा चौके-छक्कों से बोनस मिलता है? क्या एक चौके को एक छक्के के बराबर ही गिना सकते है? क्या किसी मैच में अंपायर का हर गलत फैसला एक ही टीम के खिलाफ जाता है? क्यों स्टोक्स के बल्ले से लगकर गेंद के चौके की ओर जाने पर पांच की जगह छह रन दिए जाते हैं? जी हां, रविवार को दुनिया के सबसे पुराने स्टेडियम लॉर्ड्स में यही हुआ। क्रिकेट के प्रशंसक इसे न्यूजीलैंड के साथ धोखा होना मान रहे हैं। अगर इतने फैसले न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं गए होते तो शायद इयोन मोर्गन की जगह केन विलियमसन की टीम के हाथों में पहली बार विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी होती। यही कारण है कि मैच के बाद जब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की प्रेस कांफ्रेंस खत्म हुई तो पहली बार सारे पत्रकारों ने उनके लिए खड़े होकर ताली बजाई। विश्व विजेता कप्तान इयोन मोर्गन के अपने मैदान में ऐसा करने के बावजूद नहीं हुआ।

सवाल ही सवाल: सबसे ज्यादा चौके और सुपर ओवर टाई होने के बाद चौके-छक्कों के आधार पर विश्व चैंपियन घोषित करने पर हो रहे हैं। जब एक चौका और एक छक्का आपस में बराबर नहीं होता तो फिर बाउंड्री के आधार पर कैसे किसी को चैंपियन बना सकते हैं, यह सवाल अधिकतर भारतीयों के मन में ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के दिमाग में कौंध रहा है। इसके लिए आइसीसी की आलोचना भी हो रही है लेकिन सच कहूं तो दुनिया में क्रिकेट चलाने वाली संस्था को शायद उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा होगा क्योंकि अगर उसे लगता कि ऐसा होगा तो वह इस तरह का नियम नहीं बनाती।

लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ फाइनल मैच टाई रहा। फिर सुपर ओवर भी टाई हो गया जिसके बाद इंग्लैंड को सबसे ज्यादा 26 चौके-छक्के (सुपर ओवर मिलाकर) के आधार पर विश्व विजेता घोषित कर दिया गया। हमेशा धीमे बल्लेबाजी करने वाली न्यूजीलैंड ने 17 चौके-छक्के ही लगाए थे और उसे हार का सामना करना पड़ा। रविवार को जब न्यूजीलैंड के 241 रनों के जवाब में इंग्लैंड की टीम 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर उसी स्कोर पर ढेर हो गई तो लॉर्ड्स मीडिया सेंटर में स्कोरर की सुखे आवाज ने सबके कान खड़े कर दिए। स्कोरर ने वनडे में पहली बार प्रयोग किए जा रहे सुपर ओवर नियम का उल्लेख किया। वह बोले, सिर्फ अंतिम-11 के खिलाड़ी ही इसमें भाग लेंगे। प्रत्येक टीम से तीन बल्लेबाज ही बल्लेबाजी कर सकते हैं (यानी दूसरा विकेट हुआ तो पारी खत्म) और एक गेंदबाज ही छह गेंदें फेंक सकता है। जिसने 50-50 ओवर में दूसरी पारी में बल्लेबाजी की है, वह सुपर ओवर में शुरुआत में बल्लेबाजी करेगा। इसी आधार पर मेजबान इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला। स्कोरर आगे बोला कि सुपर ओवर में जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा वह विजेता बनेगा, यहां तक भी किसी को परेशानी नहीं होगी। स्कोरर आखिरी नियम बता रहा था, अगर सुपर ओवर टाई हुआ तो जिस भी टीम ने पारी और सुपर ओवर मिलाकर सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाए होंगे वही विजेता बनेगा। इस नियम को सुनकर सभी भौचक्क थे लेकिन किसी को नहीं लग रहा था कि छह-छह गेंदों बाद आइसीसी के सबसे आखिरी नियम का प्रयोग किया जाएगा। सुपर ओवर में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दो बाउंड्रीज की मदद से 15 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड एक छक्के की मदद से 15 रन ही बना सका और सुपर ओवर भी टाई हो गया। टी-20 क्रिकेट में भी ऐसा संयोग इससे पहले नहीं हुआ था। शायद आइसीसी को भी नहीं लगता था कि ऐसी संभावना होगी क्योंकि क्रिकेट में इतने सारे संयोग आज तक नहीं हुए थे। फीफा विश्व कप के नॉकआउट में जब मैच ड्रॉ होता है तो 15-15 मिनट के दो अतिरिक्त हाफ खेले जाते हैं। अगर तब भी स्कोर बराबर रहे तो टाई ब्रेकर खेला जाता है और अगर तब भी मामला बराबरी पर रहे तो सडन डेथ होता है। रविवार को यहीं विंबल्डन में नोवाक जोकोविक और रोजर फेडरर को जीतने का बराबरी का मौका मिला। दोनों ने दो-दो सेट जीत लिए थे और पांचवें सेट में 12-12 से टाईब्रेक होने के बाद जोकोविक ने दो मैच प्वाइंट बचाकर खिताब जीता। यह नियम परफेक्ट था इसलिए इसकी आलोचना नहीं हुई। ऐसे में दोनों टीमों के पास अंतिम तक प्रयास करके जीतने का मौका होना चाहिए था लेकिन विश्व कप खिताब को जीतने के लिए न्यूजीलैंड को वह मौका नहीं मिला। निश्चित तौर पर आइसीसी को यह सोचना चाहिए। हालांकि आइसीसी ने सभी विवादों पर कहा कि मैदानी अंपायरों के फैसले पर हम कोई टिप्पणी कर सकते हैं। खेल के समय फैसला लेना अंपायरों के अंतर्गत आता है।

> आइसीसी को अपने कुछ नियमों पर ध्यान देना चाहिए।
> **रोहित शर्मा**, भारतीय उपकप्तान

धर्मसेना ने न्यूजीलैंड से छीना विश्व कप

लंदन: पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर कृष्णन हरिहरन ने भी साइमन टॉफेल की बात का समर्थन करते हुए कहा कि मैदानी अंपायर कुमार धर्मसेना ने न्यूजीलैंड के हाथों से विश्व कप छीन लिया। हरिहरन ने कहा कि वह एक छह रन नहीं थे। मैदानी अंपायर कुमार धर्मसेना और मराइस इरासमस ने देखा ही नहीं कि थ्रो आते समय बल्लेबाजों ने क्रॉस किया ही नहीं क्योंकि जब थ्रो फेंका गया तो बेन स्टोक्स और आदिल राशिद ने रन लेना शुरू ही किया था। ऐसे में गेंदबाजी छोर धर्मसेना को छह रन नहीं देना चाहिए था। वहीं दूसरे अंपायर इरासमस का काम था कि उन्हें यह देखना चाहिए था कि दोनों रनर ने एक-दूसरे को क्रॉस किया कि नहीं। अगर कुछ गलतफहमी थी तो उन्हें तीसरे अंपायर से पूछना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर उस समय छह की जगह पांच रन दिए जाते तो इंग्लैंड की जगह न्यूजीलैंड विश्व विजेता होता। सुपर ओवर खेलने की जरूरत भी नहीं होती।

विश्व कप खिताब जीतने के बाद अगले दिन लंदन स्थित ओवल मैदान पहुंची इंग्लैंड की क्रिकेट टीम • एपी

> समझ में नहीं आते इस तरह के नियम, जो विश्व विश्व कप का फाइनल तय करते हैं, किसने सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाई...? यह आइसीसी का एक हास्यास्पद नियम है। मैच टाई होना चाहिए था। मैं दोनों टीमों को बधाई देना चाहता हूं। दोनों विजेता हैं। **गौतम गंभीर**, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

> बहुत बढ़िया काम आइसीसी। आपने सिर्फ एक मजाक किया है। **स्कॉट स्टायरिस**, पूर्व खिलाड़ी, न्यूजीलैंड

> इंग्लैंड को बधाई! लेकिन यह विजेता टीम तय करने का एक भयानक तरीका है। इस नियम को बदलना होगा। **ब्रेट ली**, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

> इस बाउंड्री नियम को पचाना मुश्किल है। यह ऐसा है जैसे की अचानक मौत हो जाए। लगातार सुपर ओवर होता तो बेहतर परिणाम निकलता। समझें, एक विजेता चाहते हैं लेकिन ट्रॉफी साझा करना ज्यादा अच्छा विकल्प था। न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल है। **मुहम्मद कैफ**, पूर्व भारतीय बल्लेबाज

> मैं बाउंड्री नियम से सहमत नहीं हूं! लेकिन नियम तो नियम हैं। इंग्लैंड को विश्व कप जीतने पर बधाई। महान खेल और एक ऐतिहासिक फाइनल। **युवराज सिंह**, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर

इंग्लैंड को छह रन देना गलती : अंपायर टॉफेल

साइमन टॉफेल • फाइल फोटो, रायटर

लंदन: पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर और क्रिकेट के कुख्यात नियमों को बनाने वाली समिति के सदस्य साइमन टॉफेल ने कहा कि इंग्लैंड के विश्व विजेता बनने की राह में बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब कानून की उप समिति के सदस्य और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई अंपायर टॉफेल ने कहा कि जब गेंद बेन स्टोक्स के बल्ले से लगकर चौके के लिए गई उस समय अंपायरों ने बड़ी गलती की। 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड को उस समय तीन गेंदों पर नौ रन की जरूरत थी। मार्टिन गुप्टिल ने थ्रो फेंका और गेंद दो रन पूरा करने के लिए डाइव लगाने वाले बल्लेबाज स्टोक्स के बल्ले से लगकर चौके के लिए चली गई। अंपायरों ने दो रन दौड़ने और एक चौके के मिलाकर कुल छह रन इंग्लैंड के खाते में जोड़ दिए लेकिन टॉफेल का कहना है कि इस यहां पर गेंद को छोड़ने के नियम का गलत इस्तेमाल हुआ। इसमें सिर्फ पांच रन ही मिलने चाहिए थे और स्टोक्स की जगह आदिल राशिद को स्ट्राइक मिलनी चाहिए थी। एमसीसी के 19.8 लॉ के अनुसार, क्षेत्ररक्षक के हाथ से गेंद थ्रो होने से पहले बल्लेबाज अगर एक-दूसरे को क्रॉस कर चुके होते हैं और गेंद किसी वजह से बाउंड्री पार कर जाती है तो पूरा रन और बाउंड्री के चार रन माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो रन अधूरा ही माना जाएगा। इस वजह से अंपायरिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर क्षेत्ररक्षक ने तब थ्रो किया जब बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और उन्होंने एक-दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, जबकि गेंद किसी अन्य क्षेत्ररक्षक से नहीं रुकी और बाउंड्री पार कर गई तो दौड़ा हुआ दूसरा रन नहीं गिना जाएगा। यानी दौड़कर लिया हुआ सिर्फ एक रन ही माना जाएगा और बाउंड्री के चार रन मान्य होंगे। इसका मतलब इस मामले में बल्लेबाजी टीम को पांच ही रन मिलेंगे (एक रन जो उन्होंने दौड़ कर पूरा कर लिया है और बाकी के चार रन बाउंड्री से)। फाइनल मैच में अंपायरों ने यहां दूसरे रन को भी गिन लिया, जो नियमों के मुताबिक सही नहीं है।

कुमार धर्मसेना • फाइल फोटो, एएफपी

मैदानी अंपायरों का पहला दोष

लंदन: मैदानी अंपायरों के फैसले भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही गए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी के समय तीसरे ओवर में ही क्रिस वोक्स की गेंद निकोलस के पैड में लगी और तुरंत ही अंपायर कुमार धर्मसेना ने बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू करार दे दिया। रिव्यू में पता चला कि गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही थी। रिव्यू के कारण वह बच गए। 34वें ओवर की पहली गेंद पर दूसरे मैदान अंपायर मराइस इरासमस ने गलत निर्णय दिया जिसका खामियाजा न्यूजीलैंड को भुगतना पड़ा। मार्क वुड की गेंद टेलर के पैड में लगी और इरासमस ने कुछ देर सोचने के बाद अंगुली उठा दी। न्यूजीलैंड के पास रिव्यू नहीं बचा था और टेलर को वापस जाना पड़ा। बॉल ट्रैकिंग से पता चल रहा था कि गेंद लेग स्टंप के ऊपर से जा रही थी। जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई तो ट्रेंट बोल्ट ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही जेसन रॉय के खिलाफ पगबाधा की अपील की। अंपायर इरासमस ने नॉट आउट का इशारा किया तो न्यूजीलैंड ने रिव्यू लिया। रीप्ले में साफ दिख रहा था गेंद का आधे से थोड़ा कम हिस्सा लेग स्टंप पर लगकर जा रहा था लेकिन तीसरे अंपायर ने 'अंपायर कॉल' का निर्णय दिया। अंपायर कॉल में मैदानी अंपायर का निर्णय बरकरार रखा जाता है। कुल मिलाकर मैदानी अंपायरों के यह तीनों फैसले न्यूजीलैंड के खिलाफ गए।

बॉलीवुड भी नाराज

लंदन: पूर्व क्रिकेटर और आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के लोग भी आइसीसी के नियम से काफी नाराज हैं। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल ने ट्वीट किया कि महेंद्र सिंह धौनी के दस्ताने बदलने की बजाय, बेवकूफ आइसीसी को अपना सुपर ओवर नियम बदलना चाहिए। वहीं लेखक चेतन भगत ने लिखा कि ये काफी अजीब है, जिस खेल में पांच दिन हो सकते हैं, उसमें दोबारा सुपर ओवर करने का समय नहीं है। सिर्फ बाउंड्री गिनकर विश्व कप का विनर तय कर लिया।

विलियमसन और मोर्गन विवाद से बचे

लंदन: भले ही फाइनल को लेकर विवाद हो रहा हो लेकिन दोनों टीमों के कप्तानों ने इस पर कुछ भी विवादित कहने से बचने की कोशिश की। जब बल्ले से लगकर गेंद के बाउंड्री पर जाने को लेकर इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ क्योंकि जब स्टोक्स ने डाइव मारी तो काफी धूल उड़ी। हमें पता नहीं चला कि गेंद विकेटकीपर के हाथ से लगकर बाउंड्री पर गई या स्टोक्स के बल्ले से लगकर। न्यूजीलैंड के सारे क्षेत्ररक्षक भी कह रहे थे कि क्या हुआ है। मैं उस पल में रहना चाहता था, मैं उसका जश्न नहीं मना रहा था क्योंकि वह ऐसा पल था जहां कभी भी इधर से उधर हो सकता था। आप ऐसी चीजों पर खुश नहीं होते हैं क्योंकि यह कभी आपके खिलाफ भी जा सकता है। वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि यह नियम सालों से हैं। अभी तक कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जिस पर यह नियम मुद्दा बने लेकिन हां अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ एक ओवरथ्रो से मैच का रिजल्ट नहीं निकला बल्कि मैच में काफी सारी चीजें हुईं जो महत्वपूर्ण हैं। जब मैच टाई होता है तो आप सिर्फ एक गेंद को नहीं देखते। यह ऐसी कड़वी दवा है जिसे निगलना मुश्किल हो रहा है। वहीं चौके-छक्के के आधार पर मिली जीत पर मोर्गन ने कहा अगर आप इसका विकल्प बताते हैं तो उसकी तुलना की जा सकती है लेकिन मैं इस समय विकल्प के बारे में नहीं सोच रहा हूं। बहुत पहले यह नियम तय किए गए थे इसलिए हमारा इस पर नियंत्रण नहीं है। वहीं विलियमसन ने इस पर कहा कि वहीं विलियमसन ने कहा कि मैं यही कह सकता हूं कि यह नियम बहुत पुराना है।

केन विलियमसन • एएफपी

बिगड़ैल लड़के की सॉरी

- पब के सामने मारपीट करने वाले स्टोक्स ने विलियमसन से माफी मांगी
- मैन ऑफ द मैच बनकर इंग्लैंड को पहली बार विश्व चैंपियन बनाया
- 2016 टी-20 फाइनल में चार गेंद पर चार छक्के खा गंवाया था खिताब

अभिषेक त्रिपाठी, लंदन

कभी ब्रिस्टल में एक पब के बाहर मारपीट करने के बाद भी क्षमा नहीं मांगने वाला शख्स आज अपनी टीम को विश्व कप जिताने के बाद सॉरी कह रहा है। अच्छे प्रदर्शन और संगत ने उस बिगड़ैल लड़के को अब शब्दों का अहसास हो गया है। उसे पता है कि अनजाने में हुई गलती की भरपाई तो नहीं हो सकती लेकिन क्षमा मांगकर न्यूजीलैंड के दर्द को कुछ कम किया जा सकता है। हम कहते हैं कि गलती तो भगवान से भी हो सकती है लेकिन माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, शायद वह बिगड़ैल बेन स्टोक्स अपनी टीम को पहली बार विश्व चैंपियन बनाने के बाद यही सोच रहा होगा। शायद अब वह बिगड़ैल नहीं रहा है, वह इंग्लैंड का नया हीरो है और इसीलिए वह इतना बदल गया है।

दो साल पहले एक नाइटक्लब के बाहर झगड़े के कारण स्टोक्स इंग्लैंड की टीम से बाहर होने की कगार पर आ गए थे लेकिन अब वह इस देश के नूर-ए-नजर हैं। मूलतः न्यूजीलैंड के स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए खेलते हुए कीवियों के खिलाफ हरफनमौला खेल दिखाकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। मैच के बाद उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्होंने उस टीम को जीत दिलाई थी जिसने उन्हें दूसरे देश का होने के बावजूद अपनी राष्ट्रीय टीम में मौका दिया था। स्टोक्स फाइनल में नाबाद 84 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने सुपर ओवर में जोस बटलर के साथ मिलकर 15 रन बनाए। स्टोक्स ने मैच जीतने के बाद कहा कि मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैंने बहुत मेहनत की और अब दुनिया के सामने हम चैंपियन बनकर खड़े हैं। यह अद्भुत है। इस तरह के लम्हों के लिए ही आप क्रिकेटर बनते हैं। मैच के आखिरी ओवर में गुप्टिल का थ्रो उनके बल्ले से लगा और चौके के लिए गया। अंपायर ने ओवरथ्रो के कारण इंग्लैंड को छह रन दिए जिस पर विवाद मचा हुआ है। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में पैदा हुए स्टोक्स ने कहा कि आखिरी ओवर में गेंद मेरे बल्ले से लगकर सीमारेखा के पार गई, आपने ऐसा सोचा नहीं होगा। मैंने केन विलियमसन से उस बारे में अनगिनत बार माफी मांगी है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था।

एशेज नहीं खेल पाए थे स्टोक्स : ब्रिस्टल में नाइटक्लब के बाहर झगड़े के कारण स्टोक्स 2017-18 की एशेज सीरीज नहीं खेल सके थे। उसके बाद साथी खिलाड़ियों ने टीम में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और विश्व कप में अपने प्रदर्शन से इस हरफनमौला ने उसका बदला चुकाया। उन्होंने विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ही मैच में एंडिले फेलुक्वायो का शानदार कैच लपका था। उसके बाद नाबाद 82 और 89 रन बनाए। भारत के खिलाफ करो या मरो के मैच में उन्होंने 79 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में चार विकेट जल्दी निकलने के बाद उन्होंने कभी हार नहीं मानने की जिजीविषा दिखाई और इसी वजह से क्रिकेट का जनक विश्व विजेता बना। तभी तो इंग्लिश कप्तान इयोन मोर्गन को कहना पड़ा कि स्टोक्स लगभग महामानव जैसे हैं। ये स्टोक्स ही थे जिनकी वजह से दुनिया को क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक फाइनल मुकाबला देखने को मिला। शायद दुनिया को कभी भविष्य में ऐसा मुकाबला देखने को भी ना मिले।

ओवल मैदान पर मौजूद बेन स्टोक्स। एपी

इंग्लैंड की हार के खलनायक थे स्टोक्स : स्टोक्स 2016 टी-20 विश्व कप में इंग्लैंड की हार के खलनायक बने थे। कोलकाता के ईडन गार्डेंस में उनके ही आखिरी ओवर में कार्लोस ब्रेथवेट ने चार छक्के जड़कर वेस्टइंडीज को 2016 टी-20 विश्व कप का चैंपियन बनाया था। मैं उस मैच में भी ईडन गार्डेंस में था और रविवार को लॉर्ड्स में भी था। मैंने तब भी स्टोक्स को देखा था और अब भी स्टोक्स को देखा। उनमें अभूतपूर्व बदलाव आ गया है। वह तब हार के कारक थे और अब जीत के नायक। कई विश्लेषकों की नजर में स्टोक्स सही मायने में क्रिकेटिंग ऑलराउंडर हैं। उनमें गैरी सोबर्स और इयान बॉथम जैसे ऑलराउंडर की झलक नजर आने लगी है। 28 साल के स्टोक्स दायें हाथ के तेज गेंदबाज हैं लेकिन वह मध्यक्रम में बायें हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। 52 टेस्ट में स्टोक्स के नाम 127 विकेट के अलावा छह शतक हैं जबकि 95 वनडे में 70 विकेट के साथ तीन शतक बना चुके हैं। टेस्ट मैचों में उनका सबसे बड़ा स्कोर 258 रन का है।

स्टोक्स ने मदद की : आर्चर

लंदन : सुपर ओवर फेंकने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने कहा कि बेन स्टोक्स की सीख से उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप फाइनल के सुपर ओवर में धीरज बनाए रखने में मदद मिली। इंग्लैंड ने सुपर ओवर में 15 रन बनाए। इसके बाद न्यूजीलैंड ने भी आर्चर के फेंके सुपर ओवर में इतने ही रन बनाए। आर्चर ने कहा कि मैं पहले मोर्गन के पास गया कि सुपर ओवर कैसे डालना है लेकिन मैं दोबारा तसल्ली करना चाहता था। मुझे लगा कि सब ठीक होगा लेकिन फिर छक्का लग गया। स्टोक्स ने ओवर से पहले ही मुझसे कहा था कि हम जीते या हारें, उसके आधार पर तुम्हारा आकलन नहीं होगा। सभी को तुम पर भरोसा है। जेम्स नीशाम ने सुपर ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगा दिया लेकिन आर्चर ने अपना संयम नहीं छोड़ा और इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई। आर्चर ने कहा कि टी-20 विश्व कप में कोलकाता की घटना को याद में रखकर स्टोक्स मुझसे बात करने आए। वह भी इन जज्बात से गुजर चुके थे लेकिन टीम तब हार गई थी। हम अगर हार जाते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता। स्टोक्स ने तीन साल पहले कोलकाता में टी-20 विश्व कप फाइनल में आखिरी ओवर डाला था। आर्चर ने कहा कि स्टोक्स मुझसे बोले, 'हम हार भी गए तो अगले साल टी-20 विश्व कप है और मेरे पास एक मौका और होगा।' उन्होंने कहा कि जो रूट ने भी मुझे हौसला दिया। मुझे पता था कि हम हार भी गए तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। मुझे खुशी है कि इन सभी ने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने मुझसे कहा कि यह जीत इंग्लैंड में क्रिकेटरों की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगी।

बेन स्टोक्स के पिता थे न्यूजीलैंड के साथ

लंदन : बेन स्टोक्स का जन्म न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हुआ। उनके पिता न्यूजीलैंड की नेशनल रग्बी टीम की ओर से खेल चुके हैं। स्टोक्स जब 13 साल के थे तब उनका परिवार इंग्लैंड आकर बस गया, तब शायद ही उनके परिवार ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब स्टोक्स के चलते न्यूजीलैंड विश्व कप हार जाएगा। उनके पिता जेरार्ड स्टोक्स कुछ समय पहले इंग्लैंड से क्राइस्टचर्च वापस चले गए। वह रविवार को न्यूजीलैंड की जीत की दुआएं कर रहे थे। कमेंटेटर नासिर हुसैन बार-बार कर रहे थे कि पिता न्यूजीलैंड को जीत दिलाना चाह रहे होंगे लेकिन बेटा इंग्लैंड को जिताने की तरफ बढ़ रहा है। फाइनल मुकाबले के बाद जेरार्ड न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले डैड बन गए हैं।

बैड ब्वॉय स्टोक्स

लंदन : 2016 में ब्रिस्टल के एक नाइटक्लब के बाहर हाथापाई के वीडियो ने स्टोक्स को इंग्लैंड का बैड ब्वॉय बना दिया। वह गिरफ्तार भी हुए और मामला अदालत तक पहुंचा। जून 2016 में बेन चार बार इंग्लैंड में तेज गति से गाड़ी चलाने के दोषी पाए गए। उससे पहले 2011 में भी शराब के नशे में डरहम में ट्रैफिक पुलिस के साथ भिड़ गए। 2012 में भी पुलिस ने उन्हें नशे की हालत में पकड़ा था, लेकिन तब उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। 2013 में उन्हें मैट कोल्स के साथ बीच ऑस्ट्रेलियाई दौरे से वापस भेज दिया गया था। आरोप वही था कि शराब के नशे में उन्हें टीम अनुशासन की कोई चिंता नहीं थी। क्रिकेट के मैदान पर भी वे विपक्षी खिलाड़ियों विराट कोहली, मिशेल स्टार्क से उलझते रहे हैं।

हैंड ऑफ गॉड

लंदन : 22 जून, 1986 को फीफा विश्व कप क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना व इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने थीं। मैच से एक-एक से बराबरी पर था। दूसरे हाफ में जब छह मिनट रह गए थे। इंग्लैंड के गोलकीपर शिल्टन गोल रोकने की कोशिश में बाहर निकल कर चले आए। मेराडोना गजब की फुर्ति दिखाते हुए गेंद के पास पहुंच गए। वह उछले तो गेंद उनके बायें हाथ से लगकर गोलपोस्ट में चली गई। मेराडोना जश्न मनाना शुरू कर चुके थे। अर्जेंटीना 2-1 से इंग्लैंड को हराकर आगे बढ़ गया। हाथ से लगकर गेंद अगर गोलपोस्ट पर जाती है तो उसे गोल नहीं माना जाता, लेकिन इस मामले में इसे हैंड ऑफ गॉड कहा गया। ऐसा ही स्टोक्स के साथ हुआ।

'विदेशियों' ने किया अंग्रेजों का सपना पूरा

विशेष संवाददाता, लंदन

- आयरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और बारबाडोस के खिलाड़ियों ने जिताया विश्व कप

विश्व कप जीतने का सपना पूरा करने के लिए इंग्लैंड की टीम को 44 साल गुजर गए। इस बीच 11 विश्व कप का सफर अंग्रेजों ने तय किया। 1979, 1987, 1992 में तो इंग्लैंड फाइनल तक में पहुंचा, लेकिन किसी भी इंग्लिश कप्तान को विश्व कप की ट्रॉफी चूमने का मौका नहीं मिला। क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड का सपना पूरा भी हुआ तो एक ऐसी टीम से जिसका कप्तान, मुख्य ऑलराउंडर, मुख्य ओपनर यहां तक की मुख्य तेज गेंदबाज तक विदेशी मूल के हैं। विश्व कप विजेता इंग्लैंड टीम की यह बेहद रोचक कहानी है।

आयरलैंड के मोर्गन : दरअसल, इंग्लैंड टीम के कप्तान इयोन मोर्गन इस देश में नहीं जन्में हैं। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। यहां तक की वह इंग्लैंड के लिए खेलने से पहले आयरलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक खेल चुके हैं। पांच अगस्त 2006 को मोर्गन ने आयरलैंड की ओर से स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला खेला था। 24 मई 2009 को उन्होंने इंग्लैंड के लिए पहला वनडे वेस्टइंडीज के खिलाफ ब्रिस्टल में खेला था। यहां उन्होंने नाबाद दो रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2015 विश्व कप में पहले ही दौर में इंग्लैंड के बाहर होने के बाद चयनकर्ताओं ने मोर्गन को कप्तानी का जिम्मा सौंपा और अब उन्होंने इंग्लैंड का अधूरा ख्वाज पूरा कर दिया।

दक्षिण अफ्रीका के जेसन रॉय : इंग्लैंड के पास आज विश्व कप खिताब है तो उसमें अहम भूमिका जेसन रॉय की ही है। लीग दौर में रॉय चोटिल हुए तो इंग्लैंड का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया था। तब रॉय ने ही वापसी कर टीम को भारत, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दिलाई। टीम के मुख्य ओपनर रॉय का जन्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता के इंग्लैंड में बसने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के लिए वनडे में 2015 को पदार्पण किया था।

अपने ही देश को स्टोक्स ने हराया : यह तो बेन स्टोक्स ने भी नहीं सोचा होगा कि वह इंग्लैंड के लिए विश्व कप जीतेंगे और उस देश को हराकर जीतेंगे जहां उनका जन्म हुआ था। 28 वर्षीय स्टोक्स का जन्म न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हुआ था। उनके भी माता-पिता न्यूजीलैंड से इंग्लैंड में आकर बस गए थे और फिर यहीं उन्हें क्रिकेट सीखना शुरू किया।

आर्चर भी इंग्लैंड के नहीं : इंग्लैंड टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के विश्व कप खेलने का सपना बहुत पास आकर पूरा हुआ। सुपर ओवर में अपनी टीम को जीत दिलाने वाले आर्चर मुख्य रूप से कैरेबियाई देश बारबाडोस से हैं। वह क्रिकेट का सपना लेकर ही इंग्लैंड पहुंचे थे। 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ ससेक्स की टीम में उन्हें चुना गया और यह उनका पहला प्रथम श्रेणी मैच था। वह लगातार काउंटी में आर्चर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन नियम के मुताबिक उन्हें इंग्लैंड में पांच वर्ष पूरे करने थे तभी उनका इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में चयन हो सकता था। विश्व कप शुरू होने से कुछ महीने पहले ही आर्चर का यह समय सीमा पूरी हुई और उन्हें विश्व कप टीम में चुना गया। किस्मत भी उनके साथ रही कि पहली बार टीम में चुने जाने पर ही वह विश्व विजेता टीम का हिस्सा बन गए।

पाक मूल के खिलाड़ियों का साथ : पाकिस्तान का विश्व कप जीतने का सपना जरूर अधूरा रहा गया, लेकिन इस देश से ताल्लुक रखने वाले इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों ने यह कर दिखाया। आदिल राशिद का जन्म भले ही इंग्लैंड के यॉर्कशायर में हुआ, लेकिन उनके पिता पाकिस्तान से हैं। ऐसी ही कहानी मोइन अली की भी है। मोइन के दादा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर जिले से थे। वह इंग्लैंड आकर बस गए थे।

आइसीसी की विश्व कप टीम में रोहित बुमराह को जगह

विशेष संवाददाता, लंदन: टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले रोहित शर्मा ओर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आइसीसी विश्व कप एकादश में शामिल किया गया जिसकी कप्तानी न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को दी गई।

इंग्लैंड का इस टीम में दबदबा है। विलियमसन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया था। रविवार को लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल के छह खिलाड़ियों को इस टीम में जगह मिली। नए विश्व चैंपियन इंग्लैंड के चार और न्यूजीलैंड के दो खिलाड़ी एकादश में शामिल हैं। इस टीम का चयन एक पैनल ने किया। टीम के अन्य खिलाड़ियों में सेमीफाइनल में हारने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के दो-दो तथा बांग्लादेश के शाकिब अल हसन हैं। रोहित ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 648 रन बनाए जबकि बुमराह ने 18 विकेट चटकाए थे। जेसन रॉय को शीर्ष क्रम में उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के कारण सलामी बल्लेबाज के रूप में चुना गया। उन्होंने टूर्नामेंट में 50 से अधिक के पांच स्कोर बनाए जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ शतक भी शामिल है। रॉय के साथ दूसरे सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं।

इंग्लैंड के साथ थी किस्मत

सुनील गावस्कर कलम से

निश्चित तौर पर यह वनडे क्रिकेट में सबसे बेहतरीन मुकाबला था। कौन सोच सकता है कि विश्व कप फाइनल में दो बार टाई देखने को मिलेगा और फैसला इस आधार पर किया जाएगा कि किस टीम ने ज्यादा बाउंड्री लगाई। यह फैक्टर पर बताता है कि यह बल्लेबाजों का खेल है। अगर ज्यादा विकेट लिए जाने के आधार पर फैसला होता, तो न्यूजीलैंड विजेता होता। खैर जो हुआ सो हुआ, इंग्लैंड ने आखिरकार विश्व कप जीत लिया और वो भी फुटबॉल के दीवाने देश में।

मैच की शुरुआत बहुत शानदार नहीं रही। इंग्लैंड के गेंदबाज पिच का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे थे। वे लगातार शॉर्ट गेंद कर रहे थे जो कि इस पिच पर आदर्श नहीं था। एक बार फिर कम करके आंके जाने वाले लियाम प्लंकेट ने कप्तान विलियमसन और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे निकोलस का विकेट लिया। विश्व कप से पहले प्लंकेट आइपीएल में खेल रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा मैचों में मौका नहीं मिला। मगर आप उन्हें उस समय भी कड़ी मेहनत करते देख सकते थे। इंग्लिश मीडिया की ओर से उनकी कद काठी को लेकर गलत टिप्पणियां की गईं। लेकिन अंत में मेहनत रंग लाई और उन्होंने बल्ले से भी अच्छा योगदान दिया। कीवी टीम 20 रन अतिरिक्त नहीं बना पाई, जिसने बड़ा अंतर पैदा किया। इसके बाद जोफ्रा आर्चर ने अपना काम किया। इंग्लैंड के इस नए शिकारी ने पारी के अंत में न्यूजीलैंड को बांधकर रख दिया। जब इंग्लैंड ने खतरनाक जेसन रॉय और निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो रूट का धैर्य खोकर विकेट गंवाया, तो कीवी टीम का पलड़ा भारी हो गया था। मगर टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं करने वाले बटलर ने बेन स्टोक्स के साथ साझेदारी की और इंग्लैंड की स्थिति को मजबूत किया। बटलर के आउट होने के बाद चीजें फिर से बदल गईं। जब दोनों टीमों पर दबाव बढ़ा, तो आसान चीजें भी मुश्किल हो गईं। कई लोग कह सकते हैं जब बोल्ट ने स्टोक्स को बाउंड्री पर लपका, तब शायद उन्हें लग रहा था कि वह बाउंड्री के अंदर हैं और सीमा पार कर छक्का दे बैठे। क्या बोल्ट अपने उस चश्मे को देखने लगे थे, जो गिर रहा था और भूल गए थे कि रस्सी पास हैं? मगर यह बताता है कि किस्मत इंग्लैंड के साथ थी और खिताब जीतना उनके भाग्य में लिखा था।

4 लाख के करीब इलेक्ट्रिक या बैटरी चालित वाहन भारत में पंजीकृत हैं। इनमें से आधे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें से अधिकतर का इस्तेमाल ई-रिक्शा के तौर पर होता है। यह जानकारी सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों से मिली है।

रुपहले पर्दे पर दिखेगा उत्तर प्रदेश की शूटर दादियों का संघर्ष

फिल्म सांड़ की आंख बनकर तैयार, दीपावली पर होगी रिलीज, जौहड़ी और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में साढ़े तीन साल में पूरी हुई शूटिंग

बागपत (उप्र) के जौहड़ी गांव में फिल्म सांड़ की आंख की शूटिंग के दौरान शूटर दादियां चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर, अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, तापसी पन्नू, निर्माता अनुराग कश्यप और निर्देशक हीरानंदानी। फाइल फोटो

जागरण विशेष

भूपेंद्र शर्मा, बागपत

जीवन के सात दशक पार करने के बाद पिस्तौल उठाकर पदकों और पुरस्कारों की झड़ी लगाने वाली शूटर दादियों की बायोपिक बनकर तैयार है। फिल्म 'सांड़ की आंख' के जरिये दुनिया चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर के संघर्ष को जानेगी। जौहड़ी गांव की इन जेठानी-देवरानी ने गांव ही नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हजारों बेटियों को ऐसी राह दिखाई, जिसने उनका जीवन बदल दिया। भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू जैसी मंझी हुई अभिनेत्रियों ने दादियों के किरदार को किस अंदाज में निभाया है, इसकी झलक फिल्म के टीजर से मिल चुकी है।

फिल्म के निर्देशक तुषार हीरानंदानी, निर्माता अनुराग कश्यप और निधि परमार हैं। फिल्म दीपावली पर रिलीज होगी। इस फिल्म के निर्माण में करीब साढ़े तीन साल लग गए। चंद्रो तोमर की पौत्री शैफाली के पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुमित राठी बताते हैं कि जुलाई 2012 में अभिनेता आमिर खान के टीवी शो सत्यमेव जयते में शूटर दादियां दिखाई दी थीं। इस शो की क्लिप यू-टयूब पर 2015 में तुषार हीरानंदानी ने देखी और शूटर दादियों की जिंदगी पर फिल्म बनाने का इरादा कर लिया। इस फिल्म को लेकर निर्माता अनुराग कश्यप से बात हुई, तो उन्होंने हामी भर दी। अनुराग ने 2016 में शूटर दादियों के परिवार से संपर्क किया।

सुमित बताते हैं कि उन दिनों वह मुंबई में ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे थे। उनकी अनुराग से शूटर दादियों पर फिल्म बनाने को लेकर बात हुई। इसके बाद निर्देशक और निर्माता टीम के साथ जौहड़ी गांव पहुंचे और शूटर दादियों और उनके परिवार से मिले। टीम ने दादियों की जिंदगी के बारे में जाना। क्षेत्रीय भाषा सीखने पर जोर दिया गया। शूटर दादियों के शादी में पहने गए गहने, कपड़ों आदि के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। तीन चार दिन टीम गांव में रहकर वापस चली गई। इसके बाद टीम फोन से शूटर दादियों से बात करती रही।

फिल्म के लिए अभिनेत्रियों की तलाश शुरू हुई। उम्रदराज अभिनेत्रियों ने शूटर दादियों का किरदार करने से इन्कार कर दिया, तो फिल्म से जुड़ी टीम हताश हो गई। युवा अभिनेत्रियों से बात की गई, लेकिन उन्होंने भी इन्कार कर दिया। 2018 में तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने किरदार निभाने के लिए हां कर दी। शूटर दादियां मुंबई गईं और दोनों अभिनेत्रियों से मिलीं। दोनों ने दादियों की भाषा शैली, उठने-बैठने, कपड़ों आदि को लेकर बात की।

बड़े पर्दे पर दिखेगा दादियों का जौहड़ी गांव : 11 फरवरी 2019 को दादियों के गांव जौहड़ी व मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। इस दौरान तापसी चंद्रो तोमर के घर में ही रहीं और भूमि मेरठ या दिल्ली से शूटिंग के लिए आती थीं। शूटिंग के दौरान भी दोनों अदाकारा शूटर दादियों से सीन को लेकर बात करती रहती थीं। सुमित बताते हैं कि फिल्म के आखिरी दृश्य में चंद्रो और प्रकाशी को दिखाया जाएगा। उनके साथ प्रकाशी तोमर की पुत्री सीमा तोमर और चंद्रो तोमर की पौत्री शैफाली भी नजर आएंगी।

87 वर्षीय चंद्रो तोमर और 79 वर्षीय प्रकाशी तोमर का रिश्ता जेठानी-देवरानी का है। चंद्रो कहती हैं कि इंसान का तन बुड्ढा हो सकता है, लेकिन मन कभी बुड्ढा नहीं होता। प्रकाशी बताती हैं कि उन्हें देखकर गांव वालों ने अपनी बेटियों को शूटिंग रेंज के साथ-साथ निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में भी भेजना शुरू कर दिया। ये बेटियां भी पदक लाने लगीं तो सबको लगा कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। दोनों दादियां कहती हैं कि जब वे पिस्टल लेकर चलती थीं तो लोग उन्हें धाकड़ महिला कहने लगे थे। इरादे मजबूत थे इसलिए समाज की सोच भी बदल गई। जिस तरह से फिल्म बनी है, उससे दादियां पूरी तरह संतुष्ट हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

ये रहे संघर्ष के साक्षी

रिटायर्ड प्रवक्ता रमेंद्र कौशिक बताते हैं कि पुराना जमाना और वो भी ग्रामीण परिवेश। महिलाओं का घर से निकलना ही मुश्किल था। ऐसे में चंद्रो और प्रकाशी तोमर ने तमाम बाधाओं को पार कर जो कुछ किया, वह काबिल-ए-तारीफ है।

बुजुर्ग महिला शांति देवी बताती हैं कि हम भी देखा करते थे जब चंद्रो और प्रकाशी तोमर निशाना लगाने जाया करती थीं। तभी लगने लगा था कि दोनों का संघर्ष एक दिन जरूर रंग लाएगा। आज उनके चर्चे देशभर में हैं।

निशानेबाज वीना कहती हैं कि दादियों को देखकर ही उन्होंने भी निशानेबाजी का अभ्यास शुरू किया था।

जल संरक्षण से विकास का 'चौका'

उपलब्धि ▶ पानी बचाकर दुनियाभर में मिसाल बना राजस्थान की राजधानी से 90 किमी दूर बसा लापोड़िया गांव

चौका विधि से संचित किया जाता है बारिश का पानी, विदेशियों के शोध का विषय बनी जल संरक्षण की यह विधि

नरेंद्र शर्मा, जयपुर

यूं ही 'जल ही जीवन' नहीं है। भीषण जल संकट और सूखे की मार झेलते राजस्थान में लापोड़िया गांव के लोग इसका प्रमाण हैं। जब पूरा राजस्थान पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहा होता है, इस गांव में भरपूर पानी होता है। चारों तरफ व्याप्त हरियाली जल संरक्षण की चौका विधि की कहानी बयां कर रही होती है।

जल संरक्षण

गुलाबी शहर जयपुर से 90 किमी दूर स्थित लापोड़िया गांव भी चार दशक पहले तक सूखाग्रस्त था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वर्ष 1997 से 2007 तक राजस्थान में नौ बार सूखे के हालत बने, लेकिन लापोड़िया गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई। गांव की हर बस्ती में अपना तालाब है, जो पानी से लबालब है। गांव की यह तस्वीर कोई एक दिन में नहीं बनी बल्कि इस बदलाव में लंबा समय लगा। करीब 35 साल पहले गांव के ही 17 वर्षीय लक्ष्मण सिंह ने 'नवयुवक मंडल' बनाकर बारिश के पानी की एक-एक बूंद को बचाने की शुरुआत की। आज यह गांव दुनियाभर के लोगों के लिए शोध का विषय बन हुआ है। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने लक्ष्मण सिंह को वर्ष 2007 में जल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया। जयपुर में हुए ब्रिक्स देशों की महिला सांसदों के सम्मेलन में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लापोड़िया और लक्ष्मण सिंह की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 'मन की बात' में जल संरक्षण को लेकर यहां हो रहे कार्यों की चर्चा कर चुके हैं।

लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों की मेहनत का परिणाम है कि 2000 लोगों की आबादी वाले लापोड़िया की 1400 बीघा जमीन सिंचित होने के साथ ही आसपास के 58 गांवों को पानी मुहैया कराया जा रहा है। हालत यह है कि लापोड़िया से शुरू बदलाव की बयार पूरे प्रदेश में बहने लगी है। पानी बचाने के लिए यहां अपनाई गई चौका विधि का अध्ययन करने के लिए कुछ समय पूर्व इजराइल का प्रतिनिधिमंडल आया था।

राजस्थान के लापोड़िया गांव में चौका सिस्टम के तहत होता है जल संरक्षण होता। करीब चार दशक पहले तक सूखाग्रस्त रहने वाले इस गांव में अब पानी ही पानी नजर आता है। जागरण

मिट्टी के चौके बनाकर बचाया जाता है पानी : लक्ष्मण सिंह और उनके सहयोगी जगवीर ने बताया कि चौका एक आयातकार क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल में गड्ढ़ा खोदा जाता है, जिसमें तीन तरफ मिट्टी की दीवार बनाई जाती है और चौथी तरफ ढलान बनाया जाता है। इसी चौथी तरफ से जब गड्ढ़े में पानी भरता है और ओवरफ्लो होता है तो बाहर निकलने लगता है। शेष पानी अंदर मौजूद रहता है। ओवरफ्लो होकर बाहर निकलने वाले पानी को भरने के लिए तीन तालाब बनाए गए हैं। इनमें एक तालाब का नाम है अन्न सागर, इससे सिंचाई होती है। दूसरे तालाब देव सागर से पीने के पानी की आपूर्ति होती है और तीसरा तालाब फूल सागर है। इससे पशुओं को पीने के लिए पानी छोड़ा जाता है। ये तालाब पक्के बनाए गए हैं। चौका में नौ इंच पानी भार को सहन करने की क्षमता होती है। यह भी ध्यान रखा गया है कि दो चौकों में तीन मीटर की दूरी हो, जिससे पानी का दबाव पाल पर नहीं पड़े और चौकों में पानी ठहरने की किसी तरह की समस्या भी नहीं हो।

चौका सिस्टम में बारिश का पानी जहां गिरता है, वहीं एकत्र हो जाता है। लंबे ढलान को छोटे-छोटे ढलानों में बांटने से पानी बहने की रफ्तार इतनी कम होती है कि जमीन का कटाव नहीं होता है। इससे पानी का बहाव रूककर जमीन में ही भर जाता है। इससे घास, झाड़ियों एवं पेड़-पौधों को उगाने में मदद मिलती है। सूखा पड़ने पर भी यहां पानी की उपलब्धता होती है। जमीन को पक्का नहीं किया जाता है, इस कारण पानी रिचार्ज होता रहता है। पानी की समस्या दूर होने के बाद गांव के 90 फीसद परिवारों ने खेती के साथ ही पशुपालन शुरू किया है। इससे इस गांव में आर्थिक तरक्की भी हुई है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

अनियोजित दोहन से खतरे में बदरी तुलसी का अस्तित्व

चमोली जिले के बामणी गांव में उगी बदरी तुलसी। बदरीनाथ क्षेत्र में तुलसी की यह प्रजाति बहुतायत में पाई जाती है। इसी तुलसी से भगवान बदरीनाथ की सभी पूजाएं संपन्न होती हैं। जागरण

रणजीत सिंह रावत, जोशीमठ (चमोली)

- बदरीनाथ धाम में बदरी तुलसी से ही होती हैं भगवान बदरी विशाल की सभी पूजाएं
- बदरीनाथ क्षेत्र के कई गांवों के लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है बदरी तुलसी
- मान्यता के अनुसार मां लक्ष्मी का प्रतिरूप है बदरी तुलसी, भगवान नारायण को है अतिप्रिय

भू-बैकुंठ बदरीनाथ धाम में पाई जाने वाली ओरिगनम वल्गर प्रजाति की दुर्लभ बदरी तुलसी संकट में है। यह स्थिति इसके अनियोजित दोहन के कारण उत्पन्न हुई है। ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब बदरी तुलसी का बदरीनाथ धाम से अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दरअसल, भगवान बदरी नारायण की नित्य पूजा इसी बदरी तुलसी से होती है। मान्यता है कि बदरीनाथ धाम में मौजूद यह तुलसी मां लक्ष्मी का ही प्रतिरूप है, जो कि भगवान नारायण की अर्द्धांगिनी हैं। यही कारण है बदरी तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दुर्लभ प्रजाति की यह तुलसी सिर्फ बदरीनाथ क्षेत्र में ही उगती है।

बदरीनाथ क्षेत्र में नारायण पर्वत पर मनांग, देवदर्शनी, रडांग बैंड, बामणी गांव, वसुधारा, माणा गांव, नाग-नागिन, इंद्रधारा, चरणपादुका, हनुमानचट्टी, सरो, जोशीमठ आदि स्थानों पर पाई जाने वाली बदरी तुलसी क्षेत्र के लोगों की आजीविका का भी प्रमुख स्रोत है। भगवान बदरी विशाल को अर्पित की जाने वाली पूजा के थाल में बदरी तुलसी की माला अवश्य होती है। यही वजह है कि यात्रा काल में इसकी भारी मांग रहती है। कई बार यात्रा के चरम पर होने पर जब बदरी तुलसी की मालाएं समाप्त हो जाती हैं तो बाहर से मंगाई गई अन्य प्रजाति की तुलसी की मालाएं यहां बेची जाती हैं। हालांकि, परंपरा के अनुसार सिर्फ बदरी तुलसी की माला ही भगवान को चढ़ाई जा सकती है।

बदरीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवनचंद्र उनियाल बताते हैं कि बदरीशपुरी में मां लक्ष्मी ने बदरी तुलसी रूप में भगवान नारायण की तपस्या की थी। इसलिए भगवान को यह अतिप्रिय है और इसके बिना भगवान की कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। लेकिन, जिस हिसाब से इसका अनियोजित दोहन हो रहा है, वह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। उनियाल के अनुसार बदरी तुलसी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है।

वैज्ञानिक ढंग से हो इसका विदोहन : राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग (चमोली) में वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विश्वपति भट्ट कहते हैं कि बदरीनाथ में तुलसी की माला केवल वही लोग बनाएं, जो परंपरा के अनुसार इसके हकदार हैं, तभी इसे बचाया जा सकता है। बकौल भट्ट, 'मैंने वन विभाग को सुझाव दिया है कि बदरीनाथ धाम और हनुमानचट्टी के आसपास 30 से 40 हेक्टेयर क्षेत्र में बदरी तुलसी की संरक्षित खेती की जानी चाहिए। साथ ही इसका विदोहन भी वैज्ञानिक ढंग से होना जरूरी है। अन्यथा हम इस दुर्लभ धरोहर को खो बैठेंगे।'

हर सीजन में बिक जाती हैं 20 लाख की माला : बदरीनाथ क्षेत्र में बदरी तुलसी से 1500 से अधिक लोगों का रोजगार मिलता है। इसके पत्तों से बनी माला धाम में 20 रुपये के हिसाब से बिकती हैं। बदरीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवनचंद्र उनियाल बताते हैं कि एक सीजन में लोग 20 लाख रुपये से ज्यादा की मालाएं बेच देते हैं। खास बात यह कि सूखने के बाद भी बदरी तुलसी की खुशबू बरकरार रहती है। लोग कई रोगों के उपचार, यहां तक कि चाय में भी इसका इस्तेमाल करते हैं।

कार्बन सोखने की क्षमता 12 फीसद अधिक : वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) देहरादून के वैज्ञानिकों ने अपने ओपन टॉप चैंबर में किए गए परीक्षण में पाया कि बदरी तुलसी में सामान्य तुलसी और अन्य पौधों के मुकाबले कार्बन सोखने की क्षमता 12 फीसदी अधिक है। तापमान अधिक बढ़ने पर इसकी क्षमता भी 22 फीसदी तक बढ़ जाती है। इसका पौधा पांच से छह फीट तक लंबा होता है और कैनोपी (छतरी) की शक्ल बना लेता है। इससे यह अधिक कार्बन सोखने में सक्षम होता है।

हर कसौटी पर खरा बदरी तुलसी का पौधा : बदरी तुलसी का इस्तेमाल चर्म रोग, डायरिया, डायबिटीज, घाव, बाल झड़ना, सिर दर्द, इंफ्लुएंजा, फंगल संक्रमण, बुखार, कफ-खांसी, आदि में बेहद फायदेमंद माना गया है। अब तो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की इसकी क्षमता ने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। आस्था हो या फिर विज्ञान, हर कसौटी पर बदरी तुलसी का पौधा शत-प्रतिशत खरा उतरा है, जो लोगों के लिए किसी चमत्कार जैसा ही है।

मप्र के निवासी खुशी खोजने जाएंगे बेंगलुरु और कोयंबटूर

नईदुनिया, भोपाल

- आनंद संस्थान अगस्त में शासकीय कर्मियों के साथ 10 नागरिकों भी भेजेगा

मध्य प्रदेश सरकार ने अब शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के साथ सामान्य नागरिकों को भी खुशी तलाशने की पात्रता दे दी है। राज्य आनंद संस्थान ने अब शासकीय कर्मचारियों के साथ सामान्य नागरिकों को भी हैप्पीनेस शिविर में भाग लेने की सशुल्क अनुमति दी है। संस्थान अगस्त से नागरिकों को खुशी तलाशने ईशा फाउंडेशन बेंगलुरु, कोयंबटूर और पंचगनी भेजेगा।

संस्थान ने आनंद शिविर के जरिये सरकारी कर्मियों को आत्मिक संतोष और खुशी तलाशने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु, ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर और इनिशिएटिव ऑफ चेंज पंचगनी की संस्थाओं से करार किया है। शिविर में 40 अधिकारी-कर्मचारियों को भेजने का प्रावधान है। अब तक कई शिविर आयोजित हो चुके हैं। शिविर में जाने वाले कर्मचारी का व्यय सरकार उठाती है। संस्थान ने इस शिविर में अब दस सामान्य नागरिकों को भी भेजने का निर्णय लिया है। इसमें संबंधित व्यक्ति को आने-जाने का व्यय और संस्थान में चार दिवसीय शिविर का खर्च स्वयं वहन करना होगा। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली हैप्पीनेस ट्रेनिंग एवं आवास-भोजन शुल्क के रूप में प्रति व्यक्ति 20 हजार रुपये खर्च आता है।

मिलेंगे खुश रहने के टिप्स : शिविर में ध्यान-योग, सकारात्मक सोच के साथ जीवन में खुश कैसे रहें, इसके टिप्स दिए जाते हैं। चार दिन तक संबंधित संस्था के विषय विशेषज्ञ इसका औपचारिक प्रशिक्षण भी देते हैं। राज्य आनंद संस्थान द्वारा वेबसाइट पर पंजीयन के जरिये शिविर में जाने वालों की सूची तैयार की जा रही है। इस बार चार अगस्त से प्रशिक्षण शुरू होगा। इनमें पहली बार 30 शासकीय अधिकारी-कर्मचारी और 10 सामान्य नागरिक रहेंगे।

राज्य आनंद संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिलेश अर्गल ने बताया कि आनंद शिविर में शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अन्य लोगों को भेजने का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। शिविर में पहले 40 कर्मचारियों को भेजते थे, अब 30 कर्मचारी और 10 आम नागरिकों को भेजने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अल्पविराम और आनंद शिविर के आयोजन भी जिला एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे।

14 हिम वीरांगनाओं ने फतह की सतोपंथ की 17 हजार फीट ऊंची अनाम चोटी

संवाद सूत्र, जोशीमठ (चमोली)

- चमोली जिले में स्थित 17 हजार फीट ऊंची यह चोटी मानी जाती है तकनीकी रूप से बेहद खतरनाक
- सतोपंथ क्षेत्र में पर्वतारोहण के एडवांस कोर्स के तहत किया हिम वीरांगनाओं ने इस चोटी का आरोहण
- प्रशिक्षण में लेह की रिन चुनी गई सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही, बिहार की प्रिंस कुमारी रही दूसरे स्थान पर

बदरीनाथ धाम के पास सतोपंथ में भारतीय पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान से जुड़ी 14 हिम वीरांगनाओं ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक अनाम चोटी को फतह करने में सफलता हासिल की है। समुद्रतल से 17 हजार फीट ऊंची यह चोटी तकनीकी रूप से बेहद खतरनाक मानी जाती है।

इन महिलाओं को भारतीय पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान औली (चमोली) में बदरीनाथ धाम के सतोपंथ क्षेत्र में पर्वतारोहण का एडवांस कोर्स कराया, जो छह सप्ताह चला। इस दौरान उन्हें रॉक क्लाइंबिंग, स्नो क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट, पर्वतों के खतरे, व्यवहार, भारी बर्फ में योग सहित अन्य कठिन से कठिन प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें हिमालयी खतरों से निपटने के गुर भी सिखाए गए। प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही रही लेह की रिन और बिहार की प्रिंस कुमारी ने बताया कि यहां पर उन्होंने अपने डर पर विजय पाना सीखा। साथ ही तकनीकी रूप से बेहद खतरनाक 17 हजार फीट ऊंची अनाम चोटी भी फतह की। यहां थोड़ी-सी चूक पर हिमस्खलन के साथ बर्फ के क्रेवास में घुसने का डर लगा रहता था। बताया कि इसे वह अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं।

आइटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) के उप सेनानी कमल भारद्वाज ने बताया कि हिम वीरांगनाओं ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। इसे देखते हुए जल्द संस्थान पर्वतारोहण के लिए महिला टीम बनाने जा रहा है। डीआइजी गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रशिक्षण में पहले स्थान पर रही लेह की रिन को सम्मानित भी किया गया।

चमोली के सतोपंथ में 14 हिम वीरांगनाओं ने अनाम चोटी पर फहराया तिरंगा। स्रोत : भारतीय पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान

दूर की परेशानी

हजारीबाग के विष्णुगढ़ में दोहराई गई थ्री इडियट्स की कहानी, अनपढ़ रमेश ने कबाड़ में पड़े स्कूटर के इंजन से बना दिया देसी पावर टिलर, ढाई लीटर पेट्रोल में पांच घंटे कर रहा जुताई

कबाड़ के इंजन से 'देसी इंजीनियर' ने दिखाया कमाल

ललित मिश्रा, विष्णुगढ़ (हजारीबाग)

यह कहानी हजारीबाग जिले के एक युवक की है, जिसके पास इंजीनियरिंग का कौशल और प्रतिभा तो है, लेकिन अपेक्षित डिग्री नहीं। डिग्री के अभाव में कंपनियां उसे ना तो इंजीनियर मानने को तैयार हैं ना ही नौकरी देने को, लेकिन युवक अपनी प्रतिभा गांव और खेतों में ही दिखा रहा है। हम बात कर रहे हैं हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के उच्चघाना गांव निवासी रमेश करमाली की, जो अनपढ़ हैं, लेकिन अलग-अलग समय में अपने तकनीकी कौशल के दम पर चर्चा में आ चुके हैं। इस बार उन्होंने कबाड़ में बेकार पड़े एक स्कूटर के इंजन से पावर टिलर बनाकर अपने खेतों की जुताई की समस्या हल कर ली। रमेश के इस आविष्कार को देख सभी प्रभावित हैं। रमेश पेशे से मैकेनिक हैं और ऑन डिमांड गांव में ही छोटी-मोटी मशीनों की मरम्मत का काम करते हैं।

जुगाड़ का पावर टिलर बनाने वाले रमेश करमाली। जागरण

ऐसे हुई शुरुआत : बताया जाता है कि रमेश के छोटे भाई ने दो भैंस बेच दी तो रमेश को खेती के लिए परेशानी होने लगी। खेती के लिए दूसरों से बैल मांगना पड़ता था। ऐसे में अनपढ़ रमेश ने महज आठ हजार रुपये जुगाड़ कर खेती ही नहीं शुरू की, बल्कि पावर टिलर बनाकर खेती के लिए बैल और भैंसों का झंझट भी दूर कर दिया। यह चमत्कार कबाड़ में फेंके उस स्कूटर के इंजन से हुआ जिसे किसी ने तीन हजार रुपये में कबाड़ी को बेच दिया था। रमेश ने इसमें थोड़ा बदलाव किया और फिर घर में टिलर तैयार कर खेतों की जुताई शुरू कर दी।

10 गुणा कम हो गया जुताई का खर्च : रमेश का पावर टिलर दस गुणा कम दर पर खेतों की जुताई कर रहा है। ढाई लीटर पेट्रोल में दस कट्ठा जमीन अर्थात पांच घंटे की भरपूर जुताई इस मशीन से की जा सकती है। रमेश की इस मशीन से पूरे गांव के लोग प्रभावित हैं।

गड़बड़ी ठीक करने पर बजाज कंपनी ने किया था पुरस्कृत : रमेश करमाली तीन भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। तीन साल की उम्र में वह पिता के साथ पुणे चले गए। पिता मजदूरी करते थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में 1995 में बजाज शोरूम में उन्हें काम पर लगा दिया। 2005-06 में उन्हें पुणे में ही बजाज कंपनी में प्रशिक्षण पाने का मौका मिला। वहां बजाज के दोपहिया वाहन की सेल्फ की गड़बड़ी ठीक करने पर उनको पुरस्कृत किया गया। नौकरी का भी ऑफर हुआ, लेकिन पढ़े-लिखे नहीं होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। इसके बाद वह वापस अपना गांव आ गए और ऑन कॉल मोटरसाइकिल रिपेयिरंग का काम करने लगे।

खेती की चिंता और पैसे के अभाव ने सुझाया उपाय : छोटे भाई द्वारा खेती के लिए दो भैंस बेच देने पर रमेश परेशान थे। इसी उधेड़बुन में उन्हें पोर्टेबल पावर टिलर बनाने की एक तरकीब आई। इसके लिए सबसे पहले 20 इंच बाई 41 इंच का चेचिस बनाया। अब इंजन और हैंडल की जरूरत पूरी करने के लिए कबाड़ में तीन हजार रुपये में मिले स्कूटर का इंजन लगा दिया। गेयर बॉक्स, हैंडल और दोनों चक्कों को निकाल कर बनाए उस चेचिस में फिट कर दिया। बाद में उसे स्टार्ट कर चला कर देखने पर उनके मुताबिक पावर टिलर सही निकला।

रमेश करमाली द्वारा बनाया गया पावर टिलर। जागरण

मौसम विशेष

पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली के ज्यादातर भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। बादल और तेज हवाओं के कारण तापमान में काफी गिरावट होगी। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के दक्षिण भागों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। राजस्थान का मौसम मुख्यतः गर्म व शुष्क बना रहेगा।

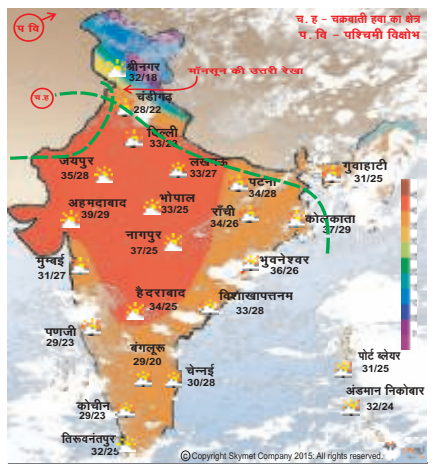

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/26/व	अहमदाबाद	40/28/व
कोलकाता	36/28/व	बड़ौदा	38/27/आंवा
चेन्नई	36/27/व	नागपुर	38/25/आंवा
हैदराबाद	35/24/व	इन्दौर	35/25/व
बंगलूरू	29/20/आंवा	रांची	37/26/व
त्रिवेन्द्रम	30/24/व	पटना	39/28/आंवा
गुवाहाटी	30/25/आंवा	जमशेदपुर	37/26/आंवा
गंगटोक	18/11/व	पुणे	24/22/व

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
मंगलवार 16 जुलाई 2019
14
www.jagran.com

इंसान को चांद पर उतारने वाला अपोलो 11 यान हुआ रवाना

1969 में आज ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान अपोलो 11 ने नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन को लेकर चांद के लिए उड़ान भरी थी। चार दिन बाद यानी 20 जुलाई को ये चांद की सतह पर उतरा। अपोलो 11 ने पहली बार मानव को अंतरिक्ष में उतारा था।

पहला पार्किंग मीटर स्थापित हुआ

1935 में आज ही अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में दुनिया का पहला पार्किंग मीटर स्थापित हुआ था। पार्किंग मीटर एक उपकरण है, जिसका उपयोग सीमित समय के लिए किसी विशेष स्थान पर वाहन पार्क करने के बदले धन एकत्र करने के लिए किया जाता है।

स्पीड और ड्रिबिलिंग के महारथी रहे हैं धनराज पिल्लै

धनराज पिल्लै का जन्म 1968 में आज ही महाराष्ट्र में हुआ था। 1989 में भारतीय हॉकी टीम में शामिल हुए। धनराज इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो चार ओलंपिक (1992, 1996, 2000, 2004), चार वर्ल्ड कप (1990, 1994, 1998, 2002), चार चैंपियंस ट्रॉफी (1995, 1996, 2002, 2003) और चार एशियन गेम्स (1990, 1994, 1998, 2002) खेल चुके हैं। अपनी तेजी और गेंद के साथ जादू करने में माहिर वह बैंकॉक एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। खेल रत्न और पद्मश्री से सम्मानित हैं।

इधर-उधर की

मुंह पर टेप लगाकर सोती है ये गायिका

जकार्ता, एजेंसी : इंडोनेशिया की मशहूर गायिका एंडेन मुंह पर टेप लगाकर सोती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम में तस्वीर डालकर इस बात की स्वीकारोक्ति की। अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि उनका परिवार पिछले तीन महीने से बुटेको की प्रैक्टिस कर रहा है। बुटेको एक प्रक्रिया है, जिसमें सांस लेने के तरीके शामिल हैं। इसमें से एक तरीका है मुंह पर टेप लगाकर नाक से सांस लेना। एंडेन ने दावा किया है कि बुटेको करने से उन्हें अच्छी नींद आती है। बुटेको तकनीक का आविष्कार 1950 में सोवियत डॉक्टर कोंस्टनटिन पाव्लोविक बुटेको ने किया था। उनका मानना था कि इस तकनीक को अपनाने से सांस संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बुटेको से मधुमेह से लेकर थकान, एकाग्र न हो पाने और अवसाद जैसी बीमारियों में सुधार लाने का दावा किया गया है। हालांकि कई डॉक्टरों ने बच्चों के मुंह पर टेप लगाने को खतरनाक बताया है।

शोध अनुसंधान

रोजाना 300 कैलोरी की कमी लाने से सुरक्षित रहेगा हृदय

अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपका वजन थोड़ा ज्यादा है या आप स्वस्थ हैं और आपको कैलोरी में कटौती करने की जरूरत नहीं है, तो यह सोच आपके दिल की सेहत के लिए भारी पड़ सकती है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि स्वस्थ होने के बावजूद अगर वयस्क लोग रोजाना करीब 300 कैलोरी की कटौती करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के स्तर को और भी बेहतर किया जा सकता है। लेंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, यह निष्कर्ष शोधकर्ताओं की उस सोच को लेकर किए गए परीक्षण के आधार पर निकाला गया है कि सिर्फ वजन घटाने से इस तरह का सुधार नहीं हो सकता। प्रमुख शोधकर्ता विलियम ई क्रूज ने कहा, 'कैलोरी संयम को लेकर कुछ चीजें हैं। कुछ ऐसा तंत्र है, जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं।' -एएनआइ

पूरी तरह रोगाणु मुक्त नहीं हो पाते अस्पताल के उपकरण

भारतवंशी समेत वैज्ञानिकों के एक दल ने पाया कि अस्पताल में सर्जन द्वारा पहले जाने वाले गाउन और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण पूरी तरह रोगाणु मुक्त नहीं हो पाते। इन उपकरणों और गाउन को जिस तरह रोगाणु मुक्त करने की सलाह दी जाती है, उन तरीकों को अपनाए जाने के बावजूद वे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल नामक बैक्टीरिया की चपेट में रहते हैं। ब्रिटेन की प्लायमाउथ यूनिवर्सिटी की लेक्चरर टीना जोशी ने कहा, 'उपकरणों को कीटाणु मुक्त किए जाने के बावजूद यह बैक्टीरिया दोबारा पैदा हो जाता है। इससे यह जाहिर होता है कि यह बैक्टीरिया प्रतिरोधी बनता जा रहा है और हमें इस बात पर दोबारा विचार करने की जरूरत है कि हम किस तरह उपकरणों को रोगाणु मुक्त करते हैं।' क्लीनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यू जर्नल में छपे अध्ययन के अनुसार, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बैक्टीरिया से अकेले अमेरिका में ही हर साल करीब पांच लाख लोग पीड़ित होते हैं। -प्रेट्र

नई खोज ▶ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले खाद्य संकट से निपटने में मिलेगी मदद

जेनेटिक बदलाव से बढ़ेगी पैदावार

अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पौधों को ज्यादा समय तक जीवित रखने में पाई सफलता होगी ज्यादा पैदावर

अमेरिका के वैज्ञानिकों ने विकसित की अनाज उत्पादन के लिए पौधों की नई खेप। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन पर भविष्य में बड़ा व्यापक असर डालने वाला है। विश्व भर के वैज्ञानिक जहां एक ओर इस परिवर्तन में कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वहीं इससे निपटने के लिए नए तरीके भी ईजाद कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने चिंता जताई थी कि जलवायु परिवर्तन से भविष्य में अनाज के उत्पादन में कमी आएगी और खाद्य संकट उत्पन्न होगा।

अब वैज्ञानिकों ने इस संकट से बचने के लिए एक बड़ी खोज की है। उन्होंने पौधे के सूखने के समय को और बढ़ाने में मदद हासिल की है। इससे पौधों का जीवन बढ़ाया जा सकेगा।

प्लांट सेल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया कि जीवों और पौधों में एक विशेष प्रकार का आनुवंशिक गुण होता है, जिसमें हम उन कोशिकाओं को खत्म कर देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है। पौधे भी अपनी कोशिकाओं को खत्म कर देते हैं।

अमेरिका की क्लेमसन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर राजन सेखों ने बताया कि मौसम के अनुसार पेड़ों का रंग बदल जाता है। जब मौसम अनुकूल नहीं होता तो पेड़ अपनी पत्तियां भी गिरा देते हैं। यह एक प्रकार से ऊर्जा की अर्थव्यवस्था के बारे में है। वह अपने तने में इतनी उर्जा संग्रहीत रखते हैं कि अगले वसंत में नई पत्तियों को जन्म दे सकें। अब वैज्ञानिकों ने अनाज वाले पौधों के जीन में एडिटिंग कर नए प्रजाति विकसित की है।

इस तरह बढ़ेगा उत्पादन

वैज्ञानिकों ने बताया कि अनाजों (मक्का, चावल और गेहूं) की नई प्रजाति 'स्टे ग्रीन' विकसित की गई है। ये अपने नाम के ही अनुरूप होते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इससे अनाज का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है।

क्या होती है प्रक्रिया

वैज्ञानिकों ने बताया पौधों में कोशिका के खत्म होने की प्रक्रिया एक जटिल लक्षण है। यह आंतरिक और बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। यह प्रक्रिया एक साथ काम करने वाले कई जीनों के माध्यम से होती है। वैज्ञानिकों ने पौधों में जेनेटिक बदलाव करके उनके कोशिका खत्म करने के समय को बढ़ा दिया है। इससे पौधे पर्यावरण की जटिलताओं से निपटने में ज्यादा सक्षम होते हैं।

डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म खोजे

ह्यूस्टन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने 8 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर विचरण करने वाले डक-बिल्ड डायनासोर (बतख की चोंच जैसे जबड़े वाले) की नई प्रजाति की खोज की है।

सिस्टेमैटिक पेलियोन्टोलॉजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में अमेरिका के बिग बेंड नेशनल पार्क से मिली एक डक-बिल्ड डायनासोर की खोपड़ी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है, इसमें बताया गया कि एक्वलिनहिनस पैलिमेंट्स नाम की नई प्रजाति की खोज की गई है। बताया गया कि इस नई प्रजाति के डायनासोर की नाक चोंच की तरह और नीचे के जबड़े काफी चौड़े थे। पिछली सदी के आठवें दशक में अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टाम लेहमन ने इस प्रजाति के डायनासोर के कुछ जीवाश्म प्राप्त किए थे। 1990 में उन जीवाश्मों का अध्ययन करने के बाद यह बताया गया था कि यह जीवाश्म डक-बिल्ड डायनासोर की एक प्रजाति ग्रिपोसॉरस की प्रजाति के हैं। हालांकि, वर्तमान में किए गए शोध के बाद से पुराने अध्ययनों को गलत माना गया है। वैज्ञानिकों का कहना है। जीवाश्मों की विशिष्टता देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि ये ग्रिपोसॉरस के नहीं हैं। ये उससे भी भिन्न हैं और निश्चित ही किसी नई प्रजाति के हैं। स्पेन की मिकेल क्रूसाफॉट कैटलन इंस्टीट्यूट इन पैलेन्टोलॉजी के अल्बर्ट प्रीतो मार्केज ने बताया कि पहले इस तरह की नई प्रजाति की केवल कल्पना ही की जाती थी, लेकिन अब मिलते सुबूत इस कल्पना को हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। डक-बिल्ड डायनासोर को हेड्रोसारिड्स भी कहा जाता है। आठ करोड़ साल पहले यह विशेष प्रकार का डायनासोर धरती पर निवास करता था। वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह डायनासोर उत्तरी मेक्सिको के पास दलदल के आसपास निवास करता था। जहां वर्तमान में चिहुआहुआन रेगिस्तान है।

अध्ययन

- वैज्ञानिकों का दावा है कि यह नई प्रजाति मेक्सिको के उत्तर में दलदलों के पास निवास करती होगी, वर्तमान में यहां रेगिस्तान है
- जबड़े का विशेष स्वरूप ही इसे और डायनासोर से अलग करता है

1980 में पहली बार इस प्रजाति के खोजे गए थे जीवाश्म। प्रतीकात्मक

अलग प्रकार की जबड़े हैं विशेषता

वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई प्रजाति के डायनासोर के जबड़े की भिन्नता ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि आम तौर पर डक-बिल्ड डायनासोरों में किसी के जबड़े नुकीले तो किसी की चौड़े होते थे। उन्होंने बताया कि नई प्रजाति के अवशेषों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसके जबड़े फसल काटने के औजार की तरह होगें, जिससे यह छोटे मोटे पौधों को काटकर आसानी से आहार बना सकता था। इसका ऊपर का जबड़ा यू आकार का तो नीचे का डब्ल्यू आकार है।

समय से पहले पैदा हुए बच्चों में रहती है उदासी

लंदन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने बताया है कि ऐसे युवक जो समय से पहले पैदा होते हैं बड़े होने पर उनका जीवन उन लोगों की तुलना में कम सुखमय होता है जो समय पर पैदा होते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने शोध से बताया है कि ऐसे लोगों के जीवन में उदासी रहती है।

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक के शोधकर्ताओं ने 44 लाख वयस्कों पर इसका अध्ययन किया और पाया कि ऐसे लोग जिनका जन्म समय से पूर्व (37 सप्ताह में) हुआ है। उनमें सामान्य की तुलना में 28 फीसद तक खुशी की कमी रहती है और 22 फीसद तक मां-बाप बनने की संभावना भी कम होती है। यह अध्ययन जेएएमए नेटवर्क ओपन जर्नल में प्रकाशित हुआ है, इसमें बताया गया कि वे लोग जिनका जन्म समय से पूर्व होता है वे अपने ही साथियों के तुलना में लोगों से रिश्ते कम बना पाते हैं। लोगों को अपनी ओर प्रभावित भी कम कर पाते हैं और उनका वैवाहिक जीवन भी ज्यादा सुखमय नहीं रहता है। वहीं जो बहुत ही ज्यादा समय से पहले पैदा होते हैं उनमें 3.2 गुना कम सुखी रहने के अवसर होते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि समाज में लोगों से रिश्ते बनाना खुशी को बढ़ाता है और यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक है। बताया कि ऐसे वयस्क आमतौर पर डरपोक और समाज में भूमिका निभाने से पीछे हटते हैं।

गुलदार के स्वभाव में बदलाव समूह में करने लगे शिकार

केदार दत्त, देहरादून

- प्रसिद्ध शिकारी लखपत सिंह रावत के अध्ययन में हुआ इस बात का राजफाश
- अल्मोड़ा व बागेश्वर में गुलदारों के समूह में रहकर शिकार के आए मामले

चमोली निवासी शिकारी लखपत सिंह। लखपत अब तक 53 नरभक्षी गुलदारों को मार चुके हैं। जागरण

वन्यजीवों विशेषकर गुलदारों के खौफ से त्रस्त उत्तराखंड में अब इनके स्वभाव को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। प्रसिद्ध शिकारी लखपत सिंह रावत के अध्ययन पर गौर करें तो गुलदार अब समूह में रहकर शिकार भी करने लगे हैं। अल्मोड़ा के बाद बागेश्वर में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इस बदलाव को अस्तित्व की लड़ाई में खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की गुलदारों की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है।

अमूमन, नर गुलदार अकेला रहता है और अकेले ही शिकार करता है। अलबत्ता, मादा गुलदार अपने बच्चों को ढाई-तीन साल तक अपने साथ रखती है और इसी दौरान उन्हें शिकार के तरीके सिखाती है। यह अवधारणा अब दम तोड़ती नजर आती है। प्रसिद्ध शिकारी लखपत सिंह रावत का अध्ययन तो यही कहता है। प्रदेश में 2002 अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 53 आदमखोर गुलदारों को ढेर कर जनसामान्य को इनके खौफ से मुक्ति दिलाने वाले लखपत ने इस अवधि में इनके स्वभाव को लेकर भी अध्ययन किया।

गैरसैंण (चमोली) में प्रभारी उप शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत लखपत सिंह बताते कि अब जिंदा रहने के लिए गुलदार भी समूह में रहकर शिकार करने लगे हैं। पिछले साल अक्टूबर में बागेश्वर में समूह में रह रहे चार गुलदारों की सक्रियता ने सांसें अटका दी थीं। इसकी तस्वीरें वहां सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थीं। इनमें से तीन गुलदारों को मार गिराया गया था, जबकि एक को पकड़ा गया।

शिकारी लखपत सिंह के अनुसार इस सबको देखते हुए गहन अध्ययन कर ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। उनके मुताबिक वह इस संबंध में वन विभाग के अफसरों को भी अवगत करा चुके हैं।

वन विशेषज्ञ सोचते हैं अलग : हालांकि, वन्यजीव विशेषज्ञों की राय इससे जुदा है। मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव आरके मिश्र कहते हैं कि गुलदारों का समूह में रहकर शिकार करना असंभव सी बात है। वह बताते हैं कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान तो नर-मादा साथ दिखते हैं, मगर इसके बाद नर अकेले ही रहता है। यही नहीं, मादा बच्चों को पालती है और ढाई- तीन साल तक उन्हें साथ रहकर शिकार करना सिखाती है। हो सकता है कि बागेश्वर और अल्मोड़ा में ऐसी स्थिति रही हो।

इसलिए कर रहे आबादी की ओर रुख

- गुलदारों की संख्या में बढ़ोतरी
- जंगलों के कटान से वासस्थल में कमी
- जंगलों में भोजन का अभाव
- पलायन के चलते खाली खेतों में उगी झाड़ियां बन रही बसेरा
- गांवों के नजदीक मिल रहा भोजन

गुलदारों ने उड़ाई है नींद : उत्तराखंड में मानव और गुलदारों के बीच संघर्ष चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है। राज्य में वन्यजीवों के हमलों में 80 फीसद घटनाएं गुलदारों की हैं। गुलदारों के सॉफ्ट टारगेट बच्चे बन रहे हैं, जिससे हर साल औसतन वह 24 बच्चों को निवाला बना रहे हैं।

अपनाने होंगे बचाव के तरीके : शिकारी लखपत सिंह कहते हैं कि गुलदारों को नरभक्षी घोषित कर मार गिराना समस्या का हल नहीं है। इससे निबटने के लिए हमें बचाव के तरीके अपनाने होंगे। वह कहते हैं कि खेतों में कार्य करते वक्त एक व्यक्ति चारों तरफ निगरानी में रहे। वह बताते हैं कि अगर गुलदार पर नजर है तो वह हमला नहीं करता। इससे बचाव के मद्देनजर गुलदार को भ्रमित करने के लिए सिर पर मनुष्य के चेहरे का मुखौटा पीछे की ओर लगाया जा सकता है।

आतिशबाजी का खूबसूरत नजारा

फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेसल दिवस समारोह का आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया। यह यहां का प्रमुख समारोह है। वर्ष 2006 में सीक्रेट इम कोर द्वारा प्रारंभ इस समारोह में सैन्य परेड और सैन्य टैटू शो मुख्य आकर्षण हैं। समारोह में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो के अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल और यूरोप के कई राष्ट्र प्रमुख शामिल रहे थे। समापन पर दिलकश आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया। रायटर

दावत के लिए प्रतिस्पर्द्धा

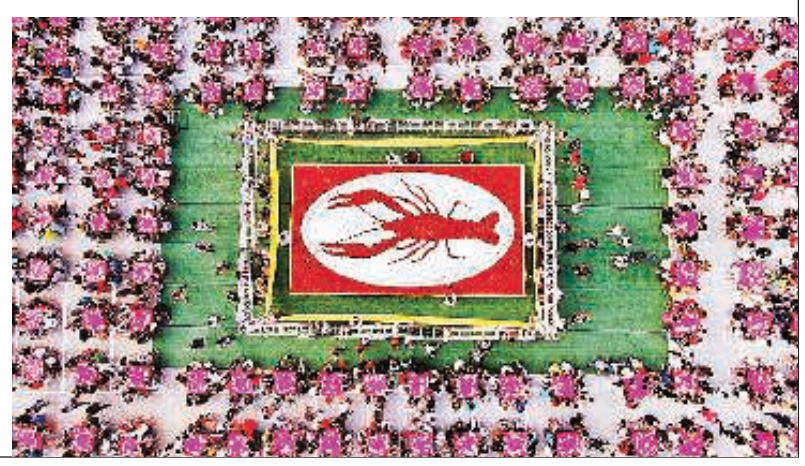

चीन के हेनान प्रांत के लुओयांग शहर में प्रतिवर्ष क्रेफिश की शानदार दावत में शामिल होने के लिए लोगों में जबरदस्त प्रतिस्पर्द्धा होती है। हजारों प्रतिभागियों में से कुछ सौ लोगों को ही टेबल पर बैठने का मौका मिल पाता है। एक टन वजन की क्रेफिश का मसालों से शानदार व्यंजन तैयार किया जाता है। यह चीन का सबसे पसंदीदा व्यंजन है। एजेंसी

स्क्रीन शॉट

अनुष्का लाएंगी वेब शो 'माई'

वेबशोज बनाने वाली कंपनी नेटफ्लिक्स अगले एक साल में पांच नए शो लाने की तैयारी में है। इनमें अनुष्का शर्मा की कंपनी द्वारा निर्मित शो 'माई' भी होगा। इस शो में 47 वर्षीय एक महिला शील की कहानी होगी। व्यक्तिगत त्रासदी के बाद वह खुद को अचानक हिंसा और ताकत के भंवर में पाती है। उससे उसकी दुनिया कैसे बदल जाती है, शो में दिखाया जाएगा। इस शो का लेखन अतुल मोंगिया, तमाल सेन, अमिता व्यास और सुदीप शर्मा ने मिलकर किया है। इसके अलावा 'बॉम्बे बेगम्स' को अलंकृता श्रीवास्तव ने लिखा और निर्देशित किया है। यह समकालीन भारत में सेट पांच महिलाओं की कहानी होगी। अलंकृता के मुताबिक, 'बॉम्बे बेगम' के जरिए शहरों में रहने वाली महिलाओं की कहानी कहने का प्रयास किया गया है। इस कड़ी में शाह रुख खान की कंपनी रेड चिली में बना एक्शन जॉम्बी ड्रामा 'बेताल' आएगा। यह नेटफ्लिक्स पर शाह रुख की कंपनी का दूसरा शो होगा। वह जल्द ही इमरान हाशमी अभिनीत 'ब्लड ऑफ बार्ड' नामक शो भी लाने की तैयारी में हैं। 'मेस्सी' मुंबई में स्टैंडअप कॉमेडियन बेनी की कहानी होगी, जो कॉमेडी में करियर बनाने और जीवन में संतुलन साधने में लगी है। इसके अलावा, वह अभिनेत्री नीना गुप्ता की बेटी मसाबा की जिंदगी पर 'मसाबा मसाबा' नामक शो लेकर आ रहा है। खास बात यह है कि उसमें मसाबा और नीना खुद अभिनय करती दिखेंगी। इसका निर्देशन सोनम नायर करेंगी।

धर्मेंद्र सिखा रहे हैं भैंस के बच्चे को दूध पीना....!

ग्लैमर की दुनिया से दूर इन दिनों धर्मेंद्र ग्रामीण जीवन का आनंद ले रहे हैं। पंजाब में अपने घर पर वह कभी अपने बगीचे में पेड़-पौधे लगाते नजर आते हैं, तो कभी गाय-भैंसों की देखरेख में व्यस्त रहते हैं। इन सबकी जानकारी वह अपने सोशल मीडिया पर देते रहते हैं। अब उन्होंने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह भैंस के बच्चे को दूध पीना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, 'मेरी भैंस का पहला बच्चा है। न मां जानती है कैसे दूध पिलाना है, न बच्चा जानता है कि कैसे दूध पीना है। मैं दोनों को एक-दूसरे के साथ सहज बनाऊंगा।' वीडियो में धर्मेंद्र भैंस के बच्चे को मां का दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओर वह बछड़े को हिदायत दे रहे हैं- दूध पीना सीखो। वहीं दूसरी ओर भैंस से कह रहे हैं- दूध पिलाओ। धर्मेंद्र के इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद यूजर्स ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। एक यूजर ने धर्मेंद्र से एक अलग हटकर सवाल पूछ दिया। दरअसल, पिछले दिनों संसद परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत हेमा मालिनी ने भी झाड़ू लगाई थी। एक यूजर ने लिखा, 'सर, मैडम (हेमा मालिनी) ने कभी झाड़ू उठाई है क्या?' जवाब में धर्मेंद्र ने लिखा, 'हां, फिल्म में। मुझे भी अनाड़ी लग रही थी। मैंने बचपन में अपनी मां का हाथ बंटाया है। मैं झाड़ू लगाने में माहिर था। मुझे साफ-सफाई पसंद है।'

...इसलिए क्रिकेट से नफरत करते हैं आरव

अभिनेता अक्षय कुमार क्रिकेट के फैन हैं, लेकिन उनके बेटे आरव को यह खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी वजह बड़ी मजेदार है। वह यह है कि पापा अक्षय कुमार बहुत ज्यादा क्रिकेट देखते हैं। इसलिए आरव को इस खेल से नफरत हो गई है। अक्षय कहते हैं, 'मेरे बेटे को क्रिकेट पसंद नहीं, लेकिन बेटी नितारा को पसंद है। बेटी महज 6 साल की है, लेकिन क्रिकेट की शौकीन है। मेरे बेटे को क्रिकेट से इसलिए नफरत है, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा देखता हूं।' अक्षय कहते हैं, 'मैं अपने स्कूल में हमेशा क्रिकेट खेलता था। लोगों का चयन बैटिंग या बॉलिंग की वजह से होता था, लेकिन मेरा चयन फील्डिंग स्किल की वजह से होता था। लोग कहते थे यह लड़का भागेगा और बाउंड्री पर बॉल को रोकेगा।'

लेखिका बनीं रिचा चड्ढा, पूरी की अपनी किताब

इंडस्ट्री में कई एक्टर्स हैं, जिन्होंने अपने जीवन अनुभवों को किताबों में समेटा है। ऋषि कपूर, करण जौहर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे अभिनेताओं ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो शिल्पा शेट्टी, ट्विंकल खन्ना जैसी अभिनेत्रियों ने अलग विषयों पर किताबें लिखी हैं। रिचा चड्ढा भी अब इस फेहरिस्त का हिस्सा बन गई हैं। रिचा ने भी अपने अनुभवों को किताब में समेटा है। उनकी यह किताब पूरी हो चुकी है, जो बहुत जल्द प्रकाशित होगी। हालांकि रिचा के लिए किताब लिखने का यह सफर आसान नहीं था। एक तरफ वह अपनी फिल्मों में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक शॉर्ट फिल्म की निर्माता और निर्देशिक भी बन गई हैं। उनकी फिल्म 'शकीला' की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 'पंगा' और 'सेक्शन 375 : मर्जी या जबरदस्ती' की शूटिंग अब भी चल रही है। ऐसे में सेट पर खाली समय के दौरान रिचा चड्ढा ने किताब लिखी है। किताब में कई विषय शामिल होंगे, जो उनके कैमरे के सामने और पीछे की कहानी बयां करेंगे। पिछले एक साल से रिचा इस किताब पर काम कर रही थीं। यह सफर रिचा के लिए काफी भावनात्मक रहा है, जिसने कई पुरानी बातों को दोबारा रिचा के सामने ला खड़ा किया है।

अद्भुत

केदारनाथ मंदिर और निकटवर्ती चौराबाड़ी ग्लेशियर में रिकॉर्ड स्तर पर हुई बर्फबारी, मंदिर परिसर में 40 फीट, ग्लेशियर में 55 फीट तक गिरी बर्फ, 15 फीट था औसत

ग्लोबल वार्मिंग के दौर में पहाड़ों में रिकॉर्ड बर्फबारी

सुमन सेमवाल, देहरादून

आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने का जतन कर रहा है और ग्लेशियरों की सेहत की चिंता निरंतर सता रही है। ऐसे में उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित केदारनाथ मंदिर और इसके निकटवर्ती चौराबाड़ी ग्लेशियर में रिकॉर्ड बर्फबारी होने से वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों की ओर से जुटाए गए बर्फबारी के ताजा आंकड़ों की बात करें तो 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर में 40 फीट बर्फबारी हो गई तो चौराबाड़ी ग्लेशियर क्षेत्र में 4,270 मीटर ऊंचाई पर बने एडवांस बेस कैंप पर यह आंकड़ा 50 फीट तक जा पहुंचा।

वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ हिमनद विशेषज्ञ डॉ. डीपी डोभाल के मुताबिक, बर्फबारी के आंकड़े एकत्रित करने के लिए हाल ही में रुद्रप्रयाग के चौराबाड़ी ग्लेशियर का रुख किया गया था। यहां पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए एडवांस बेस कैंप (एबीसी) पर करीब 17 लाख रुपये के दो ऑटो वेदर स्टेशन लगाए गए थे। इसके साथ ही इसके नीचे 3,910 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप में रहने के लिए प्री-फैब्रिकेटेड हट बनाई गई थी।

रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी ग्लेशियर में इस वर्ष हुई भारी बर्फबारी से वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान का ऑटो वेदर स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गया। जागरण

इस दफा जनवरी से लेकर अप्रैल तक इतनी अधिक बर्फ पड़ी कि बर्फ के दबाव से जहां हट पूरी तरह पिचक गई। वहीं, ऑटो वेदर स्टेशन भी क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में इनसे त्वरित डाटा निकालने का काम नहीं हो पाया। इसकी जगह केदारनाथ मंदिर क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रही वुडस्टॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी से बर्फबारी के आंकड़े लिए गए। साथ ही ग्लेशियर क्षेत्र में अब तक मौजूद बर्फ के आधार पर बर्फबारी का विश्लेषण किया गया। पता चला कि केदारनाथ मंदिर में सीजन में (जनवरी से अप्रैल) 40 फीट बर्फ पड़ी और चौराबाड़ी ग्लेशियर में यह आंकड़ा करीब 50 फीट पाया गया।

डॉ. डोभाल ने बताया कि चौराबाड़ी ग्लेशियर की मॉनिटरिंग 2003 से की जा रही है। इसके बाद से पिछले साल तक यहां औसतन 15 फीट बर्फ पड़ रही है। 2013 की केदारनाथ आपदा में भी बर्फबारी का आंकड़ा इसके आसपास ही रहा। तब जून माह में बेस कैंप में दो फीट बर्फ जमा थी और इस दफा छह फीट बर्फ शेष है।

एक हजार फीट नीचे आई स्नो लाइन : केदारनाथ क्षेत्र में स्नो लाइन पांच हजार मीटर पर रहती है। इस दफा रिकॉर्ड स्तर पर बर्फबारी होने के चलते यह चार हजार मीटर पर आ गई है। यानी स्नो लाइन का दायरा एक हजार मीटर नीचे आ गया। हालांकि, अभी यह बर्फ कच्ची है और सितंबर-अक्टूबर में ही स्पष्ट हो पाएगा कि बर्फबारी से स्नोलाइन कितनी नीचे आई है।

इस सीजन नहीं पिघलेगा ग्लेशियर : वाडिया संस्थान के हिमनद विशेषज्ञ डॉ. डोभाल का मानना है कि इस साल ग्लेशियर की बर्फ पिघलने की उम्मीद कम ही है और जो ग्लेशियर के ऊपर अतिरिक्त बर्फ जमी है, वही पिघलेगी। ऐसे में अगर अगले सीजन में भी इसी तरह बर्फबारी हुई तो ग्लेशियर की सेहत और बेहतर हो जाएगी।